सूर्योदय 5:58 सूर्यास्त 6:44

आज का तापमान

शिमला	16.8 न्यू	23.6 अधि
धर्मशाला	21.8 न्यू	29.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	76,944
निफ्टी	24,055

सोना 1,55,000 चांदी 2,35,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 17 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 128, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

गोवा-दिल्ली फ्लाइट के इंजन में आई खराबी

एजेंसी, नई दिल्ली। गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2102 को उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद एक इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। इसके बाद विमान को वापस मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (मोपा) लाया गया। फ्लाइट ने सुबह 9:16 बजे उड़ान भरी थी और 9:30 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। फ्लाइटराडार24 के डेटा के मुताबिक, वापस मुड़ते समय विमान करीब 14 हजार फुट की ऊंचाई पर था। विमान में 229 यात्री सवार थे। इंडिगो ने बताया कि विमान की फिलहाल मेंटेनेंस जांच की जा रही है। सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही विमान दोबारा उड़ान भरेगा। कंपनी ने कहा कि असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों को खाने-पीने की चीजें उपलब्ध कराई गईं और उन्हें समय-समय पर जानकारी दी गई। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।

एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के लोन माफी वाले आदेश पर लगाई रोक

एजेंसी, नई दिल्ली। एनसीएलटी की 5-सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी है।

25 अगस्त के आदेश में उनके 22,000 करोड़ से ज्यादा के बकाए कर्ज के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ चुकाने के प्लान को मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने सुभाष चंद्रा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। यह एनसीएलटी के इतिहास में पहली बार है, जब पांच सदस्यीय बेंच बनाई गई है। बेंच की अध्यक्षता प्रेसिडेंट जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल कर रहे हैं। इसके बाकी सदस्य बचु वेंकट बालाराम दास, महेंद्र खंडेलवाल, अतुल चतुर्वेदी और रविंद्र चतुर्वेदी हैं।

चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी, गृह मंत्रालय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में गंभीर चिंता पैदा हो गई है।

मंत्रालय को मिले एक हस्ताक्षरविहीन संचार में दो मोबाइल नंबरों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री को कथित तौर पर 'कट्टर आतंकवादी' द्वारा जल्द मार दिए जाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त निजी सचिव आलोक कुमार सिंह ने 1 सितंबर को केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार को पत्र भेजा है। पत्र में पूरे मामले की तत्काल और गहन जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम फैसला : नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुई सभी एफआईआर रद्द

नई एफआईआर भी दर्ज नहीं होंगी; सीजेपी ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने साफ किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा। यह आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च वापस ले लिया। संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार के आश्वासन और कोर्ट के फैसले के बाद यह फैसला

◆ कोर्ट बोला- यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत लिया

लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली पुलिस के अंतरिम आवेदन पर सुनाया। इस आवेदन में सरकार ने कहा था कि 25 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी 13 एफआईआर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। यानी इन मामलों में पुलिस अब कार्रवाई जारी रखने के बजाय उन्हें खत्म करना चाहती है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द करने का फैसला सिर्फ इसी मामले के खास तथ्यों और हालात को देखकर लिया गया है, इसलिए इसे दूसरे मामलों के लिए उदाहरण और बाध्यकारी फैसला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल इस शर्त पर किया जा रहा है कि दोनों पक्ष कोर्ट के सामने हुए समझौते का पूरी तरह पालन करेंगे।

अभिजीत दीपके ने कहा यह फैसला छात्रों की जीत

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'अगस्त के शुरूआत में सरकार के डेलिगेशन ने हमसे बात करना बंद कर दिया था, फिर हमें लगा कि ये विश्वासघात करना चाहते हैं, इसलिए हम 5 सितंबर को मार्च निकालेंगे का फैसला किया। आज कोर्ट में सुनवाई हुई। पूरे देश में सारे एफआईआर को रद्दकर दिया है। यह ऐतिहासिक पल है।' अभिजीत दीपके ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला छात्रों की जीत है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ चल रहे सभी अन्यायपूर्ण मुकदमों को खारिज कर दिया है। हमारी मांगें सुनी गई हैं और अब किसी भी छात्र को आगे ऐसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद।'

आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को करना होगा ध्वस्त : मोदी

एजेंसी, बिश्केक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और एकजुट कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ व आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने वाले पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती और जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने एससीओ के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित 26वें शिखर सम्मेलन में कहा कि पिछले 25 वर्षों में संगठन ने यूरेशिया के विशाल भूभाग में संवाद और सहयोग की मजबूत परंपरा विकसित की है तथा मानवता के विकास और अपने लोगों की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब अगले 25 वर्षों में इस सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना एससीओ का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जब दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है।

एससीओ अब दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन : पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शुरुआत कुछ देशों के छोटे संगठन के तौर पर हुई थी, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है। पुतिन के मुताबिक, एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की करीब आधी आबादी रहती है और ये देश दुनिया की कुल जीडीपी के करीब एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जीएसटी कलेक्शन 14.8% बढ़कर दो लाख करोड़ पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। देश का जीएसटी राजस्व संग्रह अगस्त में सालाना आधार पर 14.8 फीसदी बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल अगस्त में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा था। जीएसटी महानिदेशालय ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया कि सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह अगस्त में सालाना आधार पर 14.8 फीसदी बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए (करीब दो लाख करोड़ रुपए) रहा है। इस दौरान शुद्ध जीएसटी राजस्व संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो सालाना आधार पर 8.3 फीसदी की वृद्धि है। आंकड़ों के अनुसार घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.3 फीसदी बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। आयात से राजस्व 29 फीसदी की बढ़त के साथ 62,604 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह सकल केंद्रीय जीएसटी संग्रह अगस्त में 38,413 करोड़ रुपए रहा, राज्य जीएसटी संग्रह 46,316 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है।

उप्र में हो रही बारिश को देखते हुए सीएम योगी का अधिकारियों को फील्ड में निकलने के निर्देश

◆ मुख्यमंत्री ने दो से चार घंटे में मुआवजा देने को कहा

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि व आर्थिक हानि का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के दिए निर्देश दिए हैं। साथ ही खराब मौसम में लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।

मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जलभराव से जनमानस को कोई समस्या न होने पाए। अति वर्षा, आकाशीय बिजली से हुई जन हानि, पशु हानि व आर्थिक हानि का आंकलन कर दो से चार घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी फील्ड में निकलें। मौके पर जाकर स्थिति का आंकलन कर बचाव कार्य कराएं। प्रभावित परिवारों से अधिकारी संवाद बना कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि खराब मौसम में आकाशीय बिजली के खतरे को देखते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। अतिवृष्टि के समय नदियों व जलाशयों में स्नान करते हुए विशेष सावधानियां बरतें। मंगलवार की सुबह से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कुछ जिलों में तो सोमवार से ही बारिश हो रही है।

दिल्ली के 2.30 लाख घरों पर मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल, कैबिनेट ने दी मंजूरी

400 यूनिट खपत वाले घरों को मुफ्त सोलर सुविधा

एजेंसी, नई दिल्ली। राजधानी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बेहद अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने 'संशोधित सोलर नीति' को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

इस नई नीति के तहत सरकार उपभोक्ताओं को मुफ्त में सोलर पैनल लगाने की सुविधा देने जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं के घरों पर 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल बिलकुल मुफ्त लगाए जाएंगे। इस मुफ्त योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक राजधानी के 2.30 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस संशोधित सोलर नीति को दिल्ली में ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) को अपनाने की दिशा में एक 'मास्टरस्ट्रोक' माना जा रहा है। सरकार के इस कदम से न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों के बिजली बिल का बोझ काफी हद तक कम होगा, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण के लक्ष्यों को हासिल करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। सरकार का पूरा फोकस समय-सीमा के भीतर अपने 2.30 लाख घरों के लक्ष्य को पूरा करने पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिल्लीवासी मार्च 2027 तक इस योजना का सीधा लाभ उठा सकें।

सरकार देगी 100 यूनिट के 9500 रुपए

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत आने वाले कुल खर्च में से 78,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, जबकि शेष 78,000 की राशि का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। मुफ्त इंस्टॉलेशन के साथ-साथ सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक शानदार 'प्रोत्साहन योजना' भी पेश की है। यदि कोई उपभोक्ता अपनी मासिक 200 यूनिट बिजली की खपत के बाद, सोलर पैनल से बनी 100 यूनिट अतिरिक्त बिजली बचाकर वापस ग्रिड को देता है, तो सरकार इसके बदले उसे 9,500 की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी।

कॉमर्शियल सिलेंडर 11 .50 और दूध 9 रुपए हुआ महंगा

एजेंसी, नई दिल्ली। 1 सितंबर से कॉमर्शियल सिलेंडर औसतन 11.50 रुपए महंगा हो गया है। वहीं, मुंबई में आज से दूध 9 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है।

इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाइसी पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी का फायदा लेने में परेशानी हो सकती है। ई-केवाइसी कराने की समयसीमा 31 अगस्त थी। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 11.50 रुपए तक महंगा कर दिया है। कोलकाता में इसकी कीमत 2884 हो गई है। पहले ये 2872.50 में मिल रहा था। इसके अलावा 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर 2 रुपए महंगा हो गया है। अब इसे रिफिल कराने के लिए 764 रुपए देने होंगे। वहीं, 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने 1 सितंबर से थोक दूध की कीमतों में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे थोक दर 93 रुपए से बढ़कर 102 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए 1 सितंबर 2026 से इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टैंप लगवाने का नियम खत्म कर दिया गया है। अब प्रोसेस डिजिटल हो गई है।

ममता बनर्जी की भतीजी फंदे से लटकी मिलीं

एजेंसी, कोलाकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजी ब्रिष्टी मुखर्जी मंगलवार को बीरभूम जिले के कुसुंबा गांव के घर में फंदे से लटकी मिलीं। ब्रिष्टि, ममता के चचेरे भाई और तृणमूल नेता निहार मुखर्जी की बेटी थीं। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिष्टि बोलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थीं। शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद 2024 में उनकी जॉब चली गई थी। इसके बाद से ही वे डिप्रेशन में थीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2024 को अवैध रूप से प्राप्त सभी 25,753 नौकरियां रद्द कर दी थीं। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें ब्याज समेत सैलरी लौटानी होगी। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च, 2025 दिए आदेश में करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है।

गोगामेड़ी से लौट रहे यूपी के श्रद्धालुओं का वाहन पलवल में पलटा, 6 की मौत, 17 घायल

एजेंसी, पलवल। कुंडली-मानेसर-पलवल मार्ग पर मंगलवार तड़के यादूपुर गांव के पास श्रद्धालुओं से भरा 22 सीटर मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए।

मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। हादसे में घायल दो छोटी बच्चियों में 13 वर्षीय वाणी और आठ वर्षीय तनु भी शामिल हैं। दोनों को हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी अनुसार वाहन में कुल 23 श्रद्धालु सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का दल गोगामेड़ी और श्री खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहा था। इसके बाद उनकी वृंदावन व बरसाना जाने की योजना थी। मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे यादूपुर गांव के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में जान गंवाने वाले सभी छह लोगों के बीच आपस में पारिवारिक संबंध और रिश्तेदारी बताई जा रही है।

मृतकों की पहचान विजय सिंह यादव पुत्र हाकिम सिंह निवासी चंदा किशनपुर, रेशमा देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी मैनपुरी, कमला देवी निवासी रामसुधु किशनपुर, राजकुमार, महेश राम सिंह निवासी मैनपुरी और सुधा पत्नी शेर सिंह के रूप में हुई है। वाहन के पलटते ही उसमें सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायलों का उपचार चल रहा है। सदर थाना प्रभारी हरिकिशन शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी।

दिल्ली गैंगरेप पर राहुल बोले-नाकामी पर कब तक पर्दा डालेंगे

एजेंसी, नई दिल्ली। राहुल गांधी ने दिल्ली में 16 साल की नाबालिग से स्लीपर बस में गैंगरेप के मामले को लेकर केंद्र के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 47 किमी चलती बस में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। किसी को जवाबदारी लेनी होगी। दरअसल, सोमवार को दिल्ली में नाबालिग से चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, घटना 4 अगस्त की है, जिसकी जानकारी पुलिस ने 31 अगस्त को दी। बस के ड्राइवर-कंडक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। स्लीपर बस में हुई घटना की जानकारी दिल्ली और नोएडा पुलिस को भी नहीं हुई।

राष्ट्रीय खेलों के पदकवीरों को जल्द मिलेगी नौकरी, 235 खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी : मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, अब तक 29 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 235 से अधिक पदक विजेताओं की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मंगलवार को चंपावत जनपद के टनकपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सितंबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता राज्य की 662 न्याय पंचायतों से प्रारंभ होकर जिला और राज्य स्तर तक पहुंचेगी। इसका उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही राज्य स्तर के विजेताओं को चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धामी ने कहा कि प्रदेश में पहला खेल विश्वविद्यालय शुरू हो चुका है, जबकि महिला खिलाड़ियों के लिए स्थापित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज देश का अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों के लिए बीमा सुविधा, आधुनिक खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 'एक जनपद, एक खेल' योजना के माध्यम से प्रत्येक जिले की खेल पहचान विकसित करने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत न्याय पंचायत स्तर से की गई है, जिससे गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

ब्रह्म सरोवर सहित कुरुक्षेत्र के समग्र सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने तैयार की योजना : सीएम सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर सहित शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार की व्यापक योजना राज्य सरकार ने तैयार की है।

योजना के तहत विभिन्न विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। कई कार्यों के टेंडर लगाए जा रहे हैं,जबकि रेस्ट हाउस सहित अन्य कार्य टेंडर प्रक्रिया में हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायक अशोक अरोड़ा द्वारा ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायक अशोक अरोड़ा ने ब्रह्म सरोवर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है और पूर्व में भी

◆ कुरुक्षेत्र के सौंदर्यीकरण से जुड़े कई कार्यों के टेंडर जारी अन्य टेंडर भी प्रक्रियाधीन

इस विषय को उठाया था। संबंधित मंत्री द्वारा इस संबंध में सदन को विस्तार से जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ब्रह्म सरोवर और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की पूरी योजना बनाई है। रेस्ट हाउस सहित विभिन्न कार्य टेंडर प्रक्रिया में हैं और आने वाले समय में योजनाबद्ध ढंग से इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। कुरुक्षेत्र के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सरकार ने इसके समग्र विकास और सौंदर्यीकरण के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार की है और उसी के अनुरूप कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे और वे स्वयं सांसद थे, उस समय इस परियोजना को लेकर बात रखी गई थी। आज रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। इस परियोजना से शहर को रेलवे फाटकों की समस्या से मुक्ति मिली है और शहर की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है।

सवाल — हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान गूंजा संस्थानों के बंद और खोलने का मुद्दा

जरूरत के आधार पर ही खुलेंगे संस्थान : मुख्यमंत्री सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकारी संस्थानों को बंद करने और नए संस्थान खोलने का मुद्दा छाया रहा।

इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार संस्थानों को राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, जनता की जरूरत और आकलन के आधार पर खोल रही है। जहां संस्थानों की आवश्यकता नहीं है या पर्याप्त आधारभूत ढांचा और स्टाफ उपलब्ध नहीं है, वहां उनका युक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल के मूल

सवाल के जवाब में बताया कि बीते तीन वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के 2,035 संस्थान बंद किए गए, जबकि 362 नए संस्थान खोले गए। उन्होंने बताया कि बंद किए गए संस्थानों में से 123 को बाद में फिर से शुरू किया गया। सुक्खू ने कहा कि संस्थानों को बंद करना सरकार का नीतिगत फैसला होता है और यह व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार ने संस्थानों की समीक्षा की तो कई शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक और विद्यार्थी नहीं मिले। कुछ स्कूलों को पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्राथमिक से उच्च स्तर तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन संबंधित विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। ऐसे संस्थानों को बंद करने के लिए सरकार ने पैरामीटर तय किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां संस्थान खोलने का औचित्य है, वहां सरकार जरूरत के आधार पर उन्हें खोलेगी। वहां कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी और आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में संस्थान खोले थे। कई स्वास्थ्य संस्थान भी खोले गए, लेकिन वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे और जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर संस्थान खोल रही है, जहां आवश्यकता नहीं है, वहां युक्तिकरण किया जाएगा। सुक्खू ने बताया कि 31 जुलाई 2025 के बाद करीब आठ से दस नए संस्थान ही खोले गए हैं।

संस्थान बंद करने के मापदंड सार्वजनिक करे सरकार : जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि सरकार ने 2,035 संस्थान बंद किए, जबकि 362 खोले। इनमें 123 ऐसे हैं, जिन्हें बंद करने के बाद फिर शुरू किया गया। उन्होंने पूछा कि अगर ये संस्थान सही नहीं थे तो इन्हें दोबारा क्यों खोला गया। उन्होंने यह भी पूछा कि संस्थानों को बंद करने के लिए सरकार ने क्या मापदंड तय किए थे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पूरक सवाल में 31 जुलाई 2026 तक बंद और खोले गए संस्थानों की संख्या जाननी चाही। उन्होंने नैनादेवी क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के डिविजन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्टाफ रखने के बाद डिविजन चलाया गया, लेकिन सरकार बदलने पर इसे बंद कर दिया गया। करीब तीन साल बाद कुछ किलोमीटर दूर इसे किराये के भवन में फिर खोला गया।

सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर, ठाकुर ने मांगा जवाब

बिक्रम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की घोषणाओं रोजगार और विकास कार्यों पर उठाए सवाल

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पूर्व उद्योग मंत्री एवं भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय गोलमोल जवाब देकर वास्तविक स्थिति से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उठाए जाने वाले सवाल किसी विधायक के निजी विषय नहीं बल्कि जनता की समस्याओं और अधिकारों से जुड़े होते हैं।

घोषणाओं के धरातल पर उतरने पर सवाल : बिक्रम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र जसवां-प्रागपुर में 15 अप्रैल 2025 को परागपुर में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि घोषणा के बावजूद अभी तक कार्यालय धरातल पर शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक है तो सरकार को ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन के बीच अंतर से जनता में असमंजस पैदा होता है।

बंद संस्थानों को दोबारा खोलने पर उठाए सवाल : भाजपा विधायक ने प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों को बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई संस्थानों को बंद किया था, जबकि अब उनमें से कुछ को दोबारा खोलने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने पूछा कि यदि आज ये संस्थान जनता के लिए आवश्यक हैं तो इन्हें पहले बंद करने का फैसला किस आधार पर लिया गया था। उन्होंने जनहित में आवश्यक संस्थानों की समीक्षा कर उन्हें संचालित करने की मांग की।

चुनावी वादों पर सरकार से मांगा हिसाब : बिक्रम ठाकुर ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने और युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के कांग्रेस के चुनावी वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की जनता के सामने इन वादों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी घोषणाओं और धरातल की वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।

रोजगार और विकास को लेकर सरकार पर हमला : उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योग, पर्यटन और स्वरोजगार को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में कई उद्योग प्रदेश से बाहर गए हैं और बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया।

रत्नाड़ी पंचायत की मांगों पर रोहित ठाकुर ने दिए निर्देश

रत्नाड़ी की सड़कों और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। कोटखाई क्षेत्र की रत्नाड़ी पंचायत के प्रधान सुनील ठाकुर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान पंचायत और क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं तथा लंबित विकास कार्यों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सेब सीजन शुरू होने से पहले क्षेत्र की सड़कों की स्थिति सुधारने और अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से सुंदरनगर रोड के अधूरे कार्य का मुद्दा उठाया। उन्होंने सड़क की मैटलिंग और टायरिंग जल्द करवाने का आग्रह किया। बताया गया कि नाबार्ड के तहत स्वीकृत सुंदरनगर रोड का कार्य अभी लंबित है, जिससे स्थानीय लोगों और बागवानों को परेशानी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सेब सीजन से पहले सड़क का शेष कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक बजट जारी किया जाए, ताकि बागवानों को सेब की ढुलाई में दिक्कत न हो।

लंबित कार्य जल्द पूरे करने पर जोर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुंदरनगर रोड की मैटलिंग और टायरिंग तथा अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी।

इसके अलावा रत्नाड़ी पंचायत में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनाने की मांग भी रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि क्षेत्र में वन विभाग से जुड़े कार्यों और अधिकारियों-कर्मचारियों की आवाजाही को देखते हुए इसकी आवश्यकता है। वन क्षेत्र से संबंधित अन्य समस्याओं और सुविधाओं को लेकर भी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया।

प्रतिनिधिमंडल में पंचायत उपप्रधान यशपाल भोलटा, सुंदरनगर वार्ड सदस्य विजय, गांधी नगर वार्ड सदस्य हीरा सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता लायक राम औस्टा तथा जुब्बल-नावर-कोटखाई ब्लॉक अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हरिदत्त सहित अन्य लोग शामिल रहे।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों पर बिंदल ने सरकार को घेरा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को अपने अधिकारों और पेंशनरी लाभों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो सरकार की संवेदनहीनता दर्शाता है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश के करीब 1.85 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनरी लाभ, एरियर, डीए, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन और चिकित्सा बिलों से जुड़े भुगतान लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक प्रदेश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिंदल ने कहा कि भाजपा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर उनके सभी जायज अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

सहयोग से चलता है सदन, छात्रों से बोले विधानसभा अध्यक्ष

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आठवें दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों के करीब 200 छात्र-छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से मुलाकात की। छात्रों ने सदन की कार्यवाही, विधानसभा की कार्यप्रणाली, अध्यक्ष की भूमिका, विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन सहित कई विषयों पर सवाल पूछे। अध्यक्ष ने सभी प्रश्नों के विस्तार से जवाब दिए।

छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष से किया संवाद

संसदीय व्यवस्था की दी जानकारी : पठानियां ने छात्रों को बताया कि भारत की संसदीय व्यवस्था संघीय ढांचे पर आधारित है। केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि कुछ बड़े राज्यों में विधान परिषद का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वह चौदहवीं विधानसभा के सर्वसम्मति से निर्वाचित अध्यक्ष हैं और उनका प्रमुख दायित्व सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करना है।

दोनों पक्षों का सहयोग जरूरी : विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही सौहार्द, सामंजस्य और सभी सदस्यों के सहयोग से चलती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग लेकर ही विधानसभा की कार्यवाही गरिमा और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है।

छात्रों को बताया जिम्मेदारी : कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों से संवाद करते हुए पठानियां ने कहा कि वे भविष्य में अधिवक्ता और न्यायाधीश बनेंगे। उन्होंने छात्रों से लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अधिवक्ताओं की भूमिका का उल्लेख करते हुए मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं का उदाहरण दिया।

विधानसभा की गरिमा पर जोर : पठानियां ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अपनी उच्च परंपरा और गरिमा रही है। विट्ठलभाई पटेल ने राष्ट्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में संसदीय परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने छात्रों को सदन की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानियां भी मौजूद रहे।

भरवाई स्कूल की छात्राओं ने जीती अंडर-19 बैडमिंटन प्रतियोगिता

भारतेन्दु संवाददाता, भरवाई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरवाई की छात्राओं ने अंडर-19 जोनल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। विद्यालय की छात्राओं सिमरन, निकुंज, राधिका और अंकिता ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया और विद्यालय के साथ-साथ अपने माता-पिता तथा क्षेत्र का नाम रोशन किया।

प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में शानदार प्रदर्शन : विद्यालय के शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता एवं प्रशिक्षक रजनीश कुमार के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण में छात्राओं ने प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रभावी प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी हासिल की।

विजेता टीम को किया सम्मानित : उपनिदेशक स्कूल शिक्षा (प्राथमिक) ऊना सोम लाल धीमान ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। एस्कॉर्ट अध्यापिका वंदना कौंडल ने भी छात्राओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय में खुशी का माहौल : छात्राओं की इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्य निर्मल कुमार, स्कूल प्रबंधन समिति की अध्यक्ष रितिका कौशल, समिति के सदस्यों, अध्यापकों और विद्यार्थियों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। सभी ने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

हिमाचल के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण हुआ शुरू

अनिल कुमार शर्मा ,भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का कार्य 1 सितंबर से शुरू हो गया है। यह अभियान 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर निर्धारित 40 प्रश्नों के माध्यम से जनसंख्या संबंधी जानकारी एकत्र करेंगे। पूरी तरह हिमाच्छादित क्षेत्रों में शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति शामिल हैं, जबकि चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी के कुछ क्षेत्र आंशिक रूप से हिमाच्छादित हैं। इन क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए समयबद्ध तरीके से गणना पूरी की जाएगी। 17 से 31 अगस्त तक निवासियों को स्व-गणना की सुविधा भी दी गई थी। जिन परिवारों ने स्व-गणना पूरी की है, उन्हें प्रगणक के पहुंचने पर स्व-गणना पहचान संख्या उपलब्ध करानी होगी। जिन लोगों ने स्व-गणना नहीं की है, उनकी जानकारी प्रगणक घर जाकर दर्ज करेंगे।

चौदहवीं विधान सभा के 12वें सत्र (मॉनसून सत्र) के 8वें दिन की कार्यवाही का संचालन करने विधान सभा सचिवालय पहुँचने पर सलामी लेते विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां।

कुमारसैन में महिला की आंखों में मिर्च डालकर लूटी बालियां

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। कुमारसैन थाना क्षेत्र के दरोग गांव में बदमाश ने महिला की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर सोने की बालियां छीन लीं। सीमा देवी अपनी बेटी को स्कूल से घर लेकर पैदल लौट रही थीं। घर के पास पीछे से आए व्यक्ति ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। इसी दौरान बदमाश दोनों कानों से सोने की बालियां छीनकर फरार हो गया। महिला के अनुसार बालियों की कीमत करीब 20 हजार रुपये थी। शिकायत मिलने पर कुमारसैन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षकों के लिए रोजगार का अवसर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला के अनुसार समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के तहत संचालित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम शास्त्रांग इंडियन मॉडर्न मार्शल आर्ट द्वारा सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च और माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं को 36 घंटे का आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक और योग्य युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित प्रशिक्षकों को तीन दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला और आवश्यक पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षण देना होगा। जिले के करीब 616 विद्यालयों में कार्यक्रम संचालित होने की संभावना है। मार्शल आर्ट, आत्मरक्षा, खेल गतिविधियों या प्रशिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले इच्छुक युवा अधिक जानकारी के लिए 9988874789 पर संपर्क कर सकते हैं।

शिमला-दधोगी बस रूट पर अव्यवस्था खराब बसों से यात्री हो रहे परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। शिमला से कोठी जमोगी होते हुए दधोगी जाने वाले बस रूट पर पिछले कुछ दिनों से बस सेवा सुचारू नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार 20 अगस्त 2026 से इस रूट पर बसों की व्यवस्था प्रभावित है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रूट पर कई बार ऐसी बसें भेजी जा रही हैं, जिनकी स्थिति पहले से ही बेहतर नहीं होती। सफर के दौरान बसों में तकनीकी खराबी आने के कारण वे बीच रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। इसके चलते यात्रियों को काफी देर तक परेशानी झेलनी पड़ती है और कई बार उन्हें वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

ग्रामीणों के मुताबिक बस सेवा में लगातार आ रही बाधा से क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में बसों के खराब होने से लोगों को अतिरिक्त समय और खर्च दोनों उठाना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने कहा कि समस्या केवल सड़क की स्थिति से संबंधित नहीं है। बसों की हालत और उनके नियमित रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि बसों की समय-समय पर तकनीकी जांच और आवश्यक मरम्मत की जाए तो बीच रास्ते में बस खराब होने की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

दधोगी पंचायत प्रधान भूपेंद्र शर्मा, पंचायत समिति सदस्य सागर शर्मा, पंचायत के वार्ड सदस्य, युवक मंडल दधोगी के प्रधान अमित कुमार शर्मा सहित अन्य स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है।

मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए रामपुर में 8 सितंबर को होंगे साक्षात्कार

भातरेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला की ओर से 8 सितंबर 2026 को उप रोजगार कार्यालय रामपुर में कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस दौरान ऑरो टेक्सटाइल बद्दी, जिला सोलन में मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं या आईटीआई पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी भर्ती में भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 13,500 रुपये मासिक वेतन के साथ आवास सुविधा भी दी जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। अपंजीकृत उम्मीदवार रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 8410184542 और 9816021174 पर संपर्क किया जा सकता है।

18 संगठनों के हजारों पेंशनरों ने चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

लंबित देनदारियों को लेकर पेंशनरों ने किया प्रदर्शन, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। वर्षों से लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशनरों ने राजधानी शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेशभर के 18 संगठनों से जुड़े पेंशनर हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए। सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक चली रैली में पेंशनरों ने सरकार से लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की।

आश्वासन पूरा नहीं होने पर नाराजगी : प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित रैली में पेंशनरों ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि भुगतान संबंधी अधिसूचना जारी होनी चाहिए।

कई देनदारियां लंबित : प्रदर्शनकारियों के अनुसार, एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, 166 माह के वेतन एरियर और पेंशन एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की लंबित राशि जारी करने की मांग भी उठाई गई।

परिवहन पेंशनरों की समस्याएं :: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन कल्याण संघ के अध्यक्ष बृज लाल ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम के पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। उन्होंने हर माह पहली तारीख को पेंशन देने और लंबित चिकित्सा बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की।

सरकार को आंदोलन की चेतावनी : संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि 13 मई को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में 31 जुलाई से पहले 40 प्रतिशत अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिसूचना जारी करने पर सहमति बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

भारत की विकास दर पर बिंदल ने जताया गर्व, राहुल गांधी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

भारत की आर्थिक प्रगति पर बिंदल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सोमवार को शिमला के बालूगंज चौक पर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देश की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने पर खुशी जताते हुए इसे भारत की प्रगति का प्रमाण बताया। उन्होंने देशवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी।

चाय को बताया संवाद का माध्यम : डॉ. बिंदल ने कहा कि चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और आपसी संवाद का माध्यम है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक चाय अलग-अलग तरीकों से पी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा का विषय भी जनसंवाद से जुड़ा है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना : कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बिंदल ने आरोप लगाया कि उन्हें हर विषय में विभाजन दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि कागज के कप और दूसरे प्रकार के कप को लेकर भी विभाजन की बात करना उचित नहीं है। बालूगंज में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं।

राष्ट्रीय एकता पर जोर : बिंदल ने कहा कि देश को एकजुट रखना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटने वाली राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती।

लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा जरूरी : उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल को जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखने और समर्थन हासिल करने का अधिकार है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव से समझौता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में एकता है। देश की प्रगति के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना आवश्यक है।

सहायता मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की

शिमला में ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े 4,050 सहारा लाभार्थी

भारतेन्दु संवाददाता शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सहारा योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में योजना को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने के लिए विकसित की गई नई ऑनलाइन प्रणाली की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

विभाग ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए समर्पित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। नई व्यवस्था के तहत 4,050 सक्रिय और पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन मंच पर स्थानांतरित किया जा चुका है। इनमें से 3,958 लाभार्थियों की आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद जुलाई 2026 की वित्तीय सहायता के रूप में अब तक 3,723 लाभार्थियों को राशि जारी की जा चुकी है।

बैठक में बताया गया कि ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से योजना के तहत अब तक 4,143 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों को योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच और प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीकृत किया जा रहा है। विभाग का ऑनलाइन पोर्टल आम जनता के लिए उपलब्ध है। पात्र व्यक्ति और जरूरतमंद परिवार इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है, जो चिन्हित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लंबे समय तक चलने वाले उपचार के दौरान परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जरूरत के अनुसार मरीजों के परिचारकों को भी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर बीमारियों के इलाज में लंबे समय तक खर्च होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिलने से उपचार जारी रखने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक बिना अनावश्यक परेशानी के पहुंचे।

वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए 20.01 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों तक सहायता समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले चिकित्सा उपचार के कारण आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव सीपी वर्मा, निदेशक ईएसओएमएसए सुमित किमटा, निदेशक महिला एवं बाल विकास डॉ. पंकज ललित सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन देशों के उच्चायुक्तों से मिले राज्यपाल

अनिल थपलियाल

देहरादून। देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) से भारत के तीन देशों में नियुक्त उच्चायुक्तों ने शिष्टाचार भेंट की। जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा, लिथुआनिया में भारत के उच्चायुक्त देवेश उत्तम और जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपने-अपने देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों की गतिविधियों और कार्यों की जानकारी साझा की। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, पर्यटन, स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ी संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

◆ **उत्तराखंड के ग्रामीण पर्यटन को विदेशों में बढ़ावा देने की अपील की**

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड अपनी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, योग तथा आयुर्वेद की परंपरा के कारण वैश्विक स्तर पर वेलनेस और आध्यात्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। उन्होंने उच्चायुक्तों से अपने-अपने देशों में उत्तराखंड की योग, आयुर्वेद, मिलेट्स, स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पादों तथा होमस्टे संस्कृति को बढ़ावा देने में सहयोग करने का आग्रह किया। उनका कहना था कि उत्तराखंड की विशिष्ट जीवनशैली और प्राकृतिक वातावरण विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट करते तीन देशों के उच्चायुक्त।

बालिकाओं के विदेश अध्ययन भ्रमण की पहल पर जोर

राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिलेट आधारित खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, स्थानीय खान-पान और ग्रामीण जीवन से जुड़े अनुभव विदेशों में उत्तराखंड की अलग पहचान बनाने में सहायक हो सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ युवाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भेंट के दौरान राज्यपाल ने उत्तराखंड की बालिकाओं के लिए विदेशों में अध्ययन भ्रमण और एक्सपोजर विजिट आयोजित करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति, तकनीक और कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

यूपीईएस के छात्रों को मिलेंगे जेमिनी एंटरप्राइज के अत्याधुनिक एआई साधन

10,100 छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा जेमिनी एंटरप्राइज का लाभ

अनिल थपलियाल

देहरादून। यूपीईएस और गूगल क्लाउड के बीच रणनीतिक सहयोग ने विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा को नई गति दी है। देहरादून स्थित यूपीईएस में गूगल जेमिनी डे के आयोजन के साथ छात्रों और शिक्षकों के लिए 10,100 जेमिनी एंटरप्राइज फॉर एजुकेशन की सुविधा शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य पढ़ाई, अध्यापन, शोध, सहयोग और नवाचार के क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को व्यापक बनाना है। कार्यक्रम में गूगल इंडिया, गूगल क्लाउड के प्रतिनिधियों, प्रौद्योगिकी सहयोगी पैराडाइमआईटी तथा यूपीईएस के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जनरेटिव एआई की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई और बताया गया कि अत्याधुनिक एआई साधनों की मदद से विद्यार्थी नए विचारों पर काम करने, समस्याओं का समाधान खोजने और रचनात्मक परियोजनाएं विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। गूगल जेमिनी डे के दौरान छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र और प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें जेमिनी एंटरप्राइज के विभिन्न शैक्षणिक उपयोगों और इसके जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई।

यूपीईएस ने एआई शिक्षा के लिए गूगल क्लाउड से मिलाया हाथ।

यूपीईएस को डिजिटल कैंपस बनाने की तैयारी तेज

गूगल क्लाउड के प्रतिनिधि वैभव कुमार श्रीवास्तव ने यूपीईएस को डिजिटल कैंपस के रूप में आगे बढ़ने के लिए बधाई दी और कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य की कार्यशक्ति के साथ भविष्य के रोजगार सृजकों को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेमिनी एंटरप्राइज की सुविधा से छात्र और शिक्षक एआई आधारित समाधान विकसित करने, शोध कार्यों में तकनीक का प्रयोग करने और विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रयोग करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल यूपीईएस के एआई सक्षम शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों को तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

एआई प्रशिक्षण से विद्यार्थियों की बढ़ेगी दक्षता

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जनरेटिव एआई की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई और बताया गया कि अत्याधुनिक एआई साधनों की मदद से विद्यार्थी नए विचारों पर काम करने, समस्याओं का समाधान खोजने और रचनात्मक परियोजनाएं विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं। गूगल जेमिनी डे के दौरान छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र और प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें जेमिनी एंटरप्राइज के विभिन्न शैक्षणिक उपयोगों और इसके जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई।

यूपीईएस के कुलपति डॉ. सुनील राय ने कहा कि एआई फर्स्ट विश्वविद्यालय बनना केवल आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया, शिक्षकों के अध्यापन और शोध गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना भी जरूरी है।

सॉन्ग बांध से देहरादून और जमरानी से हल्द्वानी को मिलेगा सुनिश्चित पेयजल

जल शक्ति मंत्रालय के शिखर सम्मेलन में सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की जल योजनाओं की प्रगति बताई

अनिल थपलियाल

नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के सिंचाई, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में चल रही जल संसाधन विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, कृषि भूमि की सिंचाई, भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। महाराज ने बताया कि उत्तराखंड में 3142 लिफ्ट नहरें और 1774 नलकूप हैं, जिनसे कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिल रही है।

देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉन्ग नदी पर बांध निर्माणाधीन है। इस परियोजना से वर्ष 2051 तक अनुमानित आबादी को प्रतिदिन 150 मिलियन लीटर पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसी तरह हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए गोला नदी पर जमरानी बांध का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रतिदिन 117 मिलियन लीटर पेयजल आपूर्ति के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

महाराज ने गैरसैंण सहित अन्य क्षेत्रों में प्रस्तावित बांध और बैराज परियोजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कैच द रेन अभियान के तहत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। चाल-खाल, चेक डैम और छत आधारित वर्षाजल संचयन जैसी संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। प्रस्तावित 4998 जल संचय संरचनाओं में से अधिकांश का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने जल संरक्षण को भविष्य की जरूरत बताते हुए योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

खटीमा में नगर वन ऑक्सीजन पार्क का मुख्यमंत्री धामी ने किया लोकार्पण

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में नवनिर्मित नगर वन ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर में पौधरोपण करने के साथ ही पार्क का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खटीमा क्षेत्र के विकास से संबंधित छह महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने नगर वन ऑक्सीजन पार्क का विस्तारीकरण करने, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय को पार्क परिसर में स्थानांतरित करने, खटीमा में स्टेडियम का निर्माण करने, क्रियाशाला का निर्माण करने, सर्किट हाउस का निर्माण करने तथा वेंडिंग जोन विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खटीमा की भौगोलिक स्थिति पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्यास वैली, पंचाचूली और आदि कैलाश की ओर जाने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खटीमा में सर्किट हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने नगर वन ऑक्सीजन पार्क के विस्तारीकरण एवं आवश्यक संसाधनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही।

न्यूज ब्रीफ

सुंग गांव में तीसरी बार जन्मा चौसिंग्या खाड़ू, मां नंदा की यात्रा में जाएगा कैलाश

अनिल थपलियाल। चमोली के नंदानगर स्थित सुंग गांव में इस बार फिर चौसिंग्या खाड़ू के जन्म लेने से ग्रामीणों और नंदा भक्तों में उत्साह है। करीब ढाई दशक में यह तीसरी बार है, जब गांव में चौसिंग्या खाड़ू ने जन्म लिया है। वर्ष 2000 और 2014 के बाद अब 2026 में भी इसी गांव से मां नंदा की यात्रा के लिए चौसिंग्या खाड़ू निकलेगा। वर्तमान उपप्रधान रमेश सिंह बिष्ट की गौशाला में जन्मे करीब आठ माह के खाड़ू को 3 सितंबर को ग्रामीण ढोल-दमाऊ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर ले जाएंगे। यहां पूजा-अर्चना के बाद 5 सितंबर को होने वाली बड़ी जात यात्रा में खाड़ू मां नंदा की अगुवाई करेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार चौसिंग्या खाड़ू को मां नंदा की यात्रा का मार्गदर्शक और अगुवा माना जाता है। ग्रामीण इस संयोग को मां नंदा की विशेष कृपा मान रहे हैं।

बैडमिंटन खेलने को लेकर कहासुनी के बाद चाकूबाजी, 12 वर्षीय बच्चे की मौत

अनिल थपलियाल। नैनीताल कुमाऊं जसपुर के लकड़ी मंडी क्षेत्र में बैडमिंटन खेलने को लेकर बच्चों में विवाद हो गया। आरोप है कि खेलने से मना करने पर करीब 10-11 वर्षीय नाबालिग ने 12 वर्षीय मोहम्मद ईशान पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ईशान की काशीपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सीखी बाल विकास की नई गतिविधियां

अनिल थपलियाल। नई टिहरी के बाल विकास परियोजना चंबा में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें स्कूल पूर्व शिक्षा के तहत बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यकर्त्रियों ने कविताओं, खेलों और संवाद के माध्यम से भाषा, शारीरिक और मानसिक विकास की गतिविधियां प्रस्तुत कीं। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौरव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका पर प्रकाश डाला। बाल विकास परियोजना अधिकारी ममता लेखक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयोगी बताया। वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी गई।

कैम्पटी में 1.034 किलो डोडा पोस्त के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

अनिल थपलियाल। नई टिहरी गढ़वाल में कैम्पटी पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 31 अगस्त को मसूरी बैंड के पास सघन चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध स्कार्पियो वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 1.034 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन सवार अभिनव पंवार और शुभम नेगी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ स्कार्पियो वाहन भी जब्त कर लिया। आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

उत्तराखंड में बिना मान्यता वाले मदरसों पर सरकार सख्त

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपना रुख और कड़ा कर दिया है। राज्य में अब वही मदरसे संचालित हो सकेंगे जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता हासिल करेंगे और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जाएगा। मदरसों को लेकर सरकार की सख्ती के बीच रुद्रपुर में जश्न-ए-मोहम्मदी जुलूस के दौरान त्रिशूल चौक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला भी सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने संबंधित मौलवी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने उसके मदरसे को सील कर दिया था। प्रशासन की ओर से बताया गया था कि संबंधित मदरसा निर्धारित मान्यता के बिना संचालित हो रहा था और लागू नियमों का पालन नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति सरकार की सख्त नीति दोहराई है। मुख्यमंत्री के अनुसार देवभूमि में ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा जो कट्टरता को बढ़ावा दे।

नेपाल आपदा पर गोरखाली महिला कमेटी ने की विशेष पूजा

अनिल थपलियाल

देहरादून। नेपाल में आई विनाशकारी जल प्रलय और भीषण बाढ़ से हुई जनहानि एवं तबाही पर देहरादून की गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव कमेटी ने गहरी संवेदना व्यक्त की। कमेटी की ओर से मृतकों की आत्मा की शांति और लापता लोगों की सकुशल बरामदगी के लिए गढ़ी कैंट स्थित शनि मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई। पूजा आचार्य श्री सुशांत जी महाराज के सान्निध्य में संपन्न हुई।
कमेटी पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा ने बड़ी संख्या में परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया है।

बाढ़ और जल प्रलय के कारण कई लोगों की जान चली गई, जबकि अनेक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और जरूरी सुविधाओं का संकट भी उत्पन्न हो गया है। कमेटी ने आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए आर्थिक सहयोग करने का संकल्प लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से जुड़ा देश है, इसलिए वहां की त्रासदी का दुख भारत में भी महसूस किया जा रहा है।

सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाए युवा मंगल दल: प्रेमचंद अग्रवाल

अनिल थपलियाल। (ऋषिकेश) नवगठित खदरी युवा मंगल दल के पदाधिकारियों ने ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल से उनके कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान डॉ. अग्रवाल ने युवा मंगल दल के पदाधिकारियों का माल्यार्पण और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने नवगठित टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं की सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा मंगल दल जनसेवा, सामाजिक सरोकारों और सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में प्रभावी योगदान दे सकता है। उन्होंने युवाओं से समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। साथ ही विश्वास जताया कि खदरी युवा मंगल दल क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और सामाजिक विकास के लिए सक्रियता से कार्य करेगा। इस अवसर पर अध्यक्ष कुलदीप नेगी, सचिव अश्विनी रयाल, कोषाध्यक्ष आशीष भट्ट सहित अन्य पदाधिकारी और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बलिदान | 2 सितंबर 1994 का मसूरी गोलीकांड उत्तराखंड के इतिहास में दर्दनाक शहादत का अमिट अध्याय

मसूरी गोलीकांड की शहादत आज भी अमर

विकास बलोनी

देहरादून। दो सितंबर 1994 उत्तराखंड के इतिहास का वह दिन है जिसे राज्य आंदोलन की पीड़ा और शहादत के साथ याद किया जाता है। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान मसूरी में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। यह घटना केवल एक गोलीकांड नहीं थी, बल्कि उस दौर में पहाड़ के लोगों की आकांक्षाओं, आक्रोश और संघर्ष की गंभीर अभिव्यक्ति भी थी।

आंदोलनकारी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे ताकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जरूरतों और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के अनुरूप विकास की नीतियां बनाई जा सकें। मसूरी की घटना में कई आंदोलनकारी घायल हुए और अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हिंसा के दौरान पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी की भी मृत्यु हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया कि लोकतांत्रिक मांगों के समाधान के लिए संवाद और संवेदनशीलता की जगह बल प्रयोग क्यों हुआ।

राज्य गठन के बाद भी सपने अधूरे

मसूरी और खटीमा की घटनाओं ने उत्तराखंड आंदोलन को कमजोर करने के बजाय उसे और व्यापक बना दिया। गांवों, कस्बों और शहरों से लेकर देश की राजधानी तक अलग राज्य की मांग तेज होती गई। यह आंदोलन केवल प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की मांग नहीं रहा, बल्कि पहाड़ की पहचान, सम्मान, रोजगार, विकास और भविष्य से जुड़ा जनसंघर्ष बन गया। लंबे संघर्ष और अनेक बलिदानों के बाद उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। लेकिन आज भी यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या राज्य निर्माण के पीछे जिन सपनों और उम्मीदों ने आंदोलन को जन्म दिया था, वे पूरी तरह साकार हो पाए हैं। शहीदों की स्मृति हमें पहाड़ में रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बुनियादी सुविधाओं जैसे सवालों पर आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है।

आंदोलन में दिखा पहाड़ का आक्रोश

यह घटना केवल एक गोलीकांड नहीं थी, बल्कि उस दौर में पहाड़ के लोगों की आकांक्षाओं, आक्रोश और संघर्ष की गंभीर अभिव्यक्ति भी थी। आंदोलनकारी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे ताकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जरूरतों और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के अनुरूप विकास की नीतियां बनाई जा सकें।

शहीदों को चाहिए विकसित उत्तराखंड

आंदोलनकारियों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उत्तराखंड को ऐसा राज्य बनाया जाए जहां पहाड़ के अंतिम व्यक्ति तक विकास, सम्मान और अवसर पहुंच सकें। यही उन अमर बलिदानों की वास्तविक सार्थकता होगी।

न्यूज शॉर्ट्स

जल जीवन मिशन के भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने खोला मोर्चा

अनिल थपलियाल। जल जीवन मिशन के तहत लंबित भुगतान को लेकर उत्तराखंड के ठेकेदारों में आक्रोश बढ़ गया है। देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेशभर के ठेकेदार 2 सितंबर को सचिवालय कूच कर धरना प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन का आरोप है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री को समस्या समाधान के लिए दिया गया तीन दिन का समय भी समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

कुमाऊं विश्वविद्यालय में विशेष बैक परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसरों, महाविद्यालयों और संस्थानों में संचालित ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए विशेष बैक परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनमें अध्यादेश के अनुसार विशेष बैक परीक्षा का प्रावधान है। विद्यार्थी 2 से 10 सितंबर 2026 तक समर्थ एवं विश्वविद्यालय के ईआरपी पोर्टल के माध्यम से परीक्षा के लिये आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रथम से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि में आवेदन करने को कहा है।

मेडिकल कॉलेज निर्माण को क्रमिक अनशन शुरू

भारतेंदु संवाददाता, नई टिहरी। टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में नई टिहरी के गणेश चौक में मंगलवार को आंदोलन के तहत क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रथम दिन नागरिक मंच के त्रिलोक चंद रमोला, जगजीत सिंह नेगी क्रमिक अनशन पर बैठे। वहीं पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष जीतराम भट्ट का सत्याग्रह जारी है। इससे पहले 16 अगस्त से यहां पर क्रमिक धरना दिया जा रहा था। मंगलवार को बौराड़ी में वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि सीएम घोषणा के तहत नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। विस्थापित शहर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या बनी हुई है। सीएम धामी से समिति की वार्ता में भी उन्होंने नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है।

मनीषा जोशी को मिला एसीएस एग्रो जर्नी अवार्ड

भारतेंदु संवाददाता, नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर नैनीताल के रसायन विज्ञान विभाग की शोधार्थी मनीषा जोशी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्हें अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के एसीएस एग्रो डिवीजन की ओर से वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एसीएस एग्रो जर्नी अवार्ड प्रदान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 में यह पुरस्कार विश्वभर से केवल दो शोधार्थियों को प्रदान किया गया, जिनमें भारत से मनीषा जोशी का चयन हुआ। पुरस्कार के साथ उन्हें 2,000 अमेरिकी डॉलर की राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उनकी इस उपलब्धि को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे शोध कार्य की अंतरराष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जा रहा है। मनीषा जोशी ने 23 से 27 अगस्त तक अमेरिका के शिकागो में आयोजित एसीएस फॉल 2026 नेशनल मीटिंग में प्रतिभाग किया।

दशकों बाद पंजाब के भूजल स्तर में सुधार 109 ब्लॉकों में दिखा सकारात्मक बदलाव

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वर्ष 2026 के ताजा आंकड़ों और मूल्यांकन के अनुसार, राज्य में दशकों बाद पहली बार भूजल स्तर की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। पंजाब के जल संसाधन मंत्री ने यह जानकारी साझा करते हुए इसे भूजल संकट से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मंत्री के अनुसार, राज्य में भूजल के अत्यधिक दोहन की दर वर्ष 2022 में 164 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2026 में घटकर 152.22 प्रतिशत रह गई है। वहीं, अत्यधिक दोहन वाले ब्लॉकों की संख्या भी 117 से घटकर 110 हो गई है। दूसरी ओर, सुरक्षित श्रेणी वाले ब्लॉकों की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है।

109 ब्लॉकों में दर्ज हुआ सुधार : कुल 153 मूल्यांकन किए गए ब्लॉकों में से 109 में भूजल की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यह बदलाव सरकार की ओर से नहर का पानी खेतों तक पहुंचाने और भूजल पर निर्भरता कम करने के प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने बताया कि राज्य में भूजल का वार्षिक इस्तेमाल भी कम हुआ है। वर्ष 2022 में जहां करीब 28.02 अरब घन मीटर भूजल का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं वर्ष 2026 में यह घटकर 26.32 अरब घन मीटर रह गया है। सरकार का लक्ष्य नहर आधारित सिंचाई को बढ़ावा देकर किसानों की भूजल पर निर्भरता और कम करना है।

14 ब्लॉक बेहतर श्रेणी में पहुंचे : वर्ष 2025 के मुकाबले इस बार 14 ब्लॉक बेहतर श्रेणी में पहुंचे हैं। इनमें से चार ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में शामिल हो गए हैं। फाजिल्का जिले का अरनीवाला शेख सुभानपुर, फिरोजपुर का मक्खू, होशियारपुर का हाजीपुर और पठानकोट का नरोट जैमल सिंह सुरक्षित श्रेणी में पहुंच गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार, भूजल बचाने के लिए नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।

पीयू चुनाव में एबीवीपी की जीत ने पंजाब की सियासत में बढ़ाई हलचल

पीयू छात्रसंघ में एबीवीपी की जीत से आप-कांग्रेस को झटका, 2027 चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। चुनाव छात्र संघ का था, लेकिन इसके नतीजों को पंजाब के युवा मतदाताओं के रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय में करीब 65 प्रतिशत छात्र पंजाब के विभिन्न जिलों और अलग-अलग वर्गों से जुड़े हैं।

एबीवीपी के अंकित बिढ़ान ने अध्यक्ष पद पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एएसएपी के आदिल बराड़ को 512 वोटों से हराया। अंकित बिढ़ान को 3149 वोट मिले, जबकि आदिल बराड़ के खाते में 2637 वोट आए। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के प्रत्याशी गुरमन सिंह सिद्धू 2263 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

उपाध्यक्ष पद पर पीयूडीएफ के अमन सिंह ने जीत हासिल की। महासचिव पद निर्दलीय ध्यान सिंह और संयुक्त सचिव पद पर निर्दलीय विशाल बामल विजयी रहे। चुनाव परिणाम में एबीवीपी की जीत के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की छात्र इकाइयों को बड़ा झटका लगा है।

आप और कांग्रेस को लगा झटका : छात्र संघ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीदें थीं। हाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए जेन-जी आंदोलन के बाद पार्टी ने युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को लेकर रणनीति बनाई थी। आप ने चुनाव की कमान अपने युवा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को सौंपी थी और छात्र चुनाव में पूरी ताकत झोंकी थी।

इसके बावजूद पार्टी अध्यक्ष पद पर जीत हासिल नहीं कर सकी। उसकी छात्र इकाई का प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहा। कांग्रेस के लिए परिणाम और अधिक चुनौतीपूर्ण रहे। एनएसयूआई के गुरमन सिंह सिद्धू तीसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस की छात्र इकाई कोई भी प्रमुख पद हासिल नहीं कर सकी।

पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी का भी असर : छात्र संघ चुनाव में पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का असर भी दिखाई दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के कारण छात्र राजनीति में सक्रिय रहने वाले कांग्रेस नेताओं की भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर रही। माना जा रहा है कि पार्टी की आंतरिक गुटबाजी का असर छात्र इकाई के प्रदर्शन पर पड़ा।

मतदान से एक दिन पहले एबीवीपी को मिला शिअद का समर्थन

इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा एबीवीपी को मिले समर्थन की रही। मतदान से ठीक एक दिन पहले 31 अगस्त को शिरोमणि अकाली दल की छात्र इकाई एसओआई ने एबीवीपी के समर्थन की घोषणा की। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में भाजपा इस बार सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। दूसरी ओर, शिरोमणि अकाली दल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के संबंध में अभी अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है। हाल ही में शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी थी। ऐसे में छात्र संघ चुनाव में दोनों दलों की इकाइयों का एक साथ आना संभावित राजनीतिक समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

सिल गांव में पशुओं में लंपी बीमारी से पशुपालक हुए चिंतित

भारतेन्दु संवाददाता, खरड़। खरड़ के नजदीकी गांव सिल में पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के मामले सामने आने के बाद पशुपालकों में चिंता बढ़ गई है। दूध उत्पादक सहकारी सभा सिल के प्रधान सुखदेव राज ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में कई पशुओं, विशेषकर गायों में बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। प्रभावित पशुओं को तेज बुखार और दर्द के कारण चलने-फिरने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि बीमारी के कारण पशुओं का स्वास्थ्य प्रभावित होने के साथ दूध उत्पादन में भी कमी आ रही है। इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पशुपालकों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो यह आसपास के क्षेत्रों में भी फैल सकती है।

सत्र न्यायाधीश ने जेलों का निरीक्षण कर कैदियों की सुनीं समस्याएं

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना । जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी हरप्रीत कौर रंधावा ने ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल, महिला जेल और ब्रोस्टल जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव हिमांशु अरोड़ा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सत्र न्यायाधीश ने जेल अधीक्षकों की मौजूदगी में कैदियों और हवालातियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को जायज समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही कैदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार की जानकारी दी और जरूरतमंदों को जेल में संचालित कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क कर आवेदन करने के लिए कहा। उन्होंने सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए तैयार भोजन की गुणवत्ता भी जांची। इसके अलावा ब्रोस्टल जेल में निर्माणाधीन 'बेटर लाइफ प्रिजन स्कूल' का निरीक्षण किया। यहां बच्चों को चित्रकला, कला और कंप्यूटर जैसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने जेल अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और निरीक्षण में मिली कमियों को दूर कर कार्रवाई रिपोर्ट समय पर सौंपने के निर्देश दिए।

ईएसआई अस्पताल में बदली रेफरल व्यवस्था पहले सरकारी उपचार जरूरी

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर। मजीठा रोड स्थित सरकारी ईएसआई अस्पताल में अब मरीजों को सीधे निजी अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने आदेश जारी कर पहले सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ईएसआई अस्पताल में इलाज संभव न होने पर मरीज को पहले गुरु नानक देव अस्पताल भेजा जाएगा। वहां भी आवश्यक उपचार या सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर नियमों के अनुसार निजी अस्पताल में रेफर किया जाएगा। आपातकालीन विभाग में तैनात चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सलाह के बिना मरीज को रेफर नहीं कर सकेंगे। हालांकि, निजी अस्पताल में पहले से इलाज करा रहे मरीजों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

एसडी कॉलेज रोड पर निर्माण को लेकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। एसडी कॉलेज रोड पर कॉलेज के सामने बनी दो चार मंजिला इमारतों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। निगम ने इन निर्माणों को लेकर नोटिस जारी किए थे, लेकिन इसके बाद अब तक आगे की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण नियमों के विपरीत हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, अधिकारियों की कथित मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत संबंधित पोर्टल और लोकपाल तक पहुंचने की बात कही जा रही है। शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। अब सवाल है कि नोटिस के बाद निगम इन इमारतों पर क्या कार्रवाई करता है। निगम की ओर से निर्माण वैध होने या नियमों के उल्लंघन को लेकर स्थिति स्पष्ट किए जाने की भी मांग उठ रही है।

मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर किसानों का सात दिवसीय मोर्चा, कई रास्ते बंद, तीन वैकल्पिक मार्ग तय

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

पंजाब के 32 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर आज से सात दिवसीय पक्का मोर्चा शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर लगाए जा रहे इस मोर्चे के लिए किसान संगठनों ने पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब के विभिन्न इलाकों से किसान ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इसके चलते मोहाली के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

किसानों के ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के पहुंचने के कारण फेज-11, जगतपुरा, बाबा व्हाइट हाउस चौक सहित शहर के अंदरूनी इलाकों में वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। प्रशासन और यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से इन क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है।

किसानों के पक्के मोर्चे को देखते हुए आयशर चौक से एयरपोर्ट रोड तथा आयशर चौक से फेज-9 की ओर जाने वाले मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को फेज-10 और फेज-11 की ओर जाने से बचने को कहा गया है।

आयशर चौक से बेस्टेक माल तक मार्ग बंद : किसानों के ट्रैक्टर-ट्रालियों के पहुंचने के कारण आयशर चौक से बेस्टेक माल तक की सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। प्रशासन ने यातायात को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।

पिछली बार किसानों ने प्रशासन के साथ बैठक किए बिना इसी स्थान पर मोर्चा लगाया था, जिसके कारण शहर के कई रास्तों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस बार किसान यूनियन नेताओं और मोहाली-चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक के बाद मोर्चा लगाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में प्रशासन को उम्मीद है कि यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर तरीके से संभाली जा सकेगी।

एसआईआर में लापरवाही पर बीएलओ अध्यापिका निलंबित, विभागीय जांच के आदेश हुए जारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बूथ लेवल अधिकारी की जिम्मेदारी में कथित लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जीएमएचएस-32 में तैनात टीजीटी (हिंदी) अध्यापिका अमृत पाल कौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वह सेक्टर-41डी के भाग संख्या 324 की बूथ लेवल अधिकारी थीं।

आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, अमृत पाल कौर पर मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करने तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित गणना प्रपत्र एकत्र करने से कथित तौर पर इन्कार करने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने मतदाताओं से प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से जमा कराने के बजाय सीधे चुनाव कार्यालय में जमा कराने को कहा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने एक अनधिकृत संचार समूह बनाकर अन्य बूथ लेवल अधिकारियों के बीच भ्रामक जानकारी प्रसारित की। अधिकारियों के अनुसार, इससे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चल रहे निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा, अपनी बूथ लेवल अधिकारी की ड्यूटी से बचने के उद्देश्य से मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 जमा करने की बात भी सामने आई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई : निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दौरान निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं करना गंभीर लापरवाही मानी जाती है। अधिकारियों ने कथित आचरण को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत कर्तव्य में लापरवाही के दायरे में माना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निलंबन आदेश की प्रतियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चंडीगढ़ प्रशासन, स्कूल शिक्षा निदेशक और संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को भेजी गई हैं।

संशोधित रूट से प्रभावित जमीन मालिकों से एनएचएआई ने मांगे सुझाव और आपत्तियां

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे को मंजूरी के बाद पंजाब में तेज हुआ जमीन अधिग्रहण का काम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के संशोधित मार्ग को मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में परियोजना से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। नकोदर से अमृतसर के बीच करीब 99 किलोमीटर लंबे हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। संशोधित योजना के कारण इस हिस्से के मार्ग में बदलाव किया गया है, जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी पड़ी है।

इस हिस्से में आने वाली जमीन के लिए नए सिरे से मुआवजा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की ओर से प्रभावित जमीन मालिकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। जमीन मालिकों को अधिग्रहण, जमीन के विवरण और प्रस्तावित मुआवजे से संबंधित अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। प्राप्त आपत्तियों और दावों की जांच के बाद नियमानुसार अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

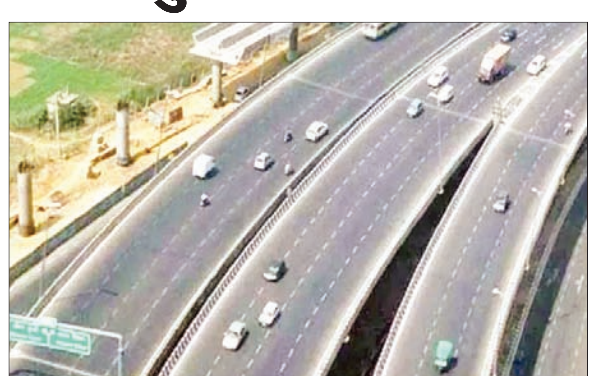

दिल्ली से कटरा तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 670 किलोमीटर है। परियोजना को अलग-अलग हिस्सों में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दिल्ली से पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है। पंजाब में नकोदर से अमृतसर के बीच का हिस्सा इस परियोजना का महत्वपूर्ण भाग माना जा रहा है। संशोधित मार्ग के तहत जिन क्षेत्रों की जमीन अब परियोजना में शामिल की गई है, वहां संबंधित प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की जा रही है।

जमीन मालिकों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका : अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल जमीन मालिक निर्धारित नियमों के अनुसार अपना दावा या एतराज दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जमीन के विवरण, अधिग्रहण की प्रक्रिया या प्रस्तावित मुआवजे को लेकर आपत्ति है तो वह संबंधित स्तर पर अपनी बात रख सकता है। एनएचएआइ की ओर से प्रभावित लोगों को जमीन और मुआवजे से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

जमीन मालिकों से जमीन के स्वामित्व और अन्य जरूरी विवरण से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलने के साथ अधिग्रहण प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निज्जर की हत्या पर आरोपों के बीच पम्मा और बराड़ आमने-सामने, विवाद हुआ तेज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। ब्रिटेन में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी परमजीत सिंह पम्मा ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को धमकी देते हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का हिसाब चुकाने की बात कही है। पम्मा ने एक ऑडियो संदेश में बराड़ पर आरोप लगाया कि भरोसा दिलाने के बाद उसने उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक की। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया है।

कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर बढ़ा विवाद, पम्मा ने बराड़ पर लगाए गंभीर आरोप

पम्मा ने बराड़ को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उसने निज्जर की हत्या का फैसला गलत तरीके से लिया और उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि यदि बराड़ मुकाबला करना चाहता है तो दिन और तारीख तय कर सामने आए। पम्मा ने दावा किया कि पिछले कई वर्षों में उसके खिलाफ हमले की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका।

निज्जर की हत्या को बताया गद्दारी : पम्मा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बराड़ पर तीखा हमला बोला। उसने कहा कि यदि बराड़ में हिम्मत थी तो निज्जर को सामने से चुनौती देनी चाहिए थी। पम्मा ने निज्जर को कौम के लिए काम करने वाला व्यक्ति बताते हुए उसकी हत्या को गलत करार दिया।

उसने दावा किया कि निज्जर के साथियों ने लंबे समय तक जेल में रहकर भी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके विपरीत उसने बराड़ और उसके साथियों पर लगातार ठिकाने बदलने का आरोप लगाया। पम्मा ने बराड़ को चेतावनी देते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

राहुल गांधी और राजा वड़िंग के समर्थन में पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर और वड़िंग के आदेशों पर कांग्रेस का चंडीगढ़ में जोरदार विरोध

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ अनुसूचित जाति आयोग की ओर से जारी गिरफ्तारी संबंधी आदेशों के विरोध में मंगलवार को पंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक खींचतान की स्थिति बनी रही। स्थिति को देखते हुए पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर बड़ी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस बल तैनात किया गया था।

प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका ने किया। सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और अनुसूचित जाति आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। इसके साथ ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित 'शुद्धिकरण' मामले में हुई कार्रवाई और राजा वड़िंग के खिलाफ जारी गिरफ्तारी आदेशों का भी विरोध किया गया।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और गिरफ्तारी संबंधी आदेश वापस लेने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और खींचतान हुई।

डॉ. राजकुमार वेरका सहित कार्यकर्ता हिरासत में : स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे डॉ. राजकुमार वेरका और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें सेक्टर-11 थाने ले गई। करीब आधे घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद वेरका ने अनुसूचित जाति आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

डॉ. वेरका ने आरोप लगाया कि आयोग बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहा है। उन्होंने राजा वड़िंग के खिलाफ जारी गिरफ्तारी आदेशों को पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना था कि मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन होने के बावजूद आयोग की ओर से इस तरह के आदेश जारी करना उचित नहीं है।

मध्य मार्ग पर यातायात प्रभावित : कांग्रेस के प्रदर्शन का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ के मध्य मार्ग पर करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कुछ समय के लिए मार्ग को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था बहाल कराई।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का राजनीतिक और कानूनी स्तर पर विरोध जारी रखेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ अपना रोष जताते हुए राहुल गांधी और राजा वड़िंग के मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करती रहेगी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की मांग की।

पंजाब के खाद्य विभाग में इंस्पेक्टरों को लैपटॉप यात्रा भत्ता और कार्यालय सुविधाओं से मिलेगी राहत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग में फील्ड पर तैनात इंस्पेक्टरों के कामकाज को अधिक सुविधाजनक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। विभाग ने इंस्पेक्टर कैडर के अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध करवाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों के दौरे के लिए यात्रा भत्ता देने का भी फैसला किया गया है। विभाग के इन फैसलों से फील्ड स्टाफ को काम के दौरान होने वाली व्यावहारिक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

इंस्पेक्टर खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग की जमीनी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। खरीद सीजन के दौरान उन्हें नियमित रूप से मंडियों और खरीद केंद्रों का निरीक्षण करना पड़ता है। इस दौरान किसानों, आढ़तियों और अन्य संबंधित लोगों से संपर्क कर खरीद प्रक्रिया की निगरानी करनी होती है। लैपटॉप मिलने से इंस्पेक्टर मौके पर ही विभागीय जानकारी दर्ज करने, जरूरी आंकड़ों का मिलान करने और संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा करने में सक्षम होंगे।

यात्रा भत्ता मिलने से फील्ड निरीक्षण के दौरान होने वाले खर्च को लेकर भी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इससे इंस्पेक्टर नियमित रूप से मंडियों का दौरा कर सकेंगे और खरीद व्यवस्था की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। विभाग का उद्देश्य फील्ड स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना है।

कार्यालयों के लिए मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस : फील्ड सुविधाओं के अलावा विभाग ने इंस्पेक्टरों के कार्यालयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउंस को भी मंजूरी दी है। इसके माध्यम से इंस्पेक्टर अपने कार्यालयों में जरूरी फर्नीचर और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकेंगे। इससे कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलने के साथ रोजमर्रा के विभागीय कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलेगी।

गरीबों के अनाज की सप्लाई पर रहेगी नजर : विभाग ने इंस्पेक्टरों को गरीब वर्ग के लिए आने वाले अनाज की सप्लाई पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि पात्र लोगों के लिए आने वाला अनाज हर स्थिति में उन्हीं तक पहुंचे। अनाज की व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लेने की बात कही गई है।

21 सितंबर से पेपरलेस होगी जम्मू-कश्मीर विधानसभा

डिजिटल व्यवस्था लागू होने से विधानसभा के कामकाज में कागजी प्रक्रिया खत्म होगी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी शरदकालीन सत्र 21 सितंबर, 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के साथ विधानसभा के कामकाज को पूरी तरह कागजरहित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब विधानसभा से जुड़े प्रश्नों, विधेयकों और अन्य विधायी कार्यों के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का इस्तेमाल किया जाएगा।

कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, सभी सरकारी विभागों को विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, विधेयक और अन्य जरूरी विधायी सामग्री केवल नेवा पोर्टल के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इससे विभागों और विधानसभा के बीच दस्तावेजों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी।

नेवा से होगा विधायी कामकाज।

रोजाना नेवा खातों की निगरानी के निर्देश: सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अपने नेवा खातों की प्रतिदिन निगरानी करने को कहा है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल पर आने वाले प्रश्नों और संबंधी कार्यों को नियमित रूप से देखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निपटारा सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर और अन्य विधायी कार्यों में अनावश्यक देरी को रोकना है। नई व्यवस्था के तहत विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब तैयार करने से लेकर विधेयकों और अन्य दस्तावेजों को भेजने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे कागज, छपाई और दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में लगने वाले समय और संसाधनों की बचत होने की उम्मीद है।

समय पर निपटाने होंगे विधायी कार्य: विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नेवा पोर्टल पर प्राप्त होने वाले सभी विधायी कार्यों पर समय रहते कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा के कामकाज को डिजिटल बनाने की यह पहल प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और तेज बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

डिजिटल व्यवस्था से विधायी कार्य होंगे तेज और पारदर्शी

नई व्यवस्था से विधानसभा से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। नेवा पोर्टल पर सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध रहने से अधिकारियों को सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। साथ ही प्रश्नों के उत्तर, विधेयकों और अन्य विधायी कार्यों के निपटारे की प्रक्रिया भी तेज होगी। विभागों को निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।

नेवा से सूचनाओं का आदान-प्रदान होगा आसान

नई व्यवस्था से विधानसभा के कामकाज में समय और संसाधनों की बचत होगी। कागजी दस्तावेजों की जरूरत कम होने से विभागों और विधानसभा के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान बनेगा। नेवा पर रिकॉर्ड उपलब्ध रहने से संबंधित अधिकारी जरूरत के अनुसार जानकारी तुरंत देख सकेंगे। इससे प्रश्नों के जवाब और विधेयकों से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय होने से कार्यों की निगरानी बेहतर होगी। अधिकारियों को पोर्टल पर मिलने वाले निर्देशों और कार्यों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

उपराज्यपाल सक्सेना ने 'लद्दाख बाइक वीक' के पहले संस्करण को दिखाई हरी झंडी

गलवान मोटरसाइकिल रैली में 11 पेशेवर राइडर पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों से गुजरेंगे

भारतेंदु संवाददाता, लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मोटरसाइकिलिंग और ऊंचाई वाले साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को पहले लद्दाख बाइक वीक का शुभारंभ किया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाइक वीक को हरी झंडी दिखाई। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य लद्दाख को केवल बाइक यात्रियों के गुजरने वाले क्षेत्र के बजाय साहसिक, खोज और अनुभव आधारित पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है।

उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख के ऊंचे पर्वत, दुर्गम रास्ते और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर-योग्य दर्रे इसे देश-विदेश के मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए आकर्षक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बाइक वीक के माध्यम से लद्दाख की प्राकृतिक खूबसूरती और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को व्यापक स्तर पर सामने लाया जा रहा है।

लद्दाख बाइक वीक से साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, जुटेंगे देश-विदेश के बाइक प्रेमी।

बाइक वीक का प्रमुख आकर्षण लद्दाख मोटरसाइकिल रैली है, जो एक से तीन सितंबर तक आयोजित की जा रही है। इसमें देशभर से 11 पेशेवर राइडर गलवान मोटरसाइकिल रैली में भाग लेंगे। राइडर पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरेंगे। इसे साहसिक यात्रा के साथ राष्ट्रीय एकता और खोज की भावना से जोड़ा गया है।

चार से छह सितंबर तक लेह के चुचोट में हिमालयन बेसकैंप आयोजित होगा। इसमें विभिन्न गतिविधियां, प्रदर्शन, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और सामुदायिक कार्यक्रम होंगे। आयोजकों को प्रतिदिन करीब 5,500 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, एक से सात सितंबर तक लेह बाजार में विंटेज मोटरसाइकिल प्रदर्शनी लगेगी। इसमें 15 चुनिंदा क्लासिक और पुरानी मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की जाएंगी।

न्यूज ब्रीफ

स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर श्रीनगर में डेली वेजर्स का प्रदर्शन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के सदस्यों ने मंगलवार को श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में स्थायी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फोरम के अध्यक्ष सज्जाद अहमद पर्रे ने कहा कि नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी को अपना वादा पूरा करते हुए जल्द रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। उन्होंने सरकार से डेली वेजर्स की लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान करने की अपील की। पर्रे ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिया था और अब उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर टैगोर हॉल में डेली वेजर्स के संघर्ष और परेशानियों पर आधारित 16 मिनट की फिल्म जारी की जाएगी। फोरम 10 सितंबर को एसके पार्क में भी विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।

सैनिक कॉलोनी सोसायटी की बैठक कोरम के अभाव में दूसरी बार रद्द

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। सैनिक कॉलोनी कोऑपरेटिव सोसायटी के सदस्यों की बैठक पर्याप्त कोरम पूरा नहीं होने के कारण लगातार दूसरी बार रद्द हो गई। बैठक में 1,420 सदस्यों की मौजूदगी अपेक्षित थी, लेकिन केवल 48 सदस्य ही पहुंचे। कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान सोसायटी की संयुक्त रजिस्ट्रार प्रीति शर्मा भी मौजूद रहीं। लगातार दूसरी बार बैठक रद्द होने से सदस्यों के बीच चर्चा तेज हो गई है। सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में सदस्यों और सोसायटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को सामने रखा।

रूपनगर में रातोंरात बिजली ट्रांसफार्मर हुआ चोरी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जानीपुर थाना क्षेत्र के रूपनगर इलाके में चोर रात के अंधेरे में मोहल्ले की बिजली आपूर्ति करने वाला ट्रांसफार्मर खोलकर ले गए। रात में बिजली गुल होने पर लोगों ने इसे सामान्य बिजली कट समझा और अपने घरों में इनवर्टर चला लिए। सुबह तक बिजली बहाल नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने ट्रांसफार्मर वाली जगह की जांच की, जहां वह गायब मिला। मोहल्लेवासियों ने बिजली विभाग के लाइनमैन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने जांच के बाद ट्रांसफार्मर चोरी होने की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

जम्मू में डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए साइनबोर्ड लगाने की पहल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू नगर निगम ने शहर की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर डोगरी भाषा के साइनबोर्ड लगाने की पहल शुरू की है। मुख्य मार्गों, चौराहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर ये साइनबोर्ड लगाए जा रहे हैं। **संस्था ने दिया सहयोग :** यह पहल सयाना नागरिक मदद सेवा संस्था के अनुरोध पर नगर निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव के मार्गदर्शन में शुरू हुई है। संस्था ने कई डोगरी साइनबोर्ड उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें नगर निगम उपयुक्त स्थानों पर स्थापित कर रहा है। **भाषा संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा :** सार्वजनिक स्थानों पर डोगरी भाषा के साइनबोर्ड लगने से जम्मू की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। साथ ही युवा पीढ़ी में अपनी मातृभाषा और स्थानीय विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। **दैनिक जीवन में डोगरी की मौजूदगी :** नगर निगम के संयुक्त आयुक्त कुलभूषण खजूरिया ने बताया कि यह प्रयास डोगरी को सार्वजनिक जीवन में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जम्मू की सांस्कृतिक पहचान और अधिक प्रभावी ढंग से सामने आएगी।

12,300 से 30 हजार स्टाइपेंड की मांग मेडिकल इंटर्न्स ने जारी रखी हड़ताल

मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न्स की हड़ताल, सरकार से आदेश जारी करने की मांग।

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न्स की स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुई हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों के इंटर्न्स ने काम से दूरी बनाकर अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया।

उनका कहना है कि जब तक सरकार स्टाइपेंड बढ़ाने का औपचारिक आदेश जारी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी इंटर्न्स वर्तमान में मिलने वाले करीब 12,300 रुपये के मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नियमित रूप से जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, इसलिए स्टाइपेंड में उचित बढ़ोतरी जरूरी है। इंटर्न्स ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती भी इंटर्न्स के बीच पहुंचीं और उनके आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों की जानकारी ली। इंटर्न्स का कहना है कि उनकी मांग लंबे समय से लंबित है और कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जा चुका है।

वैष्णो देवी धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब 66 .93 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

भारतेंदु संवाददाता, कटड़ा। तमाम दुश्वारियों और विशेषकर बरसात के मौसम में यात्रा में आ रही रुकावटों के बावजूद मां वैष्णो देवी के भक्तों का उत्साह बरकरार है। देशभर से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा पहुंचकर मां के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक 66.93 लाख श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 12.73 लाख अधिक है।

मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बढ़ता उत्साह कटड़ा के बाजारों और यात्रा मार्ग पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बारिश के कारण कई बार यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन मौसम की चुनौतियां भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकीं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार के साथ कटड़ा पहुंचकर पंजीकरण कराने के बाद भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आवश्यक

व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मौसम खराब होने पर यात्रा मार्ग की निगरानी बढ़ाई जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे कटड़ा में धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। होटल, दुकान और अन्य कारोबारी गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले महीनों में भी यात्रा में तेजी रहने की उम्मीद है। नवरात्र और अन्य प्रमुख अवसरों पर मां के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है।

सांबा-मानसर सड़क पर फिर गिरीं पस्सियां, घंटों बाद खुली सिंगल लेन

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। सांबा-मानसर सड़क मार्ग पर लगातार तीसरे दिन भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित रहा। सोमवार देर रात बिंदु दा बेड़ा के पास अचानक पहाड़ी से पस्सियां और मलबा सड़क पर आ गिरा। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और लोगों को मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ा। मलबा गिरने की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और सीमा सड़क संगठन की मशीनरी सक्रिय हुई। मंगलवार सुबह सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया।

◆ तीसरे दिन भी भूस्खलन

मार्ग पर लगातार गिर रहे पत्थरों और मलबे के कारण राहत कार्य में भी सावधानी बरतनी पड़ी। कई घंटे की मशक्कत के बाद करीब सुबह 11:30 बजे सड़क को सिंगल लेन यातायात के लिए खोल दिया गया। इसके बाद फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। सड़क मार्ग पर बार-बार हो रहे भूस्खलन को देखते हुए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांबा-मानसर मार्ग पर यात्रा शुरू करने से पहले यातायात की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर हासिल करें। विशेषकर बारिश के दौरान इस मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले तीन दिनों से मार्ग पर रुक-रुककर पस्सियां गिरने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। यात्रियों को लंबे समय तक जाम में फंसना पड़ रहा है।

पहलगाम हमले के बाद हेल्पलाइन बनी जम्मू-कश्मीरवासियों की मददगार कड़ी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू की गई जम्मू-कश्मीर सरकार की 24 घंटे सक्रिय टोल-फ्री हेल्पलाइन अब प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण सहायता केंद्र बन गई है। 1800-8900-166 नंबर के माध्यम से देश और विदेश में मुश्किल परिस्थितियों में फंसे छात्रों, कामगारों और अन्य लोगों को प्रशासन से सीधे मदद मिल रही है।

25 अप्रैल 2025 को शुरू हुई सेवा : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को यह हेल्पलाइन शुरू की थी। पहलगाम हमले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों और नागरिकों के साथ कथित धमकी, उत्पीड़न और हमलों की खबरों के बीच परिवारों की चिंता बढ़ गई थी। ऐसे समय में मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल सहायता और विभिन्न राज्यों के प्रशासन के साथ समन्वय के लिए चौबीसों घंटे नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की।

छात्रों और कामगारों को मदद : समय के साथ हेल्पलाइन का दायरा बढ़ता गया। इसके माध्यम से छात्रों को सहायता देने के अलावा आपात यात्रा की व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन से संपर्क और जनसेवा से जुड़े मामलों में मदद उपलब्ध कराई जा रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए यह प्रशासन तक अपनी समस्या पहुंचाने का सीधा माध्यम बन गया है।

ईरान-इजरायल संघर्ष में भी मदद : ईरान-इजरायल संघर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर के कई छात्र तनावपूर्ण परिस्थितियों में फंस गए थे। उस दौरान हेल्पलाइन ने छात्रों और उनके परिवारों के बीच संपर्क बनाए रखने तथा संबंधित प्रशासन तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे संकट की स्थिति में छात्रों की सुरक्षा और सहायता के लिए समन्वय करने में मदद मिली। अधिकारियों के अनुसार, एक साल से अधिक समय में हेल्पलाइन पर हजारों कॉल और संदेश प्राप्त हुए हैं।

सुरक्षा में सुधार के बीच घाटी बंद, स्थानीय कारोबारियों ने खोलने की उठाई मांग

बंगस घाटी खोलने की मांग हुई तेज, पर्यटन कारोबार और स्थानीय आजीविका पर गहराया गंभीर संकट

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की प्रसिद्ध बंगस घाटी में सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद पर्यटन गतिविधियां अभी शुरू नहीं हो सकी हैं। घाटी के बंद रहने से स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सुरक्षा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर बंगस घाटी को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने की अपील की है।

सुरक्षा में सुधार के बावजूद बंद : स्थानीय लोगों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई पर्यटन और मनोरंजन स्थलों को बंद किया गया था। इनमें से कई स्थानों पर स्थिति की समीक्षा के बाद पर्यटन गतिविधियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बंगस घाटी अभी भी बंद है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने के बावजूद घाटी को लंबे समय तक बंद रखना स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है।

लंबे समय से बंद बंगस घाटी पर प्रशासन के फैसले का इंतजार।

उपराज्यपाल से पुनर्विचार की अपील

स्थानीय निवासियों और पर्यटन कारोबारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बंगस घाटी की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का स्वयं आकलन करने और इसे फिर से खोलने पर विचार करने की अपील की है। उनका कहना है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो पर्यटन गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका, निवेश और क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को राहत मिल सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंगस घाटी को दोबारा खोलने से केवल पर्यटकों की आवाजाही ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि होमस्टे, परिवहन, स्थानीय बाजार और अन्य छोटे कारोबारों को भी फायदा होगा।

सेब ढुलाई में रेलवे पर जोर, हाईवे जाम से मिलेगी बागवानों को राहत

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में सेब सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन ने बागवानी उपज की ढुलाई व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। सेब की फसल को हाईवे जाम, भूस्खलन और खराब मौसम से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता कम कर रेलवे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। फिलहाल कश्मीर से बाहर जाने वाली 90 प्रतिशत से अधिक फल उपज सड़क मार्ग से भेजी जाती है।

मंडलायुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने बागवानी उपज की रेलवे से ढुलाई को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अनंतनाग की जबलीपोरा मंडी से अधिक से अधिक फल रेलवे के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए। सभी उपायुक्तों को बागवानों, व्यापारियों और फल संगठनों के साथ समन्वय कर रेलवे से निश्चित मात्रा में उपज भेजने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है।

प्रशासन रेलवे माल ढुलाई को अपेक्षाकृत किफायती और प्रभावी विकल्प मान रहा है। इससे परिवहन लागत कम होने के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों का दबाव भी घटेगा। रेलवे के रोल-ऑन रोल-ऑफ व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। इसके तहत फल से लदे

◆ रेलवे से सेब ढुलाई बढ़ाने की पहल, जाम और खराब मौसम से नुकसान घटेगा।

◆ रेल परिवहन से बागवानों की उपज समय पर बाजार तक पहुंचेगी।

ट्रकों को सीधे रेलवे रैक पर चढ़ाकर लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है।

प्रशासन ने सड़क मार्ग से भेजी जाने वाली फल खेप में ओवरलोडिंग पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्धारित भार सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी।

जमीन धोखाधड़ी में दिवंगत पूर्व पटवारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में दिवंगत पूर्व पटवारी मुश्ताक अहमद मलिक के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोप है कि जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा करने और श्रीनगर नगर निगम से भवन निर्माण की अनुमति हासिल करने का प्रयास किया गया था। ईओडब्ल्यू कश्मीर के प्रवक्ता के अनुसार, इस मामले में वर्ष 2016 में दर्ज प्राथमिकी संख्या 08/2016 के तहत श्रीनगर के उप न्यायाधीश की अदालत में आरोपपत्र पेश किया गया। मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 511, 167, 471 और 120-बी के तहत कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपितों ने कथित तौर पर आपसी मिलीभगत कर जाली दस्तावेज तैयार किए और उनका इस्तेमाल जमीन संबंधी दावे को मजबूत करने के लिए किया। इसके अलावा भवन निर्माण की अनुमति लेने के लिए जरूरी तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी।

परेड और एसएमजीएस अस्पताल में बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाएं होंगी विकसित

जम्मू में पार्किंग के लिए 49 करोड़ की दो परियोजनाएं मंजूर

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर में बढ़ती यातायात और पार्किंग समस्या को कम करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने करीब 49.34 करोड़ रुपये की लागत वाली दो प्रमुख पार्किंग परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने यह मंजूरी वित्तीय वर्ष 2026-27 के पूंजीगत व्यय बजट के तहत जम्मू नगर निगम को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए दी है।

सरकारी आदेश संख्या 184-जेके (एचयूडी) 2026 के अनुसार, परेड में 24.06 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर बनाया जाएगा। यह परियोजना शहर के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में लंबे समय से बनी पार्किंग की समस्या को दूर करने में मदद करेगी। परिसर में आधुनिक पार्किंग सुविधाओं के साथ आवश्यक नागरिक और उपयोगिता संबंधी कार्य भी किए जाएंगे।

दूसरी परियोजना के तहत शालीमार स्थित एसएमजीएस अस्पताल में 25.27 करोड़ रुपये की लागत से बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी।

कश्मीरी विस्थापितों के राशन वितरण पर प्रशासन ने कसी कमर

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राशन वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राजेश कुमार शवन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डा. अरविंद करवानि समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में विस्थापित परिवारों की ई-केवाईसी, राशन वितरण, तीन माह का अग्रिम राशन, खाद्यान्न के उठान और उपलब्धता समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को उनके निर्धारित हक के अनुसार समय पर और बिना परेशानी राशन उपलब्ध कराया जाए। राशन की आपूर्ति में किसी तरह की देरी न हो, इसके

◆ ई-केवाईसी, अग्रिम राशन और भ्रामक ज्वेलरी विज्ञापनों पर सख्ती

लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

एक ग्राम गोल्ड ज्वेलरी के विज्ञापनों पर सख्ती : वहीं, निदेशक ने इमिटेशन ज्वेलरी के नाम पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। एक ग्राम गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और प्रचार सामग्री पर चिंता जताई गई।

आधुनिकता की तेज दौड़ में धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है ग्रामीण संस्कृति और परंपराएं

विक्रम वर्मा
प्रवक्ता अंग्रेजी, गेहरा, जिला चंबा

कभी-कभी अनायास ही बदलते परिवेश और आधुनिक जीवन व्यवहार, मानवीय संवेदनशीलता और पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में हो रहे परिवर्तन सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आगामी कुछ वर्षों में जीवन का अर्थ और अस्तित्व क्या होगा। पर्यावरण और प्रकृति का बदलता स्वरूप, जीवनशैली और व्यवहार के बदलते पैमाने ,मानवीय संवेदना में निरंतर गिरावट निस्संदेह आज यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भावी पीढ़ी का जीवन और जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी।

हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहां की पहचान केवल ऊंचे पर्वतों, बर्फ से ढकी चोटियों और प्राकृतिक सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं, भाईचारे और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली से रही है। कभी हिमाचल के गांव केवल रहने का स्थान नहीं होते थे, बल्कि वे संस्कृति, संस्कार और सामूहिक जीवन के जीवंत केंद्र हुआ करते थे। आज आधुनिकता की तेज रफ्तार में वही ग्रामीण संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त होती दिखाई दे रही है। यह परिवर्तन केवल जीवनशैली का बदलाव नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से दूर होने की चेतावनी भी है।

एक समय था जब हिमाचल के गांवों में जीवन प्रकृति की लय के साथ चलता था। सुबह का आरंभ मंदिर की घंटियों, पशुओं की आवाज़ों और चश्मों के निर्मल जल से होता था। प्राकृतिक चश्मों का पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं था, बल्कि वह जीवन की शुद्धता और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक था। आज वही चश्मे सूख रहे हैं या उपेक्षित पड़े हैं। पाइपलाइन और बोतलबंद पानी ने सुविधा तो दी, पर प्रकृति से हमारा रिश्ता कमजोर कर दिया। ग्रामीण संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान थी — भाईचारा और सामूहिकता। किसी के घर शादी हो, निर्माण कार्य हो या कोई संकट — पूरा गांव एक परिवार बन जाता था। 'सेवा' और 'सहयोग' शब्द व्यवहार में दिखाई देते थे। आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के बजाय कई बार अलग-थलग कर दिया है। पड़ोसी का हाल पूछने की जगह लोग स्क्रीन पर व्यस्त रहते हैं।

पहले जहां चौपालों में बैठकर बुजुर्ग जीवन अनुभव साझा करते थे, आज वे परंपराएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। हिमाचल की लोक संस्कृति का सबसे सुंदर पक्ष उसके तीज-त्योहार और लोक उत्सव थे। फागली, लोहड़ी, बैसाखी, सैर, और स्थानीय देव मेलों में पूरा गांव एकत्र होता था। लोकगीतों की धुन, नाटी नृत्य की ताल और पारंपरिक वेशभूषा में झलकती सांस्कृतिक पहचान लोगों को जोड़ती थी। आज त्योहार औपचारिकता बनते जा रहे हैं। आधुनिक मनोरंजन और व्यस्त जीवनशैली ने सामूहिक उत्सवों की आत्मीयता को कम कर दिया है। त्योहारों की खुशी अब सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित होती जा रही है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भोजन और जीवनशैली में आया है।

पहले ग्रामीण जीवन में स्थानीय अनाज — मक्की, जौ, मंडुवा, राजमा और देसी सब्जियां प्रमुख थीं। ये केवल भोजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का आधार थे। आज फास्ट फूड और बाजार पर निर्भरता बढ़ने से पारंपरिक खानपान पीछे छूट रहा है। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आधुनिकता स्वयं में गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम आधुनिकता अपनाते हुए अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। यदि संस्कृति समाप्त हो जाए तो विकास केवल भौतिक रह जाता है, उसमें आत्मा नहीं बचती। समय आ गया है कि हम आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को भी थामे रखें। फिर से चश्मों का पानी बहे, चौपालों में हंसी गूंजे, त्योहारों में सामूहिक नृत्य हो और गांव फिर से परिवार बन जाएं — यही हिमाचल की आत्मा का पुनर्जागरण होगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

कुंवारेपन का बढ़ता सन्नाटा : आधुनिकता की कीमत या समाज के लिए चेतावनी

सतीश शर्मा, समाजसेवी
पंचरुखी, जिला कांगड़ा

आज का समाज आधुनिकता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां व्यक्तिगत उपलब्धियों को सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाने लगा है। शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और बेहतर जीवनशैली ने युवाओं को अपने भविष्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर दिया है। यह बदलाव निश्चित रूप से सकारात्मक है, लेकिन इसके साथ सामाजिक और पारिवारिक जीवन में पैदा हो रही दूरियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से विवाह और परिवार को लेकर युवा पीढ़ी की बदलती सोच ने समाज की पारंपरिक संरचना को प्रभावित किया है। आज बड़ी संख्या में युवा, खासकर शिक्षित वर्ग, विवाह को जीवन की अनिवार्यता के बजाय व्यक्तिगत निर्णय के रूप में देखने लगे हैं। कई युवा पहले अपने करियर को मजबूत करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह के बारे में सोचते हैं। यह सोच व्यक्ति की स्वतंत्रता और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके व्यापक सामाजिक परिणामों पर भी गंभीर चर्चा जरूरी है।

आज की युवा पीढ़ी में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। बेटियां और बेटे दोनों अपने करियर तथा आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता देती है और उसे जीवन में अधिक स्वतंत्र बनाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आर्थिक सफलता को जीवन की पूर्ण उपलब्धि मान लिया जाता है और परिवार, रिश्ते तथा भावनात्मक जुड़ाव को पीछे छोड़ दिया जाता है। नौकरी का अच्छा वेतन, बड़ा पद या आकर्षक आर्थिक पैकेज निश्चित रूप से जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन वह जीवन की संपूर्ण संतुष्टि की गारंटी नहीं देता। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। आज अच्छी नौकरी और ऊंचा वेतन हो सकता है, लेकिन भविष्य में आर्थिक स्थिति बदल सकती है। इसके विपरीत परिवार और रिश्तों से मिलने वाला भावनात्मक सहयोग कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए मजबूत आधार बन सकता है। इसलिए जीवन के फैसलों को केवल आर्थिक लाभ के आधार पर देखना उचित नहीं है।

विवाह की बढ़ती उम्र भी समाज में हो रहे इस बदलाव का महत्वपूर्ण संकेत है। अनेक युवा पहले शिक्षा पूरी करने, नौकरी हासिल करने और करियर को स्थिर करने में कई वर्ष लगा देते हैं। इसके बाद विवाह को लेकर निर्णय लिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और करियर की प्राथमिकता के कारण विवाह को टालना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब यह प्रवृत्ति व्यापक सामाजिक बदलाव का रूप लेने लगे तो उसके परिणामों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। देर से विवाह के कारण अविवाहित युवाओं की संख्या बढ़ सकती है, परिवारों का आकार छोटा हो सकता है और जन्मदर में कमी आ सकती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं है, बल्कि बदलती सामाजिक संरचना का हिस्सा है। परिवारों के छोटे होने के साथ बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों के पालन-पोषण और सामाजिक सहयोग की पारंपरिक व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

इस बदलाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू मानसिक और भावनात्मक जीवन है। तेज प्रतिस्पर्धा, लंबे कामकाजी घंटे, करियर की दौड़ और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच व्यक्ति के लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। अकेले रहने की आदत कई बार स्वतंत्रता का प्रतीक लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव से दूर रहना अकेलेपन को बढ़ा सकता है। परिवार और रिश्तों का महत्व केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। कठिन समय में किसी का साथ मिलना, अपनी भावनाएं साझा करना और अपनापन महसूस करना भी स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

मोदी की मध्य एशिया यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान यात्रा को महज कूटनीतिक यात्राओं की श्रृंखला के रूप में देखना उचित नहीं होगा। बदलती वैश्विक व्यवस्था में मध्य एशिया भारत की विदेश नीति का ऐसा महत्वपूर्ण मोर्चा बनकर उभर रहा है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, सामरिक हित और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उज्बेकिस्तान के साथ संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाना इसी बदलती रणनीति का स्पष्ट संकेत है। भारत अब मध्य एशिया को केवल अपने दूर के पड़ोसी के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इस क्षेत्र के साथ दीर्घकालिक और बहुआयामी सहयोग की संभावनाओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

प्रधानमंत्री की यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति को लेकर बनी सहमति को माना जा सकता है। भारत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए परमाणु ईंधन की सुनिश्चित आपूर्ति बेहद जरूरी है। उज्बेकिस्तान के साथ संभावित समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी दीर्घकालिक योजनाओं को भी आधार प्रदान कर सकता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भरोसेमंद स्रोतों से ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता भारत के लिए विशेष महत्व रखती है। इसलिए मध्य एशिया के संसाधन संपन्न देशों के साथ ऊर्जा सहयोग आने वाले समय में भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

व्यापार के मोर्चे पर भी भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को पांच अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान आंकड़ों की तुलना में यह लक्ष्य भले ही बहुत बड़ा न दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे छिपी संभावनाएं व्यापक हैं। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग भारत को मध्य एशिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ नई साझेदारी विकसित करने का अवसर देता है। भारत की डिजिटल क्षमता और तकनीकी कौशल तथा मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधन एक-दूसरे के पूरक साबित हो सकते हैं।

भारत की डिजिटल क्षमता और तकनीकी कौशल का इस्तेमाल मध्य एशिया के प्राकृतिक संसाधनों के साथ जोड़कर व्यापक आर्थिक सहयोग विकसित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता बढ़ रही है, जबकि भारत को अपनी औद्योगिक और तकनीकी जरूरतों के लिए ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष, दवा उद्योग, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी में भी दोनों पक्षों के बीच सहयोग की गुंजाइश है। इससे भारत की आर्थिक पहुंच बढ़ेगी और मध्य एशियाई देशों को भी भारतीय तकनीक तथा सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इस तरह आर्थिक साझेदारी केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों पक्षों की रणनीतिक निर्भरता को भी मजबूत करेगी।

इस पूरी कवायद का एक महत्वपूर्ण पक्ष चीन की बढ़ती मौजूदगी भी है। चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी आर्थिक मौजूदगी काफी मजबूत की है। भारत को चीन की नकल करने के बजाय अपनी विशिष्ट ताकत के आधार पर क्षेत्र में विकल्प प्रस्तुत करना होगा। भारत की विश्वसनीयता, लोकतांत्रिक छवि, डिजिटल तकनीक, दवा उद्योग और मानव संसाधन उसे मध्य एशियाई देशों के लिए एक अलग तरह का साझेदार बना सकते हैं। यही कारण है कि भारत की सक्रियता को केवल आर्थिक विस्तार के रूप में नहीं बल्कि क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन जैसे क्षेत्रीय मंच भारत को व्यापक सहयोग का अवसर देते हैं। आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ साझा प्रयास भारत की सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अफगानिस्तान की अस्थिरता और उससे जुड़े आतंकी नेटवर्क मध्य एशिया से लेकर भारत तक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। ऐसे में मध्य एशियाई देशों के साथ खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, सीमा पार आतंकवाद से मुकाबले और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। भारत इस क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ साझा और प्रभावी रणनीति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हालांकि सबसे बड़ी चुनौती संपर्क मार्गों की है। मध्य एशिया तक भारत की सीधी और सुगम पहुंच सीमित है। चाबहार बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और अन्य संपर्क परियोजनाओं को गति दिए बिना भारत के लिए इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार आसान नहीं होगा। बेहतर संपर्क केवल माल ढुलाई को सुगम नहीं बनाएगा, बल्कि भारत और मध्य एशिया के बीच लोगों, सेवाओं और विचारों का आदान-प्रदान भी बढ़ाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री की मध्य एशिया यात्रा को केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसका वास्तविक महत्व इस बात में है कि भारत इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को ठोस आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

-शिवांश धाकड़

कविता

अकलियत की कीमत

डॉ. कौमार्या मनोज

जीवन में अपने यारों का अभाव भी जरूरी है,
कभी अकेले चलना और खुद से मिलना जरूरी है।
जीवन अगर है जीना तो ठहराव भी जरूरी है,
भागती हुई राहों में कुछ पल विश्राम भी जरूरी है।
जब इंसान नहीं समझता अक्लियत की कीमत,
तब वक्त सिखाता है अनुभव की असली कीमत।
ठोकर लगती है तो गिरना कोई हार नहीं,
गिरकर फिर उठ जाना ही जीवन की हार नहीं।
कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं,
ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनों को भूल जाते हैं।
लेकिन वक्त बदलता है और रिश्ते फिर मिलते हैं,
जो दूर चले जाते हैं वे कभी पास भी मिलते हैं।
कब तक कोई आकाश में बनकर रहे परिंदा,
उड़ते-उड़ते थकता है हर एक मुसाफिर जिंदा।
थककर जब वह धरती की ओर लौट आता है,
तभी उसे अपनी जड़ों का एहसास हो पाता है।
इसलिए लोगों से मिलना और रिश्ते संभालना सीख,
अपनेपन की भाषा बोल और दिल से रहना सीख।
तू जमीन का आदमी है, जमीन पर रहना सीख,
सफलता मिले तो भी विनम्रता से चलना सीख।
जीवन की असली सुंदरता ऊंचाई में नहीं,
बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने में कहीं है।

क्या लोकतांत्रिक सरकारों के पीछे काम करते हैं वैश्विक प्रभावशाली नेटवर्क?

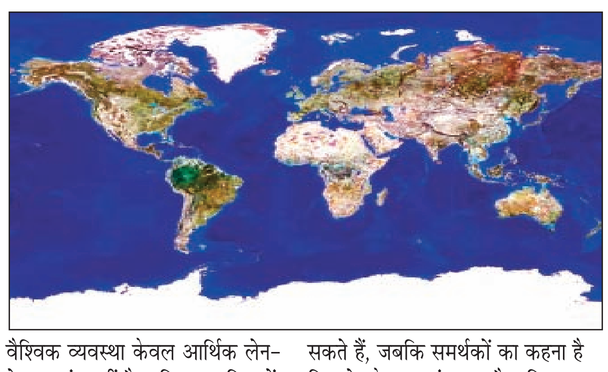

कैलाश चंद्र
सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्तंभकार

आधुनिक विश्व-राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते समय यह प्रश्न बार-बार उठता है कि क्या सत्ता केवल निर्वाचित सरकारों के हाथों में होती है या उसके पीछे ऐसे प्रभाव-समूह भी सक्रिय रहते हैं जिनकी शक्ति औपचारिक संस्थाओं से कहीं अधिक व्यापक होती है।

पिछले कुछ दशकों में अनेक शोधकर्ताओं, पत्रकारों और विश्लेषकों ने इस विषय को 'ग्लोबल एलीट नेटवर्क' या 'पावर स्ट्रक्चर' के रूप में समझने का प्रयास किया है। इन नेटवर्कों में वित्तीय संस्थाएं, वैश्विक मंच, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रौद्योगिकी कंपनियां, दान संस्थाएं और कभी-कभी खुफिया एजेंसियों से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों का परस्पर संबंध देखने को मिलता है। इस संदर्भ में कई संस्थाएं और घटनाएं चर्चा के केंद्र में रहती हैं जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस सम्मेलन, बिल्डरबर्ग ग्रुप की बंद बैठकें, वैश्विक वित्तीय संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक तथा बड़ी तकनीकी कंपनियां जिनका सामूहिक प्रभाव 'बिग टेक' के रूप में जाना जाता है। इन संस्थाओं की भूमिका को समझने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वैश्विक व्यवस्था केवल आर्थिक लेन-देन का तंत्र नहीं है, बल्कि यह विचारों, नीति-निर्माण और प्रभाव के बहुस्तरीय नेटवर्क से निर्मित होती है।

उदाहरण के लिए, दावोस में आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन विश्वभर के राजनीतिक नेताओं, कॉरपोरेट प्रमुखों, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। यहां औपचारिक निर्णय नहीं लिए जाते, किंतु नीति-निर्माण की दिशा, आर्थिक प्राथमिकताएं और वैश्विक सहयोग की रूपरेखा पर चर्चा होती है। इसी प्रकार बिल्डरबर्ग जैसी बैठकें लंबे समय से इस कारण चर्चा में रहती हैं कि वे अत्यंत सीमित और बंद प्रकृति की होती हैं, जहां प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच विचार-विमर्श होता है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे मंच वैश्विक नीति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि वे केवल संवाद और विचार-विनिमय के मंच हैं। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का निर्माण भी इसी प्रकार के ऐतिहासिक और संस्थागत नेटवर्क से जुड़ा है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बने ब्रेटन वुड्स ढांचे ने अंतरराष्ट्रीय वित्त को एक नई संरचना दी।

आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, पुनर्निर्माण और विकास को प्रोत्साहित करना था। साथ ही, केंद्रीय बैंकों का नेटवर्क जैसे विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक मुद्रा नीति और वित्तीय स्थिरता के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

इतिहास में मेयर एम्शेल रोथ्सचाइल्ड और जॉन डी. रॉकफेलर जैसे वित्तीय परिवारों ने वैश्विक वित्त और परोपकार के माध्यम से लंबा प्रभाव छोड़ा। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक जटिल है, लेकिन इन नेटवर्क का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि आधुनिक वित्तीय ढांचा कैसे विकसित हुआ। जेफ्री एपस्टीन प्रकरण ने वैश्विक सामाजिक और वित्तीय नेटवर्क पर ध्यान आकर्षित किया। एपस्टीन के अपराध और उसके सामाजिक संबंधों ने यह प्रश्न उठाया कि वैश्विक अभिजात वर्ग के नेटवर्क किस प्रकार कार्य करते हैं और कितने पारदर्शी हैं। हालांकि कई दावे विवादास्पद हैं, यह स्पष्ट है कि आधुनिक विश्व-राजनीति बहुस्तरीय शक्ति संरचना पर आधारित है, जिसमें सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वित्तीय नेटवर्क, कॉरपोरेट पूंजी और प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

भारतीय क्रिकेट का तेज सितारा

ईशांत शर्मा
जन्म : 2 सितंबर 1988

ईशांत शर्मा का जन्म 2 सितंबर 1988 को हुआ। करीब छह फीट चार इंच लंबे ईशांत दाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व टेस्ट, एकदिवसीय और ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में किया। अपनी लंबाई, उछाल और गेंद को सही दिशा में रखने की क्षमता के कारण वह लंबे समय तक भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे।

ईशांत ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत घरेलू क्रिकेट से की और दिल्ली की टीम का प्रतिनिधित्व किया। युवा स्तर पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वर्ष 2006 में वह भारत की अंडर-19 टीम के साथ इंग्लैंड और बाद में पाकिस्तान के दौरे पर गए। इन दौरों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ईशांत के प्रदर्शन ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। उनकी तेज और अनुशासित गेंदबाजी से प्रभावित होकर इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 9.5 लाख अमेरिकी डॉलर की बोली में खरीदा। उस समय यह प्रतियोगिता में किसी गेंदबाज के लिए सबसे बड़ी बोली थी। इसके बाद ईशांत ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार अपनी जगह मजबूत की।

ईशांत के करियर की बड़ी उपलब्धियों में 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करना शामिल है। वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल रहे। वर्ष 2013 में वह उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। फरवरी 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने अपने करियर के 300 टेस्ट विकेट पूरे किए। यह उपलब्धि उनके लंबे और सफल टेस्ट करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव रही।

ईशांत को कई मौकों पर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिना गया। उनकी गेंदबाजी में गति के साथ-साथ सटीकता और अनुशासन दिखाई देता रहा। वह कई बार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से भी गेंदबाजी कर चुके हैं।

आधुनिक जीवनशैली के बीच किन्नौरी महिलाओं के सामने संस्कृति और परंपरा बचाने की चुनौती

डॉ. सपना कामटेस
स्वतंत्र लेखिका

समाज के दो महत्वपूर्ण अंग स्त्री और पुरुष हैं और दोनों की समान भागीदारी के बिना किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में स्त्री की सामाजिक स्थिति हमेशा से विशेष रही है। यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। किन्नौर की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, सामुदायिक जीवन और लोक परंपराओं ने यहां महिलाओं की भूमिका को दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अलग स्वरूप दिया है। परिवार की जिम्मेदारियों से लेकर कृषि कार्य, सामाजिक आयोजनों और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण तक किन्नौरी महिलाओं ने सदियों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि बदलते समय के साथ उनकी भूमिका में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शिक्षा, रोजगार, तकनीक और आधुनिक जीवनशैली ने किन्नौरी महिलाओं को घर की पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनाने का अवसर दिया है।

किन्नौर में लंबे समय से महिला परिवार की धुरी रही है। कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में जीवन आसान नहीं रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद महिलाओं ने घर संभालने के साथ खेतों में काम किया, पशुपालन किया और परिवार की आर्थिक गतिविधियों में योगदान दिया। ग्रामीण जीवन में महिला केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थी बल्कि वह परिवार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण सहभागी थी। बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा और कृषि कार्यों के बीच भी शिक्षा के प्रति महिलाओं की आकांक्षा दिखाई देती रही है। पुराने समय में संसाधनों की कमी के कारण कई लड़कियों के लिए नियमित शिक्षा प्राप्त करना कठिन था। दिनभर घरेलू और कृषि कार्य करने के बाद भी कुछ लड़कियां रात्रि विद्यालयों के माध्यम से पढ़ाई जारी रखती थीं। यह उस दृढ़ इच्छा और संघर्ष का उदाहरण है जिसके बल पर किन्नौर की महिलाओं ने आगे बढ़ने का रास्ता बनाया।

किन्नौरी समाज की एक विशेषता विवाह और पारिवारिक व्यवस्था को लेकर भी रही है। यहां लड़की के विवाह को लेकर केवल उसके माता-पिता की चिंता ही महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी। कई पारंपरिक व्यवस्थाओं में विवाह का निर्णय सामुदायिक और पारिवारिक सहमति से जुड़ा रहता था। दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव भी कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में सीमित रहा है। विवाह के बाद लड़की का ससुराल ही उसका एकमात्र सामाजिक आधार हो, ऐसा भी हमेशा आवश्यक नहीं माना गया। यदि कोई महिला विवाह न करने का निर्णय लेती थी तो उसे अपने माता-पिता के साथ सम्मानपूर्वक रहने का अवसर मिलता था। आवश्यकता पड़ने पर माता-पिता अपनी बेटी को रहने के लिए स्थान और आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराते थे। यह व्यवस्था महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती थी।

किन्नौर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। स्थानीय देवी-देवताओं से जुड़ी मान्यताओं में महिलाओं को विशेष सम्मान प्राप्त रहा है। कई अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक निर्णयों में महिलाओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। लोक मान्यताओं में ऐसी धारणाएं भी मिलती हैं जहां देवी-देवताओं को प्रसन्न करने या किसी धार्मिक निर्णय को स्वीकार कराने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण समझी जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि किन्नौरी समाज में महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा केवल परिवार तक सीमित नहीं रही बल्कि धार्मिक और सामुदायिक जीवन में भी उसका प्रभाव रहा है।

समय के साथ शिक्षा ने किन्नौरी महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किया है। आज लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार हासिल कर रही हैं। वे शिक्षक, अधिकारी, चिकित्सक, उद्यमी और विभिन्न पेशों में अपनी पहचान बना रही हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े फैसलों में अधिक स्वतंत्र बनाया है। अब महिला की पहचान केवल किसी परिवार की बेटी, पत्नी या मां के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और पेशेवर के रूप में भी स्थापित हो रही है। आर्थिक मजबूती के साथ महिलाओं में अपने अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। विवाह, करियर और जीवनशैली से जुड़े फैसलों में उनकी अपनी राय को महत्व मिल रहा है।

हालांकि आधुनिकता के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। शहरों से बढ़ता संपर्क, सामाजिक माध्यमों का विस्तार और बदलती जीवनशैली ने किन्नौर की महिलाओं के सोचने और रहने के तरीके को प्रभावित किया है। यह परिवर्तन कई मायनों में सकारात्मक है, लेकिन इसके कारण पारंपरिक संस्कृति और लोक जीवन से दूरी बढ़ने की चिंता भी सामने आती है। किन्नौर की पहचान उसकी भाषा, वेशभूषा, लोकगीत, नृत्य, धार्मिक परंपराओं, त्योहारों और सामुदायिक जीवन से जुड़ी है। यदि नई पीढ़ी इन परंपराओं से पूरी तरह दूर हो जाती है तो सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ सकती है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ उनकी सांस्कृतिक भूमिका को भी मजबूत करना जरूरी है। वास्तव में आधुनिकता और परंपरा को एक-दूसरे का विरोधी मानना उचित नहीं होगा।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

रिंकू सिंह राही फिर सुर्खियों में आउटसोर्सिंग में भ्रष्टाचार का आरोप

एजेंसी, जालौन

उरई सदर में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात रिंकू सिंह राही एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने जालौन कलेक्ट्रेट में वाहन आउटसोर्सिंग में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए श्रमायुक्त और परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा है। अधिकारी ने पत्र को सोमवार देर रात सामाजिक मंच 'एक्स' पर भी साझा किया। राही ने अपनी पोस्ट में कहा कि भ्रष्टाचार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने लिखा कि जहां देखो, वहीं भ्रष्टाचार दिखाई देता है। उन्होंने जालौन कलेक्ट्रेट में आउटसोर्स के माध्यम से मिली गाड़ी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया।

बताया गया है कि रिंकू सिंह राही पहले भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने बिना काम के वेतन लेना नियमों के विपरीत बताते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इसके बाद भी वह प्रशासनिक व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखते रहे हैं। इस बार उन्होंने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर वाहन आउटसोर्सिंग व्यवस्था की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोक पाना संभव न हो, लेकिन उसे उजागर कर रिकॉर्ड पर जरूर लाया जा सकता है। राही के आरोपों के बाद अब संबंधित विभागों की ओर से मामले की जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी। फिलहाल उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर विभागीय स्तर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में दस्तावेजों और आउटसोर्सिंग प्रक्रिया की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि या खारिज होने के बाद ही मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होगी।

न्यूज ब्रीफ

हमीरपुर में बारिश का कहर, सैकड़ों मकान ढहे; फसलों को भी भारी नुकसान

एजेंसी, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। बारिश के कारण सैकड़ों कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं, खरीफ की तिल, उड़द और मूंगफली समेत अन्य फसलें पानी में खराब हो गई हैं। कई गांवों को जोड़ने वाले रास्तों और रपटों को भी नुकसान पहुंचा है। एक रपटा तेज बहाव में बह गया है। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि तहसील स्तर पर राजस्व कर्मियों की टीमें नुकसान का सर्वे कर रही हैं। सर्वे पूरा होने के बाद प्रभावित लोगों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दैवीय आपदा से अतिरिक्त धनराशि के लिए शासन को मांग भेजी गई है। बारिश का सबसे ज्यादा असर राठ तहसील में दिखाई दिया है, जहां कई स्थानों पर जलभराव है। प्रभावित गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और आवागमन के रास्ते दुरुस्त कराए जा रहे हैं। डीएम ने अधिकारियों और पुलिस को दिन में दो बार मौके पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

महिला अपराध रोकना और आमजन की सुरक्षा होगी प्राथमिकता : मानसी दहिया

एजेंसी, बस्ती। 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी मानसी दहिया ने मंगलवार को बस्ती में क्षेत्राधिकारी सदर का कार्यभार संभाल लिया। यह पुलिस सेवा में उनकी पहली पोस्टिंग है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने महिला अपराध पर सख्ती और आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि महिला अपराध के साथ यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था में सुधार भी उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा। पुलिस की सक्रियता बढ़ाकर कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। सदर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। शहर में लगने वाले जाम, प्रमुख चौराहों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया।

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: 11 मौतों के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन

एजेंसी, कौशांबी। यूपी के कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद फैक्ट्री मालिक के खिलाफ शिकंजा कस गया है। प्रशासन ने मालिक की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। वहीं, पुलिस ने देर रात फैक्ट्री मालिक को कथित हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन हादसे की जांच में जुटा है और फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी समेत अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

10.36 करोड़ से संवर रहा जायसी स्मारक, 80 प्रतिशत काम पूरा

एजेंसी, अमेठी। अमेठी में मलिक मोहम्मद जायसी स्मारक एवं पार्क को 10.36 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक पर्यटन और साहित्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के लिए 9.15 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं और करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अक्टूबर तक परियोजना पूरी होने की उम्मीद है। शोध संस्थान को आधुनिक पुस्तकालय, 120 क्षमता वाला सभागार, सामुदायिक पार्क, खुला व्यायाम क्षेत्र, ध्यान स्थल और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। स्मारक की दीवारों पर जायसी के जीवन और रचनाओं से जुड़े भित्तिचित्र बनाए जा रहे हैं।

संत पंकज महाराज ने शाकाहार, सदाचार और नशामुक्ति का दिया संदेश

एजेंसी, मीरजापुर। जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज महाराज की 108 दिवसीय शाकाहार-सदाचार, मद्यनिषेध एवं आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा मंगलवार को 124वें पड़ाव श्रीनिवास धाम पहुंची। मौनी स्वामी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संत पंकज महाराज ने मानव जीवन को अनमोल बताते हुए मेहनत, ईमानदारी, शाकाहार और नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम, सद्भाव और मानव धर्म से बेहतर समाज का निर्माण संभव है। संत ने श्रद्धालुओं को सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि समझाकर नियमित अभ्यास का आह्वान किया। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

युवाओं, महिलाओं और नई पीढ़ी को साधने के लिए सभी दलों ने शुरू की अलग-अलग रणनीति

यूपी चुनाव 2027 की तैयारी तेज, सभी दलों ने कसी कमर

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। चुनाव में अभी समय है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। सभी दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने और चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। संगठन को सक्रिय करने के साथ अलग-अलग वर्गों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

भाजपा आगामी चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। पार्टी 'बूथ जीता-चुनाव जीता' के फॉर्मूले को आधार बनाकर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रही है। बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क रखने और सरकार की उपलब्धियों तथा योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी का प्रयास है कि चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर अपना संगठन पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। वहीं, समाजवादी पार्टी भी 2027 में सत्ता में वापसी के लिए लगातार अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रही है।

पार्टी युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सरकार बनने की स्थिति में युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े वादों के जरिए मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पहुंच बढ़ाने पर भी जोर है। बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रियता बढ़ाई है।

पार्टी युवा नेतृत्व को आगे करके नई पीढ़ी के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। आकाश आनंद को आगे कर जेन-जी मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। बसपा का प्रयास अपने पारंपरिक जनाधार के साथ युवा मतदाताओं के बीच भी प्रभाव बढ़ाना है। कांग्रेस भी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चौपालों और जनसंपर्क कार्यक्रमों का सहारा ले रही है। पार्टी स्थानीय मुद्दों को उठाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

फिलहाल सभी दल चुनावी मैदान के लिए अपनी-अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। मतदाताओं का रुख किस दल के पक्ष में जाता है और किस रणनीति का कितना असर होता है, इसका वास्तविक आकलन चुनाव परिणाम आने के बाद ही हो सकेगा। चुनाव तक इन दलों की सक्रियता और बढ़ने की संभावना है, जिससे प्रदेश का सियासी माहौल लगातार गरमाता जाएगा।

सपा विधायक के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने कोतवाली में दी तहरीर

एजेंसी, बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े एक वीडियो को लेकर बस्ती में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव के फेसबुक खाते से कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो साझा किए जाने का आरोप लगाते हुए हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। संगठन ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।

हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री विनय सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज से संबंधित वीडियो बनाकर प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के वीडियो से हिंदूवादी संगठनों में रोष है। इसी को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। विनय सिंह के मुताबिक, कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री के प्रसार से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। संगठन ने पुलिस से मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मामले में सदर कोतवाल बृजा नंद सिंह ने बताया कि पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित वीडियो की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका : पदम

एजेंसी, मुरादाबाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) महानगर की ओर से मंगलवार को महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में युवा विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख पदम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपने माता-पिता के प्रति अपने ऋण को चुकाना है। इसके साथ ही मातृभूमि के प्रति भी हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे तय करें कि भारत को किस दिशा में आगे ले जाना है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, संस्कार और जिम्मेदारी के साथ देश के विकास में योगदान देने की अपील की।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉ. विशेष कुमार गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुरादाबाद विभाग के विभाग प्रचारक ब्रजमोहन, महानगर कार्यवाह विपिन, धवल दीक्षित, गौरव अग्रवाल और गोपाल हरि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला ने की, जबकि संचालन मेजर राजीव ढल ने किया।

प्रयागराज में गंगा-यमुना का रौद्र रूप, कई मोहल्ले जलमग्न

एजेंसी, प्रयागराज

◆ प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

गंगा और यमुना नदियों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण प्रयागराज में बाढ़ का संकट गहरा गया है। शहर के तटीय इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। नेवादा, गंगानगर, राजापुर, बेली, चिल्ला, छोटा बघाड़ा और दारागंज समेत कई मोहल्लों की दर्जनों गलियां जलमग्न हो गई हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाने को मजबूर होना पड़ा है।

बाढ़ की स्थिति बिगड़ने के साथ प्रभावित इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लोगों के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। शहर में फिलहाल दो राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों ने शरण ली है।

तटीय इलाकों में पानी भरने से स्थानीय लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। गलियों में पानी जमा होने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। घरों में पानी पहुंचने से लोगों को सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों को अपने घरों और जरूरी सामान की सुरक्षा की चिंता भी सताने लगी है।

गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के पीछे बांधों और बैराजों से छोड़ा जा रहा पानी भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लगातार पानी छोड़े जाने से नदियों का दबाव बढ़ रहा है और इसका असर शहर के निचले तथा नदी किनारे वाले क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। राहत शिविरों में पहुंचने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

स्थानीय स्तर पर लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। बाढ़ के कारण रसूलाबाद घाट का दाह संस्कार स्थल भी पानी में डूब गया है। इससे सामान्य जनजीवन पर बाढ़ के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी किनारे बसे क्षेत्रों में स्थिति लगातार संवेदनशील बनी हुई है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

तीन दिन की बारिश से सोनभद्र बेहाल, घाघर नदी के उफान से डूबीं बस्तियां

एजेंसी, सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा-मारकुंडी इलाके में लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते ताल-तलैया और नदी-नाले उफान पर हैं। घाघर बैराज का बांध खोले जाने के बाद घाघर नदी का जलस्तर और बहाव तेजी से बढ़ गया है।

तेज बहाव के कारण मारकुंडी जेल मार्ग तीसरी बार बह गया, जिससे क्षेत्र में आवागमन बाधित हो गया है। नदी के बढ़े जलस्तर का सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। कई बस्तियों में पानी भरने से लोगों को मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों और आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुंचने के कारण लोगों के सामने सुरक्षित स्थानों पर जाने की नौबत आ गई है। रोजमर्रा की जरूरतों और आवागमन पर भी बाढ़ का असर पड़ा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, बारिश और नदी के तेज बहाव से स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। प्रशासन प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लगातार जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। लोगों को आशंका है कि यदि बारिश जारी रही तो बाढ़ का दायरा और बढ़ सकता है।

अमेठी में बारिश के बीच गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबकर मासूम की मौत

एजेंसी, अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चे मकानों के लिए खतरा बढ़ गया है। सोमवार देर रात बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के पूरे बख्तावर गांव में कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से सात वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसके दादा घायल हो गए। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि जियालाल के घर की कच्ची दीवार सोमवार रात अचानक गिर गई। दीवार के पास चारपाई पर सात वर्षीय कोमल अपने दादा सूरज प्रसाद के साथ सो रही थी। दीवार गिरने से दोनों मलबे में दब गए।

हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों की मदद से मलबे में दबे दादा-पोती को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद कोमल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसके दादा सूरज प्रसाद के हाथ में फ्रैक्चर बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। पुलिस ने बालिका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार बारिश के बीच हुई इस घटना से गांव में शोक का माहौल है।

233 राजस्व गांवों के लाखों लोगों को राहत, अब स्वीकृत होंगे भवन नक्शे

◆ जीडीए की मंजूरी से लंबित भवन मानचित्रों का होगा निस्तारण।

एजेंसी, गोरखपुर

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के विस्तारित क्षेत्र में शामिल 233 नए राजस्व गांवों में अब भवनों के मानचित्र स्वीकृत हो सकेंगे। पिपराइच, पीपीगंज और मुण्डेरा बाजार नगर पंचायतों के साथ इन गांवों को वर्ष 2020 में जीडीए की सीमा में शामिल किया गया था। इसके बाद अलग महायोजना तैयार नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में मकानों और अन्य भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

जीडीए बोर्ड की 131वीं बैठक में शासन की ओर से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय के बाद महायोजना-2031 पुनरीक्षित में भू-उपयोग निर्धारण नहीं होने से अटके भवन मानचित्रों की स्वीकृति का रास्ता साफ हो गया है। इससे विस्तारित क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2020 में सीमा विस्तार के बाद पिपराइच, पीपीगंज और मुण्डेरा बाजार समेत 233 राजस्व गांव जीडीए क्षेत्र का हिस्सा बने थे। हालांकि, नए शामिल क्षेत्रों के लिए अलग से नियोजन व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने के कारण भवन निर्माण से जुड़े आवेदन लंबित होते रहे।

लोगों को अपने घरों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए मानचित्र स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। अब शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर इन क्षेत्रों में भवनों के मानचित्र स्वीकृत किए जा सकेंगे। इससे वैध तरीके से भवन निर्माण का रास्ता खुलेगा और लंबे समय से लंबित मामलों का निस्तारण भी संभव होगा। जीडीए के फैसले से लोगों को भवन निर्माण में बड़ी राहत मिलेगी।

फर्जीवाड़ा

11.50 करोड़ की नकदी भेजने के बाद सामने आई गड़बड़ी, जांच का दायरा बढ़ा

सहारनपुर पीएनबी में मिले 17 करोड़ के जाली नोट

एजेंसी, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में करीब 17 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने का मामला सामने आया है। बैंक में ऑडिट के दौरान नकदी की जांच में यह बड़ी गड़बड़ी सामने आई। मामले की जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब आठ बजे आरबीआई के छह अधिकारी दो वाहनों से बैंक पहुंचे। टीम ने बैंक के अंदर जाकर करेंसी चेस्ट, नकदी और संबंधित रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कई घंटे तक अधिकारी बैंक परिसर में मौजूद रहे। जांच के दौरान नकली नोटों की संख्या, उनके मूल्यवर्ग और करेंसी चेस्ट के रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। मामले में बैंक के तीन अधिकारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

इसके अलावा करेंसी चेस्ट के हाउसकीपर की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सीसीटीवी फुटेज में हाउसकीपर को कथित तौर पर रुपये निकालते हुए देखा गया है। इसके बाद जांच अधिकारियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगालनी शुरू कर दी है। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे और वहां रखे रिकॉर्ड में उनकी जानकारी क्यों नहीं सामने आई। अधिकारियों द्वारा नकदी के लेन-देन और चेस्ट से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। आरबीआई की टीम बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है।

साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि करेंसी चेस्ट में रखी रकम और बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज रकम के बीच कितना अंतर है। नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आरबीआई की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि 17 करोड़ रुपये के नकली नोट बैंक की करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे और इस पूरे मामले में किस-किस की भूमिका रही। जांच में नकली नोटों के स्रोत और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने पर जोर।

नकली नोटों के स्रोत की तलाश तेज

जांच में नकली नोटों के स्रोत और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने पर जोर दिया जा रहा है। आरबीआई अधिकारी करेंसी चेस्ट में रखी नकदी और बैंक अभिलेखों का बारीकी से मिलान कर रहे हैं। साथ ही, पिछले दिनों हुए नकदी लेन-देन और नोटों के आवागमन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हाउसकीपर की गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ के जरिए यह जानने का प्रयास है कि नकली नोट चेस्ट तक कैसे पहुंचे। फिलहाल जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में कार्रवाई की तस्वीर स्पष्ट होगी।

स्वाइन फ्लू से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पताल में बना अलग वार्ड

एजेंसी, फिरोजाबाद

◆ फिरोजाबाद में स्वाइन फ्लू का खतरा, संक्रमितों के लिए विशेष वार्ड।

स्वाइन फ्लू से संक्रमित 69 वर्षीय वृद्ध व्यापारी की सोमवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। संक्रमित मरीजों के उपचार और निगरानी के लिए सरकारी अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है। जानकारी के अनुसार वृद्ध की तबीयत खराब होने पर उन्हें रविवार रात सरकारी अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती कराया गया था।

उपचार के दौरान उनकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। सोमवार रात स्वजन उन्हें बेहतर उपचार की उम्मीद में एक निजी ट्रामा सेंटर लेकर गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बताया गया है कि वृद्ध हाल ही में जयपुर गए थे और वहीं उनके संक्रमित होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए फिरोजाबाद लाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण को देखते हुए उनके परिवार के सदस्यों की निगरानी शुरू कर दी है। संपर्क में आए लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है।

वृद्ध की मौत के बाद सरकारी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से संबंधित व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। संक्रमित मरीजों को सामान्य मरीजों से अलग रखने के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया है। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें और तत्काल चिकित्सकीय सलाह लें। विभाग की ओर से संदिग्ध मरीजों की जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है।

सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन उग्र, नगर परिषद कार्यालय में जमकर हुआ हंगामा

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र

नगर परिषद कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन मंगलवार को उस समय उग्र हो गया, जब कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के बाद नगर परिषद कार्यालय के अंदर घुस गए। यहां उन्होंने सफाई दरोगाओं पर अधिकारियों से मिलीभगत कर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला काफी बढ़ गया और करीब आधे घंटे तक कार्यालय परिसर में हंगामा होता रहा।

महिला सफाई कर्मचारियों का आरोप था कि सफाई दरोगा बनारसी, राजेंद्र कुमार और सत्यवान उनके आंदोलन में शामिल होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बात को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी थी। प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की शुरू हो गई। मामला बढ़ने पर धक्का-मुक्की मारपीट में भी बदल गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना कृष्णा गेट प्रभारी नरेश कुमार पुलिस टीम के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

हंगामे के बाद सफाई दरोगाओं ने महिला सफाई कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत भी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी तरह की गतिविधि से आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यालय परिसर में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका।

गोगामेड़ी से लौट रहे यूपी के श्रद्धालुओं का वाहन पलवल में पलटा, छह की मौत, 17 घायल

यादूपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर पलटा वाहन, मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, पलवल

कुंडली-मानेसर-पलवल मार्ग पर मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। हादसा यादूपुर गांव के पास सुबह करीब साढ़े चार बजे हुआ। श्रद्धालुओं से भरा 22 सीटर मैक्स वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। घायलों में दो छोटी बच्चियां 13 वर्षीय वाणी और आठ वर्षीय तनु भी शामिल हैं। दोनों को हल्की चोटें आई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार वाहन में कुल 23 श्रद्धालु सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का दल धार्मिक यात्रा पर निकला था। उन्होंने गोगामेड़ी और

श्री खाटू श्याम के दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद सभी वापस लौट रहे थे।

इसके बाद दल की वृंदावन और बरसाना जाने की योजना थी, लेकिन रास्ते में ही वाहन हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि यादूपुर गांव के पास पहुंचते ही चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और मैक्स सड़क पर पलट गया। वाहन के पलटते ही उसमें सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई।

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में पुलिस की मदद की। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विजय सिंह यादव पुत्र हाकिम सिंह निवासी चंदा किशनपुर, रेशमा देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी मैनपुरी, कमला देवी निवासी रामसुधु किशनपुर, राजकुमार, महेश राम सिंह निवासी मैनपुरी और सुधा पत्नी शेर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे में मृत सभी छह लोगों के बीच आपस में पारिवारिक संबंध और रिश्तेदारी थी। एक साथ कई परिजनों की मौत से परिवारों में मातम पसरा हुआ है। सदर थाना प्रभारी हरिकिशन शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी।

बैंकों में स्टाफ की भारी कमी, हजारों पद खाली; सेवाओं पर पड़ रहा असर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा के सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी सामने आई है। प्रदेश के सहकारी बैंकों में कुल 5148 स्वीकृत पदों में से केवल 582 पदों पर नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 4566 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इस तरह 90 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं। मुलाना की विधायक पूजा चौधरी के सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री डा. अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में बताया कि फिलहाल 886 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

यानी कुल खाली पदों में से करीब 19 प्रतिशत पदों पर ही भर्ती की जाएगी। इससे कर्मचारियों की कमी दूर करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति भी चिंताजनक है। इन बैंकों में 4557 स्वीकृत पदों के मुकाबले महज 375 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 4182 पद खाली हैं। तृतीय श्रेणी के 3087 स्वीकृत पदों में केवल 333 कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के 1470 पदों में महज 42 कर्मचारी तैनात हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसानों, ग्रामीण ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को ऋण, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में इनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में कर्मचारियों की भारी कमी से कामकाज प्रभावित होने और ग्राहकों को परेशानी होने की आशंका है। विभाग की ओर से 886 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन कुल रिक्तियों की तुलना में यह संख्या काफी कम है। कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर भर्ती की जरूरत महसूस की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अधिकांश पद खाली रहेंगे, जिससे सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी रहने की आशंका है।

फरीदाबाद में महिला ने दो बच्चों संग नहर में लगाई छलांग, तलाश जारी

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

गुरुग्राम नहर में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। सेक्टर-56 के पास एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तीनों की तलाश शुरू कर दी। महिला और दोनों बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह महिला अपने दो बच्चों के साथ गुरुग्राम नहर के पास पहुंची थी। सेक्टर-56 के नजदीक उसने अचानक दोनों बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान नहर में महिला

सेक्टर-56 के पास महिला और दोनों बच्चों की तलाश जारी।

और दोनों बच्चों की तलाश कर रहे हैं। पानी का बहाव अधिक होने के कारण तलाशी अभियान में कठिनाई आने की बात सामने आ रही है।

गोताखोरों की मदद से नहर के आसपास के हिस्से में तलाश की जा रही है। पुलिस ने महिला की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।

कार से टक्कर मारकर गिराया, फिर लाठी-डंडों से की युवक की पिटाई

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। अनाज मंडी क्षेत्र में सोमवार दोपहर पारिवारिक रंजिश के चलते एक युवक को घेरकर लाठी-डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने पहले गाड़ी से टक्कर मारकर युवक को सड़क पर गिराया और इसके बाद उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक सड़क पर पीड़ित को घेरकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घायल युवक की पहचान भोडिया खेड़ा निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। हमले में घायल अमित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर पंचायत में समझौता भी हुआ था, लेकिन इसके बाद दोबारा रंजिश बढ़ गई।

नौकरी से ज्यादा परिवार को तरजीह, चार पुलिसकर्मियों ने समय से पहले छोड़ी वर्दी

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

सिरसा जिला पुलिस में तैनात चार पुलिसकर्मियों ने निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी छोड़ दी। इन कर्मचारियों ने पुलिस की व्यस्त और तनावपूर्ण ड्यूटी के बजाय अब अपने परिवार और निजी जीवन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इनमें किसी की करीब डेढ़ वर्ष तो किसी की चार वर्ष तक की सेवा अभी बाकी थी।

इसके बावजूद उन्होंने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का फैसला किया। पुलिस विभाग की ओर से सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों के लंबे सेवाकाल और विभाग के प्रति उनके योगदान की सराहना की तथा उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस की नौकरी में लंबे समय तक ड्यूटी, लगातार बदलती जिम्मेदारियों और पारिवारिक जीवन के लिए सीमित समय जैसी चुनौतियां रहती हैं।

उनका कहना था कि नौकरी के दौरान परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे। ऐसे में उन्होंने शेष सेवा अवधि पूरी करने के बजाय परिवार के साथ अधिक समय बिताने को प्राथमिकता दी। कुछ कर्मचारियों ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी नौकरी छोड़ने की वजह बताया। उन्होंने बताया कि लगातार तनाव और ड्यूटी के दबाव के बीच रक्तचाप से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा।

वहीं, बदलते दौर में सामाजिक माध्यमों पर पुलिसकर्मियों को लेकर होने वाली टिप्पणियों और दबाव ने भी मानसिक तनाव बढ़ाया। पुलिसकर्मियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान छोटी-सी घटना भी सामाजिक माध्यमों पर तेजी से चर्चा का विषय बन जाती है। इससे काम का दबाव और बढ़ जाता है। ऐसे माहौल में उन्होंने निजी जीवन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। चारों कर्मचारियों के इस फैसले को विभाग ने सम्मान के साथ स्वीकार किया। अधिकारियों ने उनके सेवाकाल की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस विभाग में ईमानदारी से दी गई सेवा हमेशा महत्वपूर्ण रहती है।

न्यूज ब्रीफ

सरकारी कर्मचारियों को राहत, विदेश यात्रा पर लगी पूर्ण रोक हाई कोर्ट ने हटाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर सितंबर 2026 तक लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को मनमाना, असंगत और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। मामला नर्सिंग अधिकारी शीतल रानी से जुड़ा था, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया जाकर व्यावसायिक परीक्षा में शामिल होना था। हाई कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार के प्रतिबंध को उसके उद्देश्य की तुलना में अत्यधिक कठोर बताया। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह कदम 'अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल' करने जैसा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए नागरिकों के अधिकारों पर जरूरत से ज्यादा व्यापक रोक नहीं लगाई जा सकती।

सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी से स्टंट, राहगीरों की सुरक्षा पर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ के सेक्टर-65 की मार्केट में सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मार्केट क्षेत्र में अक्सर युवक वाहनों से स्टंट करते हैं, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में रहती है। वायरल वीडियो में एक चालक सड़क पर अपनी गाड़ी को तेज गति से गोल-गोल घुमाकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। वह काफी देर तक गाड़ी को इसी तरह घुमाता रहा। इस दौरान आसपास से दूसरे वाहन भी गुजर रहे थे। ऐसे में जरा सी लापरवाही बड़ा हादसा कर सकती थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और स्टंट करने वाले चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

23 लाख वसूले, 18 लाख और मांगे; शव रोकने पर मेदांता के खिलाफ गरमाया मामला

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। मेदांता अस्पताल में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी 30 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद शव सौंपने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर उनसे 23 लाख रुपए ले लिए थे। इसके बावजूद 18 लाख रुपये का अतिरिक्त बकाया बताया गया। परिवार ने इतनी बड़ी राशि तत्काल जमा करने में असमर्थता जताई तो अस्पताल ने कथित तौर पर भुगतान होने तक शव देने से इनकार कर दिया। मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अस्पताल को सख्त चेतावनी दी और अपने आधिकारिक इंटरनेट माध्यम पर लिखा कि वह खुद अस्पताल का इलाज करने जा रहे हैं। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव परिजनों को सौंप दिया।

हाइड्रोजन ट्रेन का दिल्ली तक विस्तार संभव जींद से नई दिल्ली तक ट्रायल

भारतेन्दु संवाददाता, जींद। जींद से सोनीपत के बीच चल रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का भविष्य में नई दिल्ली तक विस्तार संभव है। इसी संभावना को देखते हुए शुक्रवार को जींद से सब्जी मंडी होते हुए नई दिल्ली और फिर सोनीपत तक ट्रायल रन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई को ट्रेन को जींद से सोनीपत के लिए रवाना किया था। 89 किलोमीटर लंबे मार्ग पर ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलती है। कम यात्रियों के कारण इसके विस्तार पर विचार किया जा रहा है। ट्रायल के बाद आगे की योजना तय होगी। ट्रायल सफल रहा तो दिल्ली तक नियमित संचालन की राह हो सकती है आसान।

एसई की मौत के बाद गरमाया मामला, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ा परिवार

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

बिजली निगम के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (एसई) गीतू राम तंवर की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर परिवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस को दी गई शिकायत में 12 अधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से बताए गए थे, लेकिन दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोपियों को अज्ञात दिखा दिया गया। इससे परिजनों में नाराजगी है और उन्होंने कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है।

मृतक के भाई सुरेश तंवर ने कहा कि सुसाइड नोट में जिन-जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। परिवार की मांग है कि संबंधित अधिकारियों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक परिवार शव का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। परिवार की ओर से अधिवक्ता सोनिया तंवर ने

गायों को भूखा-प्यासा रखने का आरोप लगाकर किसानों ने वन विभाग के खिलाफ जताया विरोध।

भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि पुलिस को दी गई शिकायत में 12 अधिकारियों के नाम स्पष्ट तौर पर दिए गए थे। इसके बावजूद पुलिस ने शिकायत के अनुसार मामला दर्ज नहीं किया और प्राथमिकी में आरोपियों को अज्ञात दर्शा दिया। परिजनों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सुसाइड नोट में जिन लोगों का उल्लेख है, उनकी भूमिका की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। परिवार इस मामले में किसी तरह की खानापूर्ति के बजाय जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है। एसई की मौत के बाद से ही परिवार मामले में पारदर्शी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल, परिवार के रुख के कारण अंतिम संस्कार को लेकर स्थिति बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

परिवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, उनकी भूमिका की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि शिकायत में नाम स्पष्ट होने के बावजूद प्राथमिकी में आरोपियों को अज्ञात बताया गया। परिवार का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई होने तक उनका विरोध जारी रहेगा।

यमुनानगर में 98 प्रतिशत पेड़ गांवों में, शहरों में हरियाली का संकट लगातार गहराया

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

यमुनानगर जिले की हरियाली का बड़ा हिस्सा गांवों के भरोसे है। शहरों में तेजी से बढ़ते कंक्रीट के विस्तार के बीच पेड़ों की संख्या बेहद कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यमुनानगर जिले में जंगलों से बाहर 60 लाख 94 हजार 153 पेड़ हैं। यह संख्या राज्य में जंगलों से बाहर मौजूद कुल करीब 4.01 करोड़ पेड़ों का लगभग 14.86 प्रतिशत है। जिले के कुल पेड़ों में 98 प्रतिशत से अधिक पेड़ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

आंकड़े यह भी बताते हैं कि जिले के गांव पर्यावरण संरक्षण में शहरों की तुलना में कहीं आगे हैं। खेतों, गांवों की खाली जमीन, सड़कों के किनारे और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद हैं। इसके विपरीत शहरों में बढ़ती आबादी, आवासीय विस्तार, व्यावसायिक गतिविधियों और सड़क निर्माण के कारण हरियाली के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में पेड़ों की कमी का असर पर्यावरण के साथ-साथ लोगों

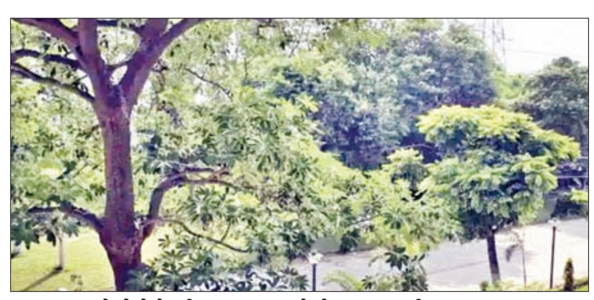

गांवों में पेड़ों की भरमार, शहरों में बढ़ता कंक्रीट का जंगल।

के जीवन पर भी पड़ सकता है। पेड़ हवा को शुद्ध करने के साथ तापमान को नियंत्रित करने, धूल और प्रदूषण को कम करने तथा भूजल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ऐसे में शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। यमुनानगर की पहचान लंबे समय से हरियाली और वन संपदा वाले जिले के रूप में रही है। हालांकि जंगलों से बाहर पेड़ों के आंकड़ों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बड़ा अंतर सामने आ रहा है। गांवों में पेड़ों की मौजूदगी जिले के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार शहरों में विकास कार्यों के साथ हरित क्षेत्र बढ़ाने पर भी ध्यान देना जरूरी है।

सड़कों के किनारे पौधारोपण, खाली सरकारी जमीन पर हरित क्षेत्र विकसित करने और पुराने पेड़ों के संरक्षण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यदि शहरी क्षेत्रों में समय रहते बड़े स्तर पर पौधारोपण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में हरियाली और तापमान से जुड़ी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। शहरी हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए पौधारोपण के साथ पुराने पेड़ों का संरक्षण और विकास योजनाओं में पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देना जरूरी है।

एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक, खाते से उड़ाए 1.90 लाख

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले में साइबर ठगों ने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका से 1.90 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने वॉट्सऐप के जरिए उन्हें एक एपीके फाइल भेजी। फाइल खोलते ही ठगों ने मोबाइल का नियंत्रण हासिल कर लिया और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी का दुरुपयोग करते हुए रकम निकाल ली। पीड़िता के अनुसार, ठगों ने उनके नाम पर नए क्रेडिट कार्ड भी जारी करवाए। इसके बाद चार अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से कुल 1.90 लाख रुपये निकाल लिए गए। खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने पर महिला शिक्षिका को ठगी का पता चला। उन्होंने मामले की शिकायत साइबर थाना पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। साइबर विशेषज्ञ लेनदेन और मोबाइल गतिविधियों की जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अनजान नंबरों से भेजी गई एपीके फाइल डाउनलोड न करें।

सीएनजी 94.80 रुपए किलो हुई, डीजल से सिर्फ 1.08 रुपए सस्ती

सस्ता ईंधन अब पड़ा महंगा, लगातार बढ़ती कीमतों से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी

भारतेन्दु संवाददाता, हांसी

कम ईंधन खर्च और बचत की उम्मीद में सीएनजी वाहन खरीदने वाले चालकों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हांसी में पिछले करीब 25 दिनों के दौरान सीएनजी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 89.90 रुपये प्रति किलो से बढ़कर अब सीएनजी 94.80 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। अचानक बढ़ी कीमतों से वाहन चालकों का ईंधन खर्च बढ़ गया है और उनके लिए बचत का गणित बिगड़ने लगा है।

शहर में डीजल की कीमत फिलहाल 95.88 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे में सीएनजी और डीजल के दाम में अब महज 1.08 रुपये का अंतर रह गया है। कुछ समय पहले तक सीएनजी को डीजल और पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन माना जाता था। इसी वजह से बड़ी संख्या में ऑटो और अन्य व्यावसायिक वाहनों के चालक सीएनजी को प्राथमिकता देते रहे हैं। लेकिन लगातार बढ़ते दामों ने अब इस अंतर को काफी

कम कर दिया है। खास बात यह है कि बीते एक सप्ताह में सीएनजी की कीमत दूसरी बार बढ़ाई गई है।

पहले सीएनजी के दाम में एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद सोमवार को एक साथ 2.90 रुपये प्रति किलो की वृद्धि कर दी गई। इससे चालकों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। सीएनजी के बढ़ते दामों का सबसे अधिक असर ऑटो चालकों और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले व्यावसायिक वाहन संचालकों पर पड़ रहा है। इन वाहनों का अधिकांश समय सड़क पर गुजरता है और प्रतिदिन बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत होती है।

ऐसे में प्रति किलो कुछ रुपये की बढ़ोतरी भी महीने के कुल खर्च पर बड़ा असर डालती है। ऑटो चालकों का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने के बावजूद यात्रियों से किराया तुरंत बढ़ाना आसान नहीं है। यदि किराया बढ़ाया जाता है तो यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और सवारी कम होने की आशंका रहती है। वहीं किराया नहीं बढ़ाने पर ईंधन खर्च बढ़ने से उनकी आमदनी प्रभावित होती है। पिछले 25 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सीएनजी की कीमत 89.90 रुपये से बढ़कर 94.80 रुपये प्रति किलो हो चुकी है।

यानी इस अवधि में कुल 4.90 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। लगातार दूसरी बार हुई बढ़ोतरी ने चालकों की चिंता और बढ़ा दी है। चालकों का कहना है कि सीएनजी को सस्ता और किफायती ईंधन मानकर वाहन खरीदने वालों के सामने अब खर्च कम करने की चुनौती है। यदि कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो सीएनजी और डीजल के बीच अंतर और कम हो सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को अपने रोजाना के खर्च और आय के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग उठाने के बजाय खर्च कम करने के उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं।

अपराधियों से आगे निकलेगी हरियाणा पुलिस, बनेगी एआई टास्क फोर्स

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

अपराध का स्वरूप तेजी से डिजिटल और तकनीक आधारित हो रहा है। ऐसे में हरियाणा पुलिस भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में है। पुलिस विभाग अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जांच और पुलिसिंग व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाने जा रहा है। इसके लिए विशेष एआई टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी करेंगे, जिन्हें एआई अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य एआई का व्यावहारिक, सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल बढ़ाना है।

इससे अपराध की जांच, नागरिक सेवाओं और पुलिस के कामकाज को अधिक तेज, सटीक तथा आंकड़ों पर आधारित बनाने में मदद मिलेगी। पुलिस विभाग पहले से ही एआई आधारित प्रणालियों के माध्यम से शिकायतों, न्यायालयों से संबंधित सूचनाओं और बड़े स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों को व्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रहा है। नई टास्क फोर्स इन प्रयासों को और व्यापक बनाएगी। टास्क फोर्स के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण, साइबर अपराध की जांच, डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल, दस्तावेजों की प्रक्रिया और अपराध के पैटर्न की पहचान जैसे कार्यों में एआई आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे। इससे जांच अधिकारियों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध डिजिटल जानकारी को कम समय में समझने और महत्वपूर्ण कड़ियों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

साइबर पुलिस की टीम पहले से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से वित्तीय लेन-देन की कड़ियों का विश्लेषण कर रही है। बैंकिंग लेन-देन और अन्य डिजिटल गतिविधियों के विशाल आंकड़ों में संदिग्ध पैटर्न, आपस में जुड़ी गतिविधियों और धन के संभावित प्रवाह की पहचान करने में एआई मददगार साबित हो सकता है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी तकनीकी रूप से मजबूत बनाना जरूरी है।

न्यूज ब्रीफ

दिल्ली में 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज सरकार ने लिया बड़ा फैसला

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती प्याज की कीमतों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उचित दर की दुकानों यानी सरकारी राशन की दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखना और आम लोगों को सस्ती दर पर प्याज उपलब्ध कराना है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महंगे प्याज का सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा कम कीमत पर प्याज उपलब्ध कराने के फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी योजना के तहत उचित दर की दुकानों के साथ-साथ मोबाइल वैन के जरिए भी प्याज की बिक्री की जाएगी। इससे अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोगों तक सस्ती दर पर प्याज पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि निर्धारित दर पर प्याज की बिक्री से बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में चार की मौत नशे में रील देखते ट्राला चला रहा था चालक

एजेंसी, नई दिल्ली। यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने ट्राला चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच और पूछताछ में चालक की गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोपित के अनुसार, वह शराब के नशे में मोबाइल फोन पर रील देखते हुए ट्राला चला रहा था। बताया गया कि साबौता कट के पास चालक ने तेज रफ्तार में अचानक ट्राला को दाईं ओर मोड़ दिया। इससे वाहन अनियंत्रित हो गया और भीषण हादसा हो गया। दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग प्रभावित हुए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया। दुर्घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ट्राला चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में चालक के नशे में वाहन चलाने और मोबाइल पर रील देखने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसे में चालक की लापरवाही और नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।

435 मामलों से मचा हड़कंप, मेरठ मंडल में डेंगू-स्वाइन फ्लू का बढ़ता प्रकोप

एजेंसी, नई दिल्ली। मेरठ मंडल में संक्रामक रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगस्त तक स्वाइन फ्लू के 302 और डेंगू के 133 मामले सामने आ चुके हैं। दोनों बीमारियों के कुल 435 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है।शासन की ओर से संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए लगातार निर्देश और अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में सर्वे पर्याप्त स्तर पर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं पर अधिक निर्भरता के कारण वास्तविक मरीजों की संख्या और स्थिति का सही आकलन करने में परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने बीमारी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने की चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच, नियमित सर्वे और संक्रमित क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। विभाग को अभियान तेज करने और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की जरूरत है।

आरएसएस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी प्रदर्शन करते उदित राज को पुलिस ने पकड़ा

केशव कुंज के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने उदित राज को हिरासत में लिया

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में कांग्रेस नेता उदित राज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केशव कुंज स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन हल्द्वानी में हुए 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के विरोध में किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की और मामले में कार्रवाई का विरोध किया।

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आरएसएस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हल्द्वानी विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास बताया। प्रदर्शन के दौरान उदित राज ने आरएसएस और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने मनुस्मृति भी जलाई। इस दौरान मौके पर पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए उदित राज समेत कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। यह पूरा मामला हल्द्वानी में हुए उस विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक कार्यक्रम और उसके बाद हुए कथित 'शुद्धिकरण' को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया

था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर वे अपना विरोध जारी रखेंगे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और आरएसएस के खिलाफ भी नारे लगाए। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और राजनीतिक असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कार्रवाई की गई।

ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक बस यात्रा में सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक करीब 43 किलोमीटर की बस यात्रा के दौरान नाबालिग लड़की के साथ हुई कथित हैवानियत ने सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद बस और पूरे रास्ते में सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां सामने आई हैं, जिन पर अब सवाल उठ रहे हैं। पहली बड़ी कमी बस में पर्याप्त निगरानी व्यवस्था का अभाव है। यदि बस में सक्रिय और स्पष्ट रूप से काम करने वाले सीसीटीवी कैमरे होते, तो घटना की जानकारी समय रहते सामने आ सकती थी।

दूसरी कमी चालक और परिचालक की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं होना है। तीसरी खामी बस में आपातकालीन सहायता की व्यवस्था को लेकर सामने आती है। यात्रियों के लिए ऐसी सुविधा जरूरी है, जिससे किसी खतरे की स्थिति में तत्काल पुलिस या संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जा सके। चौथी कमी रास्ते में पर्याप्त पुलिस गश्त और निगरानी का अभाव है। 43 किलोमीटर के लंबे मार्ग पर संवेदनशील स्थानों की पहचान कर नियमित निगरानी की जरूरत है। पांचवीं खामी बसों के संचालन और कर्मचारियों के सत्यापन से जुड़ी है। छठी समस्या यात्रियों के लिए शिकायत या मदद की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होना है।

सातवीं खामी घटना के दौरान आसपास मौजूद सुरक्षा तंत्र की प्रभावी प्रतिक्रिया से जुड़ी है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था कितनी प्रभावी है। अब जरूरत है कि बसों में निगरानी, कर्मचारियों का सत्यापन, आपातकालीन सहायता और मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

सनातन धर्म पर टिप्पणी का वीडियो वायरल,गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया केस

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक, 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ। वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया।

वीडियो सामने आने के बाद इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों तक पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मसूरी पुलिस ने तत्काल वीडियो की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने

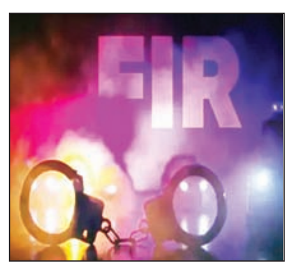

वायरल वीडियो की सामग्री और उससे जुड़े तथ्यों की जांच की। जांच के आधार पर पुलिस ने अब्दुल्ला नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर साझा या प्रसारित न करें।

प्रयागराज में बारिश ने दी गर्मी से राहत, अगले छह दिन बरसेंगे बादल

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज में इस बार मानसून जमकर मेहरबान है। अगस्त के बाद सितंबर की शुरुआत भी झमाझम बारिश के साथ हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, प्रयागराज और आसपास के जिलों में मानसून का असर 15 सितंबर तक बना रह सकता है। इसके चलते आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने और तापमान में गिरावट बने रहने की संभावना है। सितंबर के पहले ही दिन प्रयागराज में करीब 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश होती रही। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस तथा गर्मी से राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों ने अगले छह दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ बादल छाए रहने की उम्मीद है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बदली इमिग्रेशन व्यवस्था अब बोर्डिंग पास पर मुहर की जरूरत नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की इमिग्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को अब बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन की मुहर लगवाने के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और एयरपोर्ट पर उनकी यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज, आसान और अधिक व्यवस्थित बनाना है।

पहले विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर जांच के बाद अपने बोर्डिंग पास पर अधिकारी की मुहर लगवानी पड़ती थी। अब इस प्रक्रिया को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा गया है,

आईजीआई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पूरी तरह डिजिटल हुआ

जिससे कागजी औपचारिकताओं में कमी आएगी। यात्रियों को इमिग्रेशन जांच के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज और जरूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

जांच पूरी होने के बाद यात्रा से संबंधित विवरण डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इससे यात्रियों को बार-बार कागजात संभालने और बोर्डिंग पास पर मुहर की जांच कराने की जरूरत नहीं रहेगी। एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या को देखते हुए डिजिटल इमिग्रेशन व्यवस्था को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इससे इमिग्रेशन काउंटरों पर लगने वाली कतारों और प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ एयरपोर्ट की कार्यप्रणाली को भी अधिक आधुनिक बनाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड के कारण यात्रा संबंधी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज और सत्यापित किया जा सकेगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो हादसे,20 फीट नीचे गिरा ट्रॉला

एजेंसी, नई दिल्ली

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह दो अलग-अलग सड़क हादसों से हड़कंप मच गया। पहले हादसे में चालक को नींद की झपकी आने के कारण जिप्सम की बोरियों से लदा ट्रॉला अनियंत्रित हो गया। ट्रॉला एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 20 फीट नीचे जा गिरा और पलट गया। दुर्घटना में ट्रॉला चालक और हेल्पर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे।

दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉला को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी, ताकि एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित न हो। दूसरा हादसा भी मंगलवार सुबह एक्सप्रेसवे पर हुआ। यहां सड़क किनारे खड़ी एक कार को तेज रफ्तार बलेनो कार ने टक्कर

मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर हुईं। पहले हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने वाहन चालकों से एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले चालक पर्याप्त आराम के बाद ही वाहन चलाएं। नींद या थकान महसूस होने पर वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोककर आराम करना जरूरी है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉला हटाने की कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की कि नींद या थकान महसूस होने पर वाहन न चलाएं। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से बचें, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

18 लाख के बकाया बिल पर विवाद आयोग की दखल से सौंपा गया शव

एजेंसी, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी 30 वर्षीय युवक की गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद शव सौंपने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने करीब 18 लाख रुपये के बकाया बिल का भुगतान किए बिना शव देने से इनकार कर दिया। इससे परिवार के सामने गंभीर परेशानी खड़ी हो गई और मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया।

परिजनों के अनुसार, युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल की ओर से बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया। स्वजन का आरोप है कि करीब 18 लाख रुपये का अतिरिक्त बिल बताया गया और भुगतान होने तक शव सौंपने से मना कर दिया गया। मामले की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिलने के बाद आयोग ने हस्तक्षेप किया। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई की बात कही और अस्पताल पहुंचने की जानकारी भी साझा की।

आयोग की दखल के बाद मामले में तेजी आई। अस्पताल प्रबंधन ने बकाया बिल का भुगतान किए बिना ही शव परिजनों को सौंप दिया। शनिवार देर शाम शव स्वजन को मिलने के बाद परिवार उसे लेकर रवाना हुआ। घटना के बाद अस्पतालों में उपचार के बकाये और शव सौंपने से जुड़े मामलों को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। हालांकि, मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगाए गए आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयोग की कार्रवाई के बाद अब संबंधित पक्षों के दावों और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है।

नोएडा में युवक की पिटाई से मौत सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ द्वारा कथित रूप से पिटाई किए जाने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 27 वर्षीय प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से हरदोई जिले के संडीला गांव का रहने वाला था। प्रमोद सोमवार सुबह नोएडा के हरौला इलाके में किराये के कमरे में रहने वाले अपने गांव के परिचित नीरज लोधी से मिलने पहुंचा था। नीरज ने पुलिस को बताया कि वह नौकरी की

भीड़ ने युवक को पीटा, अस्पताल में मौत

तलाश में गांव से नोएडा आया था। बताया जा रहा है कि प्रमोद पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी कथित तौर पर जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया और 12 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक की पिटाई में कौन-कौन लोग शामिल थे और घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली-हरियाणा पुलिस का महामंथन, ब्रिक्स सम्मेलन में सुरक्षा होगी अभेद्य

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की सुरक्षा चाक-चौबंद, दिल्ली-हरियाणा पुलिस ने कसी कमर

एजेंसी, नई दिल्ली

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 को लेकर दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 31 अगस्त को दिल्ली और हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सम्मेलन के दौरान अंतरराज्यीय अपराधों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना और अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखना रहा।

अधिकारियों ने ऐसे लोगों से संबंधित खुफिया सूचनाओं को समय पर साझा करने, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने और दोनों राज्यों की सीमाओं पर समन्वित कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा की। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता दिल्ली पुलिस के उत्तरी

ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा में दिल्ली-हरियाणा पुलिस अलर्ट

रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त और सोनीपत के पुलिस आयुक्त ने की। इसमें बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना के अलावा सोनीपत जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा दिल्ली के उत्तरी रेंज से सटे हरियाणा के सीमावर्ती जिलों के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने सम्मेलन से पहले और उसके दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संभावित चुनौतियों की समीक्षा की। खासतौर पर दिल्ली-हरियाणा सीमा से जुड़े इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने पर चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी।

दोनों राज्यों की पुलिस के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने और जरूरी सूचनाओं को तत्काल साझा करने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने अंतरराज्यीय अपराधियों की पहचान, उनके ठिकानों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की। सम्मेलन के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली और हरियाणा के बीच बेहतर तालमेल से सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि दोनों राज्यों की पुलिस सम्मेलन से संबंधित सुरक्षा तैयारियों को लेकर आपसी समन्वय लगातार बनाए रखेगी।

किसी भी संभावित खतरे या आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान देश-विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा पुलिस का यह संयुक्त प्रयास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सम्मेलन के दौरान सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

गुरुग्राम में रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम के सेक्टर-29 में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 35 वर्षीय बाबुल हुसैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाबुल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतक बाबुल हुसैन मूल रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के डिगना गांव का रहने वाला था।

वह पिछले कुछ समय से गुरुग्राम के चक्करपुर इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। बाबुल गुरुग्राम की एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करता था और रोजमर्रा के काम के लिए साइकिल से आवाजाही करता था। बताया जा रहा है कि हादसा सेक्टर-29 इलाके में हुआ, जब बाबुल साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाबुल

गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और उसके मालिक तथा चालक की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके। मृतक के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद पुलिस ने कार कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी।

मेरठ में किसानों का हल्लाबोल, राकेश टिकैत की अगुवाई में महापंचायत शुरू

एजेंसी, नई दिल्ली

मेरठ में किसानों की बिजली, खाद, स्वास्थ्य और गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को कमिश्नरी का घेराव कर महापंचायत शुरू कर दी। भाकियू के आह्वान पर जिलेभर से किसान सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ तिरंगा रैली निकालते हुए कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे। किसानों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण पूरा चौराहा जाम हो गया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसानों की भीड़ के आगे प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हुईं। इसके बावजूद किसानों का कमिश्नरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में किसान वहां जमा हो गए और महापंचायत शुरू हो गई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने की बात कही।

न्यूज ब्रीफ

रोजगार गारंटी के नाम पर युवाओं को छला, 13 विभागों में 37% पद खाली : कटवाल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने विधानसभा में युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों

लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता को दी गई लोक-लुभावनी गारंटियां सरकार के पौने चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरी हैं। कांग्रेस ने वादे 'खटाखट' पूरे करने का दावा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही 'फटाफट' 982 संस्थान बंद कर प्रदेश को विकास की दौड़ में पीछे धकेल दिया। विधायक कटवाल ने आरोप लगाया कि 11 दिसंबर 2022 को शपथ लेने के ठीक अगले दिन बिना किसी अध्ययन के संस्थान बंद करने की अधिसूचना जारी की गई, जिससे हजारों पद समाप्त हो गए। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में लगभग 5.90 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। 13 मुख्य विभागों में करीब 37% और बिजली बोर्ड में 47% पद रिक्त पड़े हैं। राज्य में 65,254 बीएड और 16,028 जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित युवा नौकरी की राह देख रहे हैं। सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण पाने वाले जेबीटी भी बेरोजगार हैं। विभिन्न विभागों में 18-20 वर्षों से सेवाएं दे रहे करीब 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। सरकार कार्यकाल के अंतिम चरण में नीति बनाने की बात कर रही है। कटवाल ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द आरएंडपी नियम बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर स्थाई नौकरी का प्रावधान करे। उन्होंने कहा कि रोगी कल्याण समिति कर्मियों का वेतन बढ़ने के बजाय घटा है।

हमीरपुर जिला स्थापना दिवस पर प्रेम कुमार धूमल व अनुराग ठाकुर ने दीं शुभकामनाएं

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के समस्त निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 1972 में हमीरपुर जिले का गठन हुआ था। स्थापना के बाद से लेकर आज तक हमीरपुर ने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आधारभूत ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिले के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी लगन और कर्मठता के बल पर हमीरपुर को प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में एक विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की पहचान शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अग्रणी जिले के रूप में रही है। यहां के युवाओं ने देश की सेना, प्रशासनिक सेवाओं, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रोफेसर धूमल ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी हमीरपुर विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सांसद अनुराग ने जिला स्थापना दिवस पर सभी जिलावासियों को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 1972 में अस्तित्व में आया हमीरपुर आज विकास और उपलब्धियों की एक प्रेरणादायक यात्रा तय कर चुका है। बीते वर्षों में जिले ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और यहां के लोगों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और संकल्प से हमीरपुर को नई पहचान दिलाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में हमीरपुर विकास, शिक्षा, खेल, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा तथा प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

चोरी कर भागने के बजाय निर्माणाधीन मकान में सो गया युवक, पुलिस ने उठाकर पकड़ा

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट की शाह कॉलोनी में रविवार सुबह चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। आरोप है कि एक युवक दीवार फांदकर निर्माणाधीन मकान में घुसा और वहां से इनवर्टर व भारी बैटरी चोरी करने के बाद भागने के बजाय फोल्डिंग बेड पर ही गहरी नींद में सो गया। सुबह सैर के लिए निकले स्थानीय लोगों ने युवक को सोते हुए देखा तो डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जगाकर हिरासत में ले लिया। उसके पास से चोरी का सामान बरामद कर परिवार को लौटा दिया गया। पुलिस के अनुसार युवक के सामान से तीखी लाल मिर्च से भरा डिब्बा भी मिला है। आशंका है कि वह पकड़े जाने पर पीछा करने वालों की आंखों में मिर्च डालकर भागने की योजना में रहा होगा। हालांकि, इसका वास्तविक कारण जांच के बाद स्पष्ट होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलोनी में लगातार हो रही चोरियों के चलते निगरानी कमेटी बनाई गई है। थाना डिवीजन नंबर-2 पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूर्व की चोरी की वारदातों में भी उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।

एचआईवी संक्रमण के बचाव की दी जानकारी

भारतेन्दु संवादाता, मंडी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी ग्रेड-ए, में एचआईवी एवं एड्स के प्रति जागरूकता विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जोनल अस्पताल मंडी की काउंसलर श्याम लता ने संस्थान के विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षुओं एवं स्टाफ सदस्यों कोएचआईवी एवं एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने एचआईवी संक्रमण के कारणों, बचाव के उपायों, भ्रांतियों तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवनशैली के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षुओं को एचआईवी एवं एड्स के प्रति जागरूक रहने तथा समाज में इसके संबंध में फैली गलत धारणाओं को दूर करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर रेड रिबन क्लब, राजकीय आईटीआई मंडी के नोडल अधिकारी परवीन धीमान तथा रेड रिबन क्लब सदस्य महेंद्र पाल सहित प्रशिक्षक सुभाष चंद, पुष्पा देवी, मीना ठाकुर, बलदेव चौहान, दिनेश शर्मा एवं द्रुतेश उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान के विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षुओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं एवं स्टाफ सदस्यों में एचआईवी एवं एड्स के प्रति सही जानकारी, जागरूकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना रहा।

स्कूल ऑफ नेशनल प्लानिंग के प्रशिक्षुओं ने किया हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी का भ्रमण

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के वास्तु संरक्षण विभाग के एम आर्क आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन के विद्यार्थी हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी परिसर बैहना मलोरी पहुंचे। ये विद्यार्थी इन दिनों मंडी के समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य के संरक्षण एवं प्रबंधन पर व्यापक क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे हैं। 26 अगस्त से चल रहा उनका यह अध्ययन भ्रमण 9 सितंबर तक जारी रहेगा। संस्थान के वास्तु संरक्षण विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रभारी संजय भंडारी व संस्थान के विशेषज्ञों के नेतृत्व में इन विद्यार्थियों ने फोटो गैलरी में कंजरविंग एंड सेफगार्डिंग दी कल्चर लैंडस्केप आफ मंडी, एक कम्युनिटी सेंटरड अपरोच टू संस्टेनबिलिटी एंड रेजीलेंस विषय पर आधारित अध्ययन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। फोटो गैलरी के संस्थापक बीरबल शर्मा ने इन विद्यार्थियों को मंडी की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक बस्तिया, मंदिर वास्तुकला, स्थानीय परंपराओं तथा समुदाय द्वारा संरक्षित पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के बारे में विस्तार से उपलब्ध छायाचित्रों, पुस्तकों व संग्रहालय के संग्रह के माध्यम से बताया । विद्यार्थियों ने मंडी के ऐतिहासिक विकास और उसके बदलते स्वरूप को विस्तार से जाना। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट नंद लाल चंदेल,लोक निर्माण विभाग में कार्यरत वास्तुकार विजय ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे तथा उन्होंने भी विद्यार्थियों को बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवाई। संजय भंडारी ने बताया कि यह अध्ययन विशेष तौर पर हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक नाजुकता, पारिस्थितिक संवेदनशीलता तथा समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में किया जा रहा है।

जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद होगा ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार : सुक्खू

ओबीसी आरक्षण के युक्तिकरण की मांग, सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय के दिए संकेत

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिल रहे आरक्षण को लेकर मंगलवार को विधानसभा में सवाल उठा। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव की मांग की। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और आयोग भी इस विषय पर मंथन कर रहा है।

सुखराम चौधरी ने पूरक सवाल के दौरान कहा कि प्रदेश के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में एमबीबीएस की 85 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों में ओबीसी के लिए अलग-अलग संख्या में सीटें आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत है, जबकि एमबीबीएस में उन्हें मिलने वाला आरक्षण बहुत कम है। उन्होंने इसे 'ऊंट के मुंह में जीरा' बताते हुए कहा कि या तो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए या एमबीबीएस में ओबीसी को कम से कम 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उन्होंने आरक्षण के युक्तिकरण की भी मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने सुखराम चौधरी से कहा कि जब वह मंत्री थे, तब उन्होंने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, उनके हित के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग बनाया है, जिससे इस वर्ग को उनके अधिकार मिल सकें। जिन क्षेत्रों में ओबीसी के लिए आरक्षण कम है, वहां आयोग मंथन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पूरी होने के बाद इसके आंकड़ों के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और जातीय जनगणना के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर भी सरकार विचार करेगी। सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर ओबीसी को वर्ग-ए और वर्ग-बी में 12 प्रतिशत तथा वर्ग-सी और वर्ग-डी में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

तकनीकी शिक्षा में ओबीसी को 18 फीसदी आरक्षण, आयुर्वेद में 12 प्रतिशत

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में एमबीबीएस के 85 प्रतिशत राज्य कोटे के तहत ओबीसी के लिए सीटें अलग-अलग निर्धारित हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में कुल 102 राज्य कोटे की सीटों में ओबीसी के लिए चार सीटें आरक्षित हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 102 में दो, श्री लाल बहादुर शास्त्री आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मंडी में 102 में दो, डॉ. यशवंत सिंह परमार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नाहन में 102 में दो, डॉ. राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में 102 में दो और पंडित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चंबा में 102 में दो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश दंत महाविद्यालय शिमला में 64 राज्य कोटे की सीटों में ओबीसी के लिए एक सीट आरक्षित है। लिखित जवाब में बताया गया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, फार्मेसी महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए ओबीसी को 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आयुष विभाग के राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला में बीएएमएस और एमडी आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत नर्सिंग, पैरामेडिकल तथा डेंटल हाइजिनिस्ट और डेंटल मैकेनिक पाठ्यक्रमों में ओबीसी के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वहीं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में बीएड पाठ्यक्रम में ओबीसी के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित हिम-चंडीगढ़ सिटी की प्रगति की समीक्षा की

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ के निकट बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित हिम-चंडीगढ़ सिटी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस नए शहर का विकास कार्य शुरू करेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-चंडीगढ़ सिटी को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और आवश्यक नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित एक आधुनिक, सुनियोजित एवं टिकाऊ शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रस्तावित शहर का सुनियोजित, सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सरसा नदी के किनारे लगभग नौ किलोमीटर लंबे सुविकसित रिवरफ्रंट को परियोजना में शामिल किया जाए।

फेम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधीक्षकों में हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह को मिला स्थान

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। फेम इंडिया, एशिया पोस्ट ने देशभर में प्रभावी पुलिस नेतृत्व, कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा, अनुसंधान, विशेष अभियानों, तकनीक के उपयोग और जनभागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 25 प्रमुख पुलिस अधिकारियों का चयन किया है।

इसके साथ ही उत्कृष्ट और विशिष्ट कार्यशैली के लिए पांच अधिकारियों को विशेष 'सुपर-5' श्रेणी में शामिल किया गया है। फेम इंडिया मैगजीन के संपादक धीरज कुमार के अनुसार इस प्रकार इस विशेष सूची में कुल 30 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। चयन में अधिकारियों के फील्ड अनुभव, नेतृत्व क्षमता, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था प्रबंधन, नागरिक सेवाओं, पुलिस आधुनिकीकरण और जनविश्वास को प्रमुख आधार बनाया गया है। इस सूची में हमीरपुर जिला के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह का नाम 18वें स्थान पर है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी पुलिस कप्तान रहे, जो सराहनीय कार्यों के बावजूद टॉप 25 कीसूची में स्थान बनाने से चूक गए। फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने पांच ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी विशेष 'सुपर-5' श्रेणी में शामिल किया है, जिनका कार्य और नेतृत्व पुलिसिंग के अलग-अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। इसमें शिमला जिला के एसपी गौरव सिंह को चौथा स्थान मिला है। फेम इंडिया के प्रबंध संपादक अनिल सिंह के अनुसार आज पुलिसिंग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के साथ साइबर अपराध, मादक पदार्थ, यातायात, महिला एवं बाल सुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग, तकनीकी अपराध और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी चुनौतियां पुलिस नेतृत्व से नई दक्षताओं की मांग कर रही हैं।

650 केंद्रों तक पहुंचा 'एक से श्रेष्ठ' अभियान, 12 हजार बच्चों को मिल रहा शिक्षा का सहारा

शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए : राज्यपाल

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। एक्ट टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशन की ओर से संचालित 'एक से श्रेष्ठ' पहल ने करीब पांच वर्ष पूरे करते हुए 650 शिक्षा केंद्रों तक पहुंच बना ली है।

इस पहल के माध्यम से करीब 12 हजार बच्चों को शिक्षा और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। बिलासपुर स्थित आर्ट एंड कल्चर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने फाउंडेशन को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि 650 केंद्र केवल एक आंकड़ा नहीं हैं, बल्कि ऐसे 650 स्थान हैं, जहां बच्चों तक ज्ञान की रोशनी पहुंच रही है और उन्हें बेहतर भविष्य के सपने देखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और देश के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। शहर हो या दूरदराज का गांव, प्रत्येक बच्चे को सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को सीखने के लिए संसाधन, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास भी मिलना जरूरी है।

उन्होंने 'एक से श्रेष्ठ' के तहत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के साथ किताबें, स्टेशनरी, स्कूल बैग, जूते, ट्रैकसूट और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने शिक्षकों को लैपटॉप वितरित किए। उन्होंने शिक्षकों से तकनीक का उपयोग केवल पढ़ाने के साधन के रूप में न करते हुए प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत सीखने की जरूरत को समझने में करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक पहल की असली ताकत उसके भवन या संसाधन नहीं, बल्कि वे लोग होते हैं जो समर्पण के साथ उसके उद्देश्यों को धरातल पर उतारते हैं। 'एक से श्रेष्ठ' से जुड़े शिक्षक केवल विषयों की शिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सपने देखने का साहस भी पैदा कर रहे हैं।

महिलाओं को मिला रोजगार का अवसर

राज्यपाल ने बताया कि इस पहल से करीब 692 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत अवसर महिलाओं को मिले हैं। इनमें करीब 60 प्रतिशत महिलाओं के लिए यह पहला रोजगार अवसर रहा। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क शिक्षा और शैक्षणिक सामग्री मिलने से हजारों परिवारों के शिक्षा संबंधी खर्च में कमी आई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 12 हजार से अधिक परिवार सामूहिक रूप से 5.40 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत कर चुके हैं।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर हमले की घटना पर आयोग सख्त, मौके पर पहुंचे दिग्विजय मल्होत्रा

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने कंडवाल पंचायत के नडाई गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति के साथ कथित मारपीट और गाली-गलौज की घटना का कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य एडवोकेट दिग्विजय मल्होत्रा ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया तथा पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की।

एडवोकेट मल्होत्रा ने पुलिस प्रशासन से भी घटना के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि मामले में दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा मामले में की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयोग सदस्य ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज और पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस की तत्परता से पीड़ित परिवार में विश्वास की भावना मजबूत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले में आगे भी निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

दिग्विजय मल्होत्रा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, भेदभाव अथवा अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सामाजिक समरसता और भाईचारे की मिसाल रहा है तथा जात-पात और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग भी अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। मल्होत्रा ने लोगों से आपसी भाईचारा, सद्भाव और सामाजिक एकजुटता बनाए रखने की अपील की।

दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी। अधिसूचना के मुताबिक आईएएस अधिकारी कुमन्द सिंह को हिमाचल प्रदेश फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के निदेशक पद के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम शिमला के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहीं, आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान निजी सचिव-सह-विशेष सचिव के पद पर हैं। उनके पास निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी है।

केंद्र का पुतला जलाने के प्रदर्शन से कांग्रेस की बौखलाहट हुई उजागर : विजय अग्निहोत्री

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने मंगलवार को प्रेस बयान जारी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार का पुतला जलाए जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ गई है।

अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी स्वयं नफरत की राजनीति करते हैं और दूसरे नेताओं का सम्मान करना नहीं जानते। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवाद को बढ़ावा देकर राहुल गांधी केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस प्रकार की राजनीति से परहेज करती है। पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को जनता कई बार नकार चुकी है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे नेतृत्व को बार-बार आगे बढ़ाने से पार्टी को क्या हासिल होगा, इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। अग्निहोत्री ने दावा किया कि कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में जनता ने भी शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से आह्वान किया कि वे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा विकास और जनहित की राजनीति में विश्वास रखती है तथा इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

आरसीएफसी और हर्बल गार्डन को बचाने के लिए क्रमिक भूख हड़ताल 13वें दिन भी जारी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जोगिंद्रनगर में सात राज्यों के क्षेत्रीय सुविधा एवं अनुसंधान केंद्र (आरसीएफसी), हर्बल गार्डन एवं फार्मेसी को बचाने की मांग को लेकर चल रही क्रमिक भूख हड़ताल 13वें दिन भी जारी रही। मंगलवार को विभिन्न पंचायतों की महिलाओं ने मोर्चा संभाला। टिकरू से दीपा कुमारी, मचकेहड़ से रजनी देवी, पातकू से लीला देवी और सारली से कुसमा देवी भूख हड़ताल पर बैठीं।

इससे पहले भराड़ू और सपैड़ू पंचायतों की महिलाओं ने अनशन में भाग लिया था। आंदोलन को समर्थन देने के लिए युवा नेता सोमेंद्र ठाकुर, मेघना ठाकुर, जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज व शिवानी ठाकुर, पूर्व जिला परिषद सदस्य अंजना ठाकुरव ममता भाटिया, तलकेहड़ पंचायत प्रधान शुचिका प्रधान सहित कई वर्तमान व पूर्व पंचायत प्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे। संघर्ष समिति अध्यक्ष गुरुशरण परमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आरसीएफसी को जोगिंदर नगर से स्थानांतरित करने संबंधी अधिसूचना वापस लेने की मांग दोहराई गई।

बैठक में 7 सितंबर को रामलीला मैदान जोगिंदर नगर में प्रस्तावित जन आक्रोश महारैली में पांच हजार से अधिक लोगों को जुटाने का संकल्प लिया गया। रोटेरियन अजय ठाकुर ने सुबह पिछले दिन की अनशन टीम को नई टीम से बदलने की घोषणा की। संघर्ष समिति ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

कार्यक्रम 'एक से श्रेष्ठ' के पांच वर्ष पूरे, छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए राज्यपाल का अनुराग ठाकुर ने जताया आभार

शिक्षा के जरिए बच्चों को सशक्त बना रहा 'एक से श्रेष्ठ' अभियान

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने 'एक से श्रेष्ठ' सामाजिक पहल के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने 'एक से श्रेष्ठ' अभियान की पांच वर्षों की यात्रा और इसकी उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉ. अनिल धीमान, कमलेश कुमारी, उर्मिल ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर और विजय अग्निहोत्री सहित जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, जिला परिषद के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 'एक से श्रेष्ठ' केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का एक व्यापक सामाजिक अभियान है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कविंद्र गुप्ता द्वारा विद्यार्थियों के बीच समय बिताना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बच्चों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और समावेशी सोच से प्रेरणा लेकर उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बिना किसी सरकारी सहायता के 'एक से श्रेष्ठ' कार्यक्रम की शुरुआत की। गुरुकुल पद्धति की भावना के अनुरूप इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुराग ने बताया कि 'एक से श्रेष्ठ' कार्यक्रम की शुरुआत 5 अक्तूबर 2021 को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर की गई थी।

इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सामने मौजूद बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक चुनौतियों के समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 'एक से श्रेष्ठ' के तहत लगभग 650 केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 12,000 से अधिक बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग के साथ-साथ संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा दी जा रही है। अनुराग ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए नियमित रूप से प्रोटीन शेक भी उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को राष्ट्रभक्ति, खेलकूद और स्वच्छता जैसे अभियानों से जोड़कर उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में 98 प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षिकाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक पहल के अंतर्गत अब तक 950 से अधिक बच्चों को स्कूल बैग, पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि 25 से अधिक शिक्षकों को लैपटॉप देकर शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

हिंदी के प्रचार-प्रसार को लेकर पूरे माह होंगे रचनात्मक कार्यक्रम व कार्यशालाएं

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। राजकीय महाविद्यालय पनारसा में हिंदी माह के आयोजनों का शुभारंभ हो गया है। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार, विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि विकसित करने और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे माह विभिन्न प्रतियोगिताएं, गतिविधियां एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ उपप्राचार्य डॉ. पूजा शर्मा की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर इतिहास विभाग के प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष बिंदु सूर्यवंशी, प्रोफेसर अनीता सहित अन्य प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रथम दिवस सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। हिंदी माह के दौरान सुलेख व अंताक्षरी सहित विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताएं होंगी। हेरिटेज इन फाउंडेशन, पुणे के सहयोग से ऑनलाइन कैलिग्राफी तथा हिमतरु प्रकाशन के सहयोग से कहानी लेखन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों की श्रेष्ठ कहानियों का पाठ कर उन्हें प्रकाशन के लिए चुना जाएगा। इसके अलावा हिंदी भाषा-साहित्य के इतिहास एवं विकास पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन और कहानी-कविता लेखन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। समापन समारोह में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।

सितंबर में बिलासपुर में होंगे सांख्यिकीय सर्वेक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर द्वारा सितंबर 2026 में बिलासपुर जिले के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सर्वेक्षण किए जाएंगे। यह जानकारी सहायक निदेशक रूपेश जालवाल ने दी। उन्होंने बताया कि माह के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण, प्रवासन, ऋण व निवेश, स्थिति आकलन तथा अनिगमित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का वार्षिक सर्वेक्षण सहित विभिन्न विषयों पर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इन आंकड़ों का उपयोग सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आकलन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किया जाता है। सर्वेक्षण के लिए अधिकृत कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी, प्रगणक और पर्यवेक्षक चयनित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बिलासपुर में उप मुहाल खैरियां लुहणु, टिहरी और हटवाड़ में सर्वेक्षण होगा। जालवाल ने लोगों से सर्वेक्षण दलों को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध कराई गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए उपयोग होगी।

सतपाल वर्धन झंडूता की 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एपीएमसी बिलासपुर के अध्यक्ष सतपाल वर्धन को उपमंडलीय योजना, विकास व 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति, झंडूता का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नियुक्ति पर सतपाल वर्धन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं व विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए वह सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से झंडूता क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

अर्चना ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी से की मुलाकात

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल भाजपा नेत्री और तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन (ओएनजीसी) की नवनियुक्त स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। उनके इस पद पर मनोनयन के बाद डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से पहली बार शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस पद पर कार्य के लिए उनके मार्गदर्शन और सहयोग की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर अर्चना ठाकुर से मुलाकात के दौरान स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने पर आशा व्यक्त की कि प्रशासनिक, शैक्षणिक और समाज सेवा का उनका अनुभव तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन के विकास और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

बिलासपुर में वोल्वो बस से 51 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब का युवक गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम (एसआईटी) ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भजवाणी फोरलेन पर एक वोल्वो बस से 51 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। पुलिस ने मामले में पंजाब निवासी 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 30 अगस्त को एसआईटी की टीम भजवाणी फोरलेन पर नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक वोल्वो बस को जांच के लिए रोका गया। बस में सवार युवक त्रिलोक सिंह (28), पुत्र अवतार सिंह, निवासी गांव व डाकघर तेडाकलां, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर (पंजाब) की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 51 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना झंडूता में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत एफआईआर संख्या 73/26 दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब नशे की खेप के स्रोत और इसे कहां सप्लाई किया जाना था, इसका पता लगाने में जुटी है।

बिलासपुर में लो वोल्टेज व अघोषित बिजली कटों का मामला विधानसभा में गूंजा

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में गहराते बिजली संकट और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शून्य काल में सरकार को घेरा। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि क्षेत्र की कई पंचायतों में अघोषित बिजली कटों और लो वोल्टेज के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने सदन में प्रमुख समस्याएं और मांगें रखीं: पेयजल संकट: बिजली आपूर्ति ठप होने से क्षेत्र की उठाऊ पेयजल योजनाएं बंद पड़ गई हैं, जिससे बरसात के मौसम में भी लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। प्रभावित पंचायतें: कुठेड़ा, भलस्वाय, हवाण और माकड़ी-मारकंड सहित कई पंचायतों में बिना पूर्व सूचना के पूरे-पूरे दिन बिजली गुल रहती है और कई जगह दूसरे दिन आपूर्ति बहाल हो पाती है। उपकरण बने शोपीस: लो वोल्टेज के कारण बिजली से चलने वाले घरेलू उपकरण काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई बाधित: बिजली न होने से मोबाइल और लैपटॉप चार्ज नहीं हो पा रहे, जिससे छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई और कोचिंग बुरी तरह प्रभावित हो रही है। त्रिलोक जम्वाल ने मांग की कि निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरे किए जाएं और जनता को इस समस्या से प्राथमिकता के आधार पर स्थाई राहत दिलाई जाए।

ड्रॉप्स ऑफ होप ने रक्तदान करके बचाई 41 जिंदगियां

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। ड्रॉप्स ऑफ होप सोसाइटी सिरमौर का हर माह की तरह अगस्त महीने में भी सामाजिक सेवा और समर्पण का दौर निरंतर जारी रहा। समूह के सदस्यों के सामूहिक सहयोग और दिन-रात की कड़ी मेहनत से इस माह कुल 41 यूनिट रक्तदान संपन्न कराया गया। संस्था हर महीने नियमित रूप से रक्तदान शिविरों और आपातकालीन कॉल्स के माध्यम से जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाती है। इसी कड़ी में अगस्त की इस रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में भर्ती गंभीर मरीजों को समय पर रक्त और प्लेटलेट्स उपलब्ध कराए गए। सोसाइटी के अध्यक्ष ईशान राव ने बताया कि सदस्यों की तत्परता और निस्वार्थ भावना से ही यह सेवा कार्य हर महीने सुचारू रूप से चल पा रहा है। स्थानीय स्तर पर डॉ. वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नाहन में भर्ती मरीजों के लिए कुल 15 यूनिट रक्त संकलित किया गया। इसमें पॉजिटिव की 7 यूनिट,, पॉजिटिव की 5 यूनिट, ह्र पॉजिटिव की 2 यूनिट और नेगेटिव की 1 यूनिट शामिल रही, जिससे स्थानीय स्तर पर जरूरतमंदों की तत्काल सहायता हो सकी। नाहन के अलावा बाहरी राज्यों और प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में भी संस्था के सदस्यों ने तुरंत पहुंचकर रक्तदान व सहयोग प्रदान किया।

हमीरपुर में बारिश से दो दिनों में 11.25 करोड़ का नुकसान

मानसून में जिले में हुए नुकसान का आंकड़ा 71.26 करोड़ से भी अधिक

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला हमीरपुर के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले दो दिनों के दौरान हुई बारिश से 11.25 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। इसी के साथ इस मानसून सीजन में 30 जून के बाद जिला हमीरपुर में सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का आंकड़ा 71.26 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

एडीसी अभिषेक गर्ग ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के जिला एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (डीईओसी) में मंगलवार दोपहर तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत 24 घंटों के दौरान जिले भर से 11.25 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। इस दौरान एक कच्चा मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है और 2 गोशालाएं ध्वस्त हुई हैं। लोक निर्माण विभाग को लगभग 10 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं को 1.24 करोड़ रुपए और बिजली की लाइनों का भी लगभग एक लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एडीसी ने बताया कि इस मानसून सीजन में 30 जून के बाद जिला हमीरपुर में सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का आंकड़ा 71.26 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस सीजन में अभी तक लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 45.33 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि, जल शक्ति विभाग को 23.42 करोड़ रुपए, बिजली बोर्ड को 1.13 करोड़, नेशनल हाईवे को 50.22 लाख और शिक्षा विभाग को 17.70 लाख रुपए की क्षति हुई है। बागवानी की फसलों को 43.56 लाख रुपए के नुकसान की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। एक पंचायत घर के गिरने से लगभग 3.50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। 2 किचन शैड गिरने से लगभग 65 हजार रुपए की क्षति हुई है। इस सीजन में एक पक्का मकान और 6 कच्चे मकान ध्वस्त होने से लगभग 14.45 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी दौरान 28 अन्य कच्चे मकानों और 5 पक्के मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है, जिससे लगभग 15.07 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 4 डंग गिरे हैं, जिनमें लगभग 2.40 लाख रुपए की क्षति हुई है। 32 गोशालाओं के ध्वस्त होने से लगभग 8.85 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

बेकाबू ट्राले ने तीन वाहनों को मारी टक्कर बड़ा हादसा टला

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। पांवटा साहिब-कालाअंब राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह मोगीनंद के पास एक अनियंत्रित ट्राले ने एक के बाद एक तीन वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। टक्कर के बाद ट्राला चालक मौके से नहीं रुका। क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों ने पीछा कर कुछ दूरी पर ट्राले को पकड़ लिया। हादसा करीब साढ़े नौ बजे फोनिक्स उद्योग के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि ट्राला पांवटा साहिब से कालाअंब की ओर जा रहा था। टक्कर से एक स्कॉर्पियो का टायर तक फट गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर पहले भी ट्रालों के कारण हादसे हो चुके हैं। निर्माण कार्य के चलते सड़क किनारे रेत-बजरी के ढेर लगे होने से मार्ग संकरा हो गया है। वहीं, वाहन चालकों को सावधान करने के लिए पर्याप्त साइन बोर्ड और यातायात नियंत्रित करने वाले कर्मचारी भी तैनात नहीं हैं। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

मैकेनिक की आड़ में चिट्टा सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के एक मामले में आगे की कड़ी जोड़ते हुए मुख्य सप्लायर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी नरेश कुमार मनीमाजरा में मैकेनिक का काम करता था और इसी की आड़ में मादक पदार्थों की बिक्री और सप्लाई से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे 29 अगस्त को गिरफ्तार किया। अदालत से आरोपी का तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार 23 अगस्त को रामपुर बुशहर डिटेक्शन टीम ने सोफा कैंची किंगल के पास एक रिकवरी वैन की तलाशी ली थी। इस दौरान वाहन से 11.35 ग्राम चिट्टा या हेरोइन बरामद हुई। इस मामले में पुलिस थाना कुमारसेन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कुलदीप, ललित, विक्रम और संजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर चिट्टे की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पुलिस हिरासत के दौरान ललित कुमार से पूछताछ में सामने आया कि बरामद चिट्टा उसे और उसके साथियों को नरेश कुमार ने चंडीगढ़ के मनीमाजरा में उपलब्ध करवाया था। इसके बाद पुलिस ने नरेश कुमार की भूमिका और उससे जुड़े सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि मनीमाजरा निवासी नरेश कुमार (60) पेशे से मैकेनिक है और मैकेनिक के काम की आड़ में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री और सप्लाई में शामिल था। पूछताछ और जांच से मनीमाजरा में चिट्टे की खरीद और सप्लाई में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आने के बाद शिमला पुलिस की टीम ने चंडीगढ़ पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मादक पदार्थों की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।

11 सितंबर को एसएमआई हॉस्पिटल में आधुनिक मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसएमआई हॉस्पिटल द्वारा 11 सितंबर को विशेष मोतियाबिंद (सफेद मोतिया) ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मरीजों के ऑपरेशन फेको तकनीक से किए जाएंगे। यह बिना टांके की आधुनिक एवं सुरक्षित तकनीक है, जिससे मरीज को शीघ्र दृष्टि लाभ मिलने के साथ सामान्य जीवन में जल्दी लौटने में मदद मिलती है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार शिविर में मरीजों को रियायती पैकेज पर आधुनिक लेंस के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑपरेशन से पहले नेत्र विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की विस्तृत जांच कर उचित परामर्श भी दिया जाएगा। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप महाजन ने बताया कि मोतियाबिंद उम्र बढ़ने के साथ होने वाली सामान्य समस्या है। समय पर ऑपरेशन करवाने से दृष्टि को काफी सुधार संभव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी बुजुर्ग को धुंधला दिखाई देता है, रोशनी में परेशानी होती है या चश्मा बदलने के बाद भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो आंखों की जांच अवश्य करवाएं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि शिविर में सीमित संख्या में मरीजों का पंजीकरण किया जाएगा। इच्छुक मरीज अग्रिम पंजीकरण के लिए अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं।

दाढ़-चामुंडा रोड पर कूड़े के ढेर से राहगीर परेशान, कार्रवाई की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, दाढ़। दाढ़-चामुंडा मार्ग पर दुकानदारों और होटल संचालकों द्वारा सड़क किनारे कथित रूप से कूड़ा फेंके जाने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगने से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है और क्षेत्र में गंदगी का माहौल बना हुआ है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसपास के कुछ दुकानदारों और होटल संचालकों को कूड़ा न फेंकने के लिए कहने पर वे विवाद करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि यह मार्ग माता चामुंडा मंदिर की ओर जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और अन्य लोगों का आना-जाना लगा रहता है, ऐसे में सड़क किनारे फैली गंदगी से क्षेत्र की छवि भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पंचायत प्रधान को भी इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कूड़ा फेंकने का सिलसिला जारी है। समस्या को लेकर एसडीएम को भी लिखित शिकायत दी गई है। एसडीएम ने समस्या का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

तृप्ता पब्लिक स्कूल चलवाड़ा में विज्ञान प्रदर्शनी, नन्हे वैज्ञानिकों ने दिखाया हुनर

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। तृप्ता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलवाड़ा में भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा चौथी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और नवाचार का प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनी में एवरीडे साइंस, इनोवेशन इन साइंस, एआई एंड ह्यूमैनिटी, हेल्थ एंड साइंस, सेव आवर प्लैनेट तथा एनवायरनमेंट कंसर्न इत्यादि जैसे विषयों पर मॉडल प्रस्तुत किए गए। स्कूल के चेयरमैन वरिंद्र नरियाल और प्रधानाचार्य राकेश राणा ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में जीवन विज्ञान और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। विद्यार्थियों ने भविष्य की तकनीक और दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान पर आधारित कई वर्किंग मॉडल तैयार किए। मुख्य आकर्षण में एआई जनरेटर, ऑटोमैटिक वाटर डिस्पेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर ब्रेकिंग सिस्टम, स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम और सोलर कार शामिल रहे। स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से खेती में पानी की बचत, जबकि ऑटोमैटिक वाटर डिस्पेंसर से पानी की बर्बादी रोकने का संदेश दिया गया। अल्ट्रासोनिक सेंसर ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की आधुनिक तकनीक प्रदर्शित की गई। विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, भौतिकी और भूगोल से जुड़े विषयों को भी सरल मॉडलों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनमें डीएनए मॉडल, न्यूरॉन सेल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वॉटर फिल्ट्रेशन और लेयर्स ऑफ अर्थ प्रमुख रहे। प्रधानाचार्य राकेश राणा ने प्रत्येक स्टॉल का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनके मॉडलों से संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीक का है।

खो-खो में सरयांज ने जीता खिताब

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की के अंतर्गत राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भूमती में आयोजित अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न खेलों के मुकाबले करवाए गए। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

खो-खो के फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरयांज और एनपीएस धुंधन की टीमें आमने-सामने रहीं। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरयांज की टीम ने जीत हासिल कर खो-खो का खिताब अपने नाम किया। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बथालंग का सामना मेजबान राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भूमती से होगा। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में मांगल और अर्की की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों मुकाबलों के विजेता फाइनल में प्रवेश करेंगे। इससे पहले कबड्डी में अर्की ने मांजू को, जबकि बथालंग ने कुनिहार को हराया था। वॉलीबाल के पहले सेमीफाइनल में आरआरसीएस शमलोह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुघार को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नवगांव और घणागुघाट के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें घणागुघाट की टीम विजयी रही। अब वॉलीबॉल के फाइनल मुकाबले में आरआरसीएस शमलोह और घणागुघाट की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। बैडमिंटन के सेमीफाइनल मुकाबलों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमैहर का मुकाबला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धुन्दन से तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलेरा का मुकाबला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की से होगा। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

बेरल पंचायत में विकास की नई पहल, उपरला स्कोर गांव के लिए सड़क निर्माण का कार्य शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की की दूरदराज पंचायत बेरल के उपरला स्कोर गांव के ग्रामीणों के लिए रविवार का दिन लंबे समय से चली आ रही सड़क सुविधा की मांग पूरी होने की दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आया।

विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों एवं अनुशंसा से गांव तक सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय पंचायत के उपप्रधान जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरला स्कोर गांव के लिए रविवार से सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी वर्षों पुरानी परेशानी का समाधान होगा। सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान जोगिंद्र शर्मा, वार्ड सदस्य सरला देवी, पूर्व वार्ड सदस्य जयंती देवी सहित सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे तथा सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई।

जगदीश शर्मा ने बताया कि सड़क सुविधा न होने के कारण उपरला स्कोर के ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए करीब ढाई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता था। ऐसे में गांव तक सड़क पहुंचना उनके लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि उपरला स्कोर गांव तक सड़क पहुंचने का उन्हें लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था, जो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए विधायक संजय अवस्थी का आभार जताया और उम्मीद जताई कि सड़क का कार्य जल्द पूरा होने से गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

बिलासपुर कॉलेज की व्यवस्थाओं की निरीक्षण समिति ने की सराहना

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने 29 और 31 जुलाई को महाविद्यालय के सभी 26 विभागों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सत्र 2026-27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की संबद्धता (एफिलिएशन) के लिए किया गया। प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने बताया कि समिति ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, कक्षाओं, शिक्षण व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों का जायजा लिया। समिति में विश्वविद्यालय के वीसी नामित प्रो. कुलभूषण चंदेल तथा सरकार के नामित प्रतिनिधि एवं राजकीय महाविद्यालय जुखाला के प्राचार्य डॉ. एचएल शर्मा सहित सदस्य शामिल रहे। निरीक्षण के बाद प्रो. चंदेल ने महाविद्यालय की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, डिजिटल सुविधाओं और स्मार्ट क्लासरूम की सराहना की। उन्होंने बीवोक कार्यक्रम के व्यावसायिक एवं रोजगारपरक संचालन को भी प्रदेश में बेहतर बताया। दोनों परिसरों को छत से जोड़ने की व्यवस्था को भी उपयोगी पहल बताया।

अभियान | डीसी बिलासपुर की महत्वाकांक्षी पहल मिशन दृष्टि बिलासपुर' का विधिवत आगाज

3 से 8 वर्ष के बच्चों की आंखों की होगी स्क्रीनिंग

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान व उचित उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की महत्वाकांक्षी पहल 'मिशन दृष्टि बिलासपुर' का राजकीय प्राथमिक पाठशाला रौड़ा में विधिवत शुभारंभ किया गया।

अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर रुपिंदर कौर ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला रौड़ा और संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के कुल 50 बच्चों की आंखों की जांच की गई। इनमें आंगनबाड़ी केंद्र के 12 बच्चों की स्क्रीनिंग में किसी भी बच्चे में दृष्टि संबंधी दोष नहीं पाया गया, जबकि प्राथमिक पाठशाला के 38 बच्चों की जांच में 2 बच्चों में दृष्टि संबंधी दोष सामने आए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कम उम्र में बच्चों की आंखों में होने वाली दृष्टि संबंधी समस्या की समय पर पहचान न होने से इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, सीखने की क्षमता और समग्र विकास पर पड़ सकता है। छोटे बच्चे अक्सर अपनी दृष्टि संबंधी परेशानी को स्वयं पहचान या स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते। ऐसे में नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से आंखों की समस्या का शुरुआती स्तर पर पता लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। समय रहते समस्या की पहचान होने पर आवश्यक उपचार और चश्मे के माध्यम से बच्चे की दृष्टि को बेहतर किया जा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि 'मिशन दृष्टि बिलासपुर' के तहत 1 सितंबर 2026 से जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों की आंखों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की आंखों की समय पर जांच कर दृष्टि संबंधी कमियों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान करना और आवश्यकता के अनुसार उन्हें उचित उपचार उपलब्ध करवाना है, ताकि आंखों की समस्या उनकी पढ़ाई और भविष्य में बाधा न बने।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी शशि दत्त शर्मा ने बताया कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। सबसे पहले बच्चों का स्नेलन चार्ट के माध्यम से विजन टेस्ट किया जाएगा। यदि प्रारंभिक जांच में दृष्टि संबंधी दोष पाया जाता है, तो बच्चे की आगे की जांच ऑटो-रिफ्रैक्टर मशीन के माध्यम से की जाएगी। इस उपकरण से बच्चे की आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर तथा चश्मे के संभावित नंबर का आकलन किया जाएगा। अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों को इसमें शामिल किया गया है। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में की टीमें कार्यरत हैं। कई ब्लॉकों में दो-दो टीमें हैं, जबकि नैना देवी ब्लॉक में एक टीम उपलब्ध है। ये टीमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सदर ब्लॉक की आरबीएसके टीम को ऑटो-रिफ्रैक्टर मशीन के संचालन के लिए पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। टीम को मशीन के उपयोग और स्क्रीनिंग प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अन्य ब्लॉकों की टीमों को भी मशीन उपलब्ध करवाने से पहले आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी ढंग से की जा सके।

43 दिनों में 23 पंचायतों और धर्मशाला के चार वार्डों तक पहुंचा स्वराज सत्याग्रह

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहपुर। पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, सामाजिक सौहार्द एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के उद्देश्य से लोकतांत्रिक राष्ट्रनिर्माण अभियान के तत्वावधान में स्वराज सत्याग्रह यात्रा जारी है। स्वराज सत्याग्रही एवं पर्यावरण-लोकतंत्र प्रेमी डॉ. अशोक कुमार सोमल के नेतृत्व में यह पैदल यात्रा 20 जुलाई 2026 को उनके गांव जुनाट से शुरू हुई।

यात्रा के दौरान लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से संवाद किया गया व जागरूकता संबंधी पर्चे वितरित किए गए। फतेहपुर के एसडीएम को पर्चा सौंपकर विशेष रूप से पॉलीथिन प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की गई। एसडीएम के माध्यम से डॉ. सोमल ने छह अन्य साथियों के साथ जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में चल रहे जेन-जी आंदोलनकारियों के समर्थन में राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। पिछले 43 दिनों में यात्रा के तहत फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की 23 पंचायतों तथा धर्मशाला नगर निगम के चार वार्डों में करीब 1000 से 1200 लोगों से संवाद किया गया। इस दौरान लगभग 50 किलोमीटर पैदल यात्रा की गई। धर्मशाला में शीलाचौक से धर्मशाला और धर्मशाला से सकोह तक करीब 12 किलोमीटर की पदयात्रा भी की गई।

'मेरा कचरा, मेरी जिम्मेदारी' का संदेश लेकर लोगों के बीच पहुंचे डॉ. अशोक सोमल

इस दौरान पत्रकारों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर अभियान का संदेश साझा किया गया। डॉ. सोमल ने कहा कि लोगों को वायु एवं जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में घटती पौष्टिकता, बढ़ती मिलावट और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक होना होगा। उन्होंने 'मेरा कचरा, मेरी जिम्मेदारी' का संदेश देते हुए कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट बनाने के लिए नागरिकों को भी स्मार्ट और जिम्मेदार बनना होगा। उन्होंने लोगों से देश-दुनिया की बेहतरी के लिए 'दस-बीस कदम हमारे साथ चलने' का आह्वान किया।

'यूजिनी बोशार्ड' खूबसूरत अदा में

यूजिनी बोशार्ड का जन्म 25 फरवरी 1994 को कनाडा में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस में गहरी रुचि थी और उन्होंने कम उम्र में ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। 2012 में उन्होंने विंबलडन जूनियर खिताब जीता।

स्पोर्ट्स विंडो

शूटिंग से अनजान थीं मनीषा, अब एशियन गेम्स में पदक का सपना

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय ट्रैप शूटर मनीषा कीर की कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और सफलता की मिसाल है। भोपाल के पास

एक गांव में पली-बढ़ी मनीषा को कभी पता तक नहीं था कि शूटिंग भी कोई खेल है। उनकी बड़ी बहन सोना ने उन्हें इस खेल से परिचित कराया और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद मनीषा ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें खर्च बचाने के लिए कई बार अपनी पसंद का खाना तक छोड़ना पड़ा। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में सीमित सुविधाओं और नियमित कोच की कमी के बावजूद उन्होंने उपलब्ध संसाधनों से प्रशिक्षण जारी रखा। मनीषा ने 2018 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ट्रैप स्पर्धा का रजत पदक जीता। इसके अलावा एशियन गेम्स में भारतीय महिला ट्रैप टीम के साथ भी रजत पदक हासिल किया। अब उनकी नजर एशियन गेम्स में देश के लिए एक और पदक जीतने पर है। मनीषा ने अपनी यात्रा में एनआरएआई के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया।

आर्सेनल, बार्सिलोना और रोमा की जीत, फुटबॉल लीग में दिखा दम

एजेंसी, लंदन। आर्सेनल ने एस्टन विला को 1-0 से हराकर प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा, जबकि बार्सिलोना और रोमा ने क्रमशः स्पेन और

इटली में शानदार जीत दर्ज की। मौजूदा चैंपियन आर्सेनल ने बुकायो साका के 59वें मिनट में किए गए गोल के दम पर तीन अंक हासिल किए। उधर ला लिगा में लामिन यामल और राफिन्हा दोनों ने दो-दो गोल किए जिससे बार्सिलोना ने रायो वैलेकानो को 5-2 से हराकर अपने घरेलू मैदान पर लगातार 21वीं जीत दर्ज की। इस जीत से बार्सिलोना ने अंतर के आधार पर रियाल मैड्रिड से आगे निकलकर लीग तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। इटली की लीग सीरी ए में डोनेल मालेन ने दो गोल किए जिससे रोमा ने लेचे के खिलाफ 4-0 से जीत हासिल की। मालेन ने रोमा की फियोरेंटीना के खिलाफ शुरुआती मैच में जीत में हैट्रिक लगाई थी।

स्टेन वावरिंका का ग्रैंड स्लैम करियर हार के साथ हुआ समाप्त

एजेंसी, न्यूयॉर्क। यूएस ओपन 2016 के चैंपियन स्टेन वावरिंका का ग्रैंड स्लैम करियर सोमवार को पहले दौर में मैटियो बेरेटिनी

से हार के साथ समाप्त हो गया। 41 वर्षीय स्विस खिलाड़ी को बेरेटिनी से 7-6 (4), 7-6 (3), 6-0 से हराया। वावरिंका ने 10 साल पहले इसी टूर्नामेंट के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह उनका आखिरी सत्र होगा। इस बार उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए यूएस ओपन में प्रवेश मिला था। हार के बाद वावरिंका ने कहा कि उन्हें टेनिस और इस खेल से जुड़ी यादों की बहुत कमी खलेगी। अमेरिकी टेनिस संघ (यूएसटीए) के अधिकारियों ने उन्हें कोर्ट पर सम्मानित भी किया। वावरिंका ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के खिताब भी जीते। उनकी सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग तीसरी रही। उन्होंने यूएस ओपन में 18वीं बार हिस्सा लिया।

शार्दुल ठाकुर की जगह सिद्धेश लाड बने मुंबई के रणजी कप्तान

एजेंसी, मुंबई। मध्यक्रम के अनुभवी बल्लेबाज सिद्धेश लाड को आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए शार्दुल ठाकुर की जगह मुंबई का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठाकुर को कार्यभार प्रबंधन के तहत इस पद से हटाया गया। ठाकुर ने 2025-26 सत्र के लिए

अजिंक्य रहाणे की जगह मुंबई की कमानी संभाली थी, जिसमें 42 बार की रणजी ट्रॉफी विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई थी। रणजी सत्र की शुरुआत 11 अक्टूबर को होगी और मुंबई की टीम अपने पहले मैच में चंडीगढ़ से भिड़ेगी। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के एक शीर्ष अधिकारी ने लाड की नियुक्ति की पुष्टि की है। 34 वर्षीय लाड बीच में मुंबई को छोड़कर गोवा चले गए थे। उन्होंने एक साल की 'कूल ऑफ' अवधि पूरी करने के बाद 2024-25 में मुंबई की टीम में वापसी की थी। पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में उन्होंने आठ मैचों में 77.40 की औसत से 774 रन बनाए, जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल है।

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन का दबदबा, सेंट्रल जोन 158 रन पर ढेर

मोहम्मद शम्मी ने झटके 3 विकेट, अमन मोखाड़े 41 रन के साथ रहे सेंट्रल जोन के शीर्ष स्कोरर

एजेंसी, नई दिल्ली

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी की उपकप्तानी वाली ईस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को दूसरी पारी में 158 रन पर ऑलआउट कर दिया। सेंट्रल जोन के लिए अमन मोखाड़े ने 41 रन की सबसे बड़ी पारी खेली, जबकि अरशद खान ने 25 और हर्ष दुबे ने 24 रन बनाए। ईस्ट जोन की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए।

सेंट्रल जोन की शुरुआत खराब रही और 37 रन तक टीम के तीन विकेट गिर गए। कप्तान रजत पाटीदार 5 और रिंकू सिंह 20 रन ही बना सके। 95 रन तक 7 विकेट गंवाने के बाद अरशद खान ने लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया, लेकिन 25 रन पर उनके आउट होते ही सेंट्रल जोन की पारी 158 रन पर सिमट गई। ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 12 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 3, जबकि अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और कुनैन कुरैशी ने 1-1 विकेट लिया।

मोहम्मद शम्मी ने पूरे किए 900 विकेट

मोहम्मद शम्मी ने दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहले दिन बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे शमी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ 3 विकेट लेकर प्रोफेशनल क्रिकेट में अपने 900 विकेट पूरे किए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ छठे भारतीय गेंदबाज बने। शमी ने 36 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल किया।

ईस्ट जोन से पहली पारी में सूर्यवंशी का अर्धशतक

सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन की पहली पारी बराबरी पर रही। दोनों टीमों ने 266 रन बनाए। ईस्ट जोन के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 92 और अभिमन्यु ईश्वरन ने 69 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 161 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद ईस्ट जोन ने अगले 104 रन में अपने सभी विकेट गंवा दिए। सेंट्रल जोन की ओर से हर्ष दुबे ने 4, जबकि आर्यन पांडे और यश ठाकुर ने 3-3 विकेट लिए।

यूएस ओपन: इगा स्वियातेक ने शियू को हराकर दूसरे दौर में बनाई जगह

एजेंसी, न्यूयॉर्क

पोलिश स्टार ने सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया

पोलैंड की आठवीं वरीयता प्राप्त और 2022 की चैंपियन इगा स्वियातेक ने यूएस ओपन 2026 में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। स्वियातेक ने चीन की वांग शियू को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। लुई आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला 88 मिनट तक चला।

स्वियातेक ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पहले सेट में 3-1 की बढ़त हासिल की। इसके बाद उन्होंने एक और सर्विस ब्रेक हासिल कर सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी पोलिश खिलाड़ी ने वांग पर लगातार दबाव बनाए रखा। आठवें गेम में सर्विस ब्रेक के बाद उन्होंने मुकाबला आसानी से समाप्त कर दिया।

मैच के बाद स्वियातेक ने कहा कि उन्हें शुरुआत से ही कोर्ट पर अच्छा महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, 'मेरे अंदर ऊर्जा और तीव्रता थी और मैं इसे आगे भी बनाए रखना चाहती हूं।' उन्होंने बताया कि वांग के गहरे और टॉपस्पिन वाले

अब नादिया पोडोरोस्का से होगा मुकाबला

शॉट्स का सामना करने के लिए उन्हें अपनी ताकत का प्रभावी इस्तेमाल करना पड़ा। स्वियातेक हालिया टूर्नामेंटों में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने टोरंटो ओपन का खिताब जीता था, जबकि सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंची थीं। अब उनकी नजर सातवें ग्रैंड स्लैम खिताब पर है।

दूसरे दौर में उनका सामना नादिया पोडोरोस्का से होगा। वहीं, अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा ने एशलिन क्रूगर को 6-1, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका सामना ऑस्ट्रिया की लिली टैगर से होगा।

ब्रावो-पोलार्ड-नरेन के नाम हुआ क्वीन पार्क ओवल का स्टैंड

टी20 क्रिकेट में ऐतिहासिक योगदान के लिए त्रिनिदाद एवं टोबैगो के 3 दिग्गजों को मिला सम्मान

एजेंसी, पोर्ट ऑफ स्पेन

त्रिनिदाद एवं टोबैगो के तीन महान आधुनिक क्रिकेटरों ड्वेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन को उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए खास सम्मान दिया गया है। ऐतिहासिक क्वीन पार्क ओवल में उनके सम्मान में एक स्टैंड का नाम बदलकर 'ब्रावो, पोलार्ड एंड नरेन स्टैंड' कर दिया गया है।

क्वीन पार्क क्रिकेट क्लब (क्यूपीसीसी) ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो के 64वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोमवार को इस नए नाम वाले स्टैंड का अनावरण किया। इससे पहले यह स्टैंड 'ट्रिनी पॉस स्टैंड' के नाम से जाना जाता था। यह सम्मान तीनों खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में योगदान के साथ-साथ टी20 क्रिकेट के वैश्विक विकास में उनकी भूमिका को समर्पित है। तीनों खिलाड़ी त्रिनिदाद एवं टोबैगो क्रिकेट की पहचान और दुनिया भर में कैरेबियाई टी20 क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव के प्रमुख चेहरों में रहे हैं।

क्वीन पार्क ओवल में अब इन तीनों के नाम के साथ त्रिनिदाद एवं टोबैगो के कई दिग्गजों की विरासत भी जुड़ गई है।

एक ही टीम से फिर जुड़े तीनों दिग्गज

तीनों दिग्गज इस समय त्रिनिदाद एवं टोबैगो में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के 2026 कैरेबियन प्रीमियर लीग अभियान का हिस्सा हैं। पोलार्ड और नरेन टीम के लिए मैदान पर खेल रहे हैं, जबकि ब्रावो टीम के कोचिंग स्टाफ से जुड़े हैं। क्वीन पार्क क्रिकेट क्लब ने कहा कि स्टैंड का नामकरण केवल खिलाड़ियों के आंकड़ों और खिताबों का सम्मान नहीं है, बल्कि यह त्रिनिदाद एवं टोबैगो से निकलकर विश्व क्रिकेट के शीर्ष स्तर तक पहुंचने की उनकी यात्रा और नई पीढ़ी के क्रिकेटरों को दी गई प्रेरणा का भी सम्मान है।

स्टेडियम में ब्रायन लारा पवेलियन, डेरिक मरे प्लेयर्स गैलरी, जेफ्री स्टॉलमेयर स्टैंड, लियरी कॉन्स्टेंटाइन स्टैंड, गेरी गोमेज मीडिया सेंटर और सिरिल एल. ड्यूप्रे स्टैंड भी हैं। कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी हैं। वह 700 से अधिक टी20 मैच खेल चुके हैं और उनके नाम 14,000 से अधिक रन तथा 330 से ज्यादा विकेट हैं।

ड्वेन ब्रावो टी20 क्रिकेट के सबसे सफल ऑलराउंडरों में शामिल रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में 631 टी20 विकेट लिए, जो उनके संन्यास के समय पुरुष टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक थे। उनके नाम करीब 7,000 रन भी हैं। वहीं सुनील नरेन हाल ही में टी20 क्रिकेट में 650 विकेट पूरे करने वाले इतिहास के केवल दूसरे गेंदबाज बने। वह कैरेबियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। तीनों खिलाड़ियों ने इंडियन प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग और दुनिया की अन्य प्रमुख टी20 लीग में कई खिताब जीते हैं और अपनी अलग पहचान बनाई है।

मिशेल मार्श व हेड की ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में वापसी, लाबुशेन बाहर

एजेंसी, सिडनी

कप्तान मिशेल मार्श और उनके साथी सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड को इस महीने के आखिर में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है जबकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है।

मार्श और हेड इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान और बांग्लादेश में वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए 15 सितंबर से शुरू होने वाला यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में वनडे विश्व कप खेला जाएगा।

तेज गेंदबाज पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क को जोड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज में नहीं खेल पाएगी और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल होगी। युवा खिलाड़ी जोएल डेविस और ओली पीक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम में अपनी जगह बनाए रखी है।

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे मैच 15, 18 और 20 सितंबर को हरारे में खेले जाएंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज डरबन (24 सितंबर), जोहान्सबर्ग (27 सितंबर) और पोटचेफस्ट्रूम (30 सितंबर) में खेली जाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैच खेलेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा कि यह छह मैचों की

संभावित टीम

मिशेल मार्श, पैट कमिंस (केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनोली, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिशेल स्टार्क (केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए), एडम जम्पा।

श्रृंखला अगले साल होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। इसलिए मिच (मार्श), ट्रैविस और जोश (हेजलवुड) का वापसी करना बहुत अच्छा है।

प्याज की महंगाई से नेपाल परेशान 140 रुपए प्रति किलो पहुंचा खुदरा भाव

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत में प्याज की बढ़ती कीमतों का असर पड़ोसी देश नेपाल के बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। नेपाल में प्याज के खुदरा दाम बढ़कर करीब 140 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। नेपाली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, एक सप्ताह पहले प्याज लगभग 100 रुपये किलो बिक रहा था। वहीं, कालीमाटी फल एवं सब्जी मंडी में प्याज के थोक भाव में भी लगातार तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक सप्ताह में थोक कीमत करीब 20.77 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि एक महीने में इसमें 68.65 प्रतिशत और एक साल में लगभग 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रविवार को कालीमाटी थोक मंडी में प्याज का भाव 93.6 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

नेपाल के बाजार में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह भारत से होने वाली आपूर्ति में बदलाव को माना जा रहा है। नेपाल अपनी प्याज की जरूरत का बड़ा हिस्सा भारत से आयात करके पूरा करता है। भारत में कीमत बढ़ने का सीधा असर नेपाली बाजार पर पड़ता है।

इसके अलावा हाल में आई बाढ़ के कारण सड़क मार्ग प्रभावित होने से प्याज की आपूर्ति भी बाधित हुई है। नासिक से प्याज भैरहवा व्यापार केंद्र के रास्ते नेपाल पहुंचता है और इसके बाद पृथ्वी राजमार्ग से काठमांडू समेत अन्य बाजारों में भेजा जाता है। पिछले कुछ दिनों से राजमार्ग पूरी तरह सामान्य नहीं होने के कारण परिवहन और आपूर्ति दोनों प्रभावित हुए हैं। कालीमाटी फल एवं सब्जी बाजार विकास बोर्ड के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में मंडी में प्रतिदिन करीब 70 से 100 टन प्याज की आपूर्ति होती है। आपूर्ति में कमी आने और परिवहन लागत बढ़ने से बाजार पर अतिरिक्त दबाव बना है। आयातकों का कहना है कि महज दो सप्ताह में उनकी लागत लगभग दोगुनी हो गई है। इसका असर अंततः खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

सोना 1,037 और चांदी 1,711 रुपए सस्ती

एजेंसी, मुंबई। पीएम मोदी की अपील के बीच मंगलवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,037 रुपये सस्ता होकर 1,54,798 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत में 1,711 रुपये की कमी आई और यह 2,35,488 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। कीमती धातुओं में इस गिरावट के पीछे केवल घरेलू कारक ही जिम्मेदार नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने पर दबाव बना हुआ है।

पीएम मोदी की अपील के बाद सोने-चांदी की कीमतों में आई नरमी

अमेरिका में सरकारी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख ने निवेशकों की धारणा प्रभावित की है। वैश्विक बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत एक प्रतिशत से अधिक नीचे आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में लोगों से जरूरत नहीं होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील की है। इसका असर बाजार की धारणा पर भी देखने को मिला और आभूषण कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

2030 तक 30 अरब डॉलर होगा भारत-ब्राजील व्यापार

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। ब्रासीलिया में भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की आठवीं बैठक में दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15.07 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

अब फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बैठक में भारतीय दवा उत्पादों के लिए बाजार पहुंच आसान बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को अधिक स्थिर करने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। कृषि क्षेत्र में पौध स्वच्छता संबंधी मुद्दों के समाधान और पारस्परिक बाजार पहुंच बढ़ाने की दिशा में तकनीकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

दोनों देशों ने भारत-मर्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार और आधुनिकीकरण की संभावनाओं की समीक्षा की। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाएं, लॉजिस्टिक्स और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर जोर दिया गया।

जीएसटी संग्रह अगस्त में 14.8 प्रतिशत बढ़कर 1,99,853 करोड़

एजेंसी, नई दिल्ली

अगस्त 2026 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 1,74,116 करोड़ रुपये था। इस वृद्धि में घरेलू बाजार और आयात से प्राप्त राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगस्त में घरेलू जीएसटी संग्रह 9.3 प्रतिशत बढ़कर 1,37,249 करोड़ रुपये रहा, जबकि आयात पर जीएसटी राजस्व में 29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान निर्यात से सरकार को 62,604 करोड़ रुपये की जीएसटी प्राप्ति हुई।

सरकार ने अगस्त में 31,795 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड भी जारी किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 67.9 प्रतिशत अधिक है। रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.3 प्रतिशत बढ़कर

1,68,057 करोड़ रुपये हो गया। घरेलू जीएसटी से प्राप्त शुद्ध राजस्व 3.4 प्रतिशत बढ़कर 1,18,759 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों में भी जीएसटी संग्रह में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। इस अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 10,42,757 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के बाद शुद्ध संग्रह 8,89,523 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। लगातार बढ़ता जीएसटी संग्रह अर्थव्यवस्था में कारोबारी गतिविधियों और कर अनुपालन में सुधार का संकेत देता है। हालांकि रिफंड में तेज वृद्धि भी हुई है, फिर भी शुद्ध राजस्व में वृद्धि सरकार के लिए सकारात्मक संकेत है।

बाजार

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद

सेंसेक्स 13 अंक गिरकर 76,944 पर बंद

एजेंसी, मुंबई

मंगलवार को विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में पूरे दिन दबाव बना रहा। कारोबार के दौरान कई बार बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंत में दोनों प्रमुख सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 12.99 अंक यानी 0.02 प्रतिशत फिसलकर 76,944.28 अंक पर पहुंच गया। वहीं एनएसई का निफ्टी 24.60 अंक यानी 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,055.80 अंक पर बंद हुआ। हालांकि आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार को कुछ सहारा मिला और प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट नहीं आई। इसके विपरीत

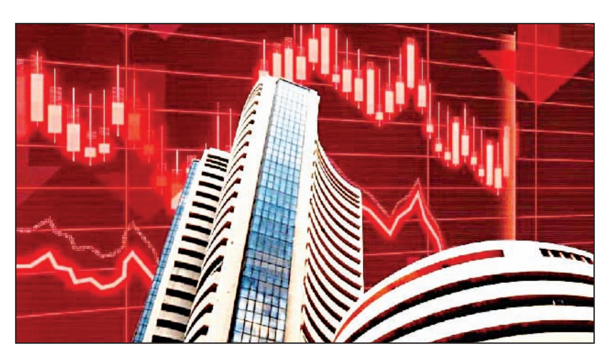

व्यापक बाजार में बिकवाली का दबाव अधिक देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप-50 में 1.31 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप-100 भी 0.23 प्रतिशत कमजोर रहा।

वैश्विक बाजारों में जारी कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया। जापान समेत कई देशों में सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला प्रतिफल बढ़ने से निवेशकों की चिंता बढ़ी है। इससे शेयर बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई और निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी।

निफ्टी 24 अंक टूटकर 24,056 पर हुआ बंद

मारुति सुजुकी चार प्रतिशत तक टूटा

सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में मारुति सुजुकी का शेयर करीब चार प्रतिशत टूट गया, जिससे वाहन क्षेत्र पर दबाव स्पष्ट हुआ। भारतीय स्टेट बैंक के शेयर में भी दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही। इंडिगो, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर दो से ढाई प्रतिशत तक कमजोर हुए। एक्सिस बैंक, टाइटन, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट में भी एक से दो प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल और अडाणी पोर्ट्स के शेयर भी नुकसान में बंद हुए। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में वैश्विक संकेत, बॉन्ड प्रतिफल और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।